www.indiatodayhindi.in

किसान आंदोलन से बढ़ी भाजपा की चुनौती

हेल्थगीरी: विजेताओं की सूची

अमरिंदर सिंह: कैप्टन के विकल्प

20 अक्तूबर, 2021 50 रुपए

इंडिया टुडे

हेरोइन: नशे की गिरफ्त

गोल्डन क्रेसेंट के फिर से सक्रिय होने के साथ ही भारत बना प्रमुख बाजार, जिसकी वजह से देश में युवा नशेड़ियों की तादाद में जबरदस्त इजाफा

RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22

अग्रिम सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 66 (आवरण सहित)

OC

VISIT…

प्रधान संपादक की कलम से

पिछले हफ्ते भारत के पश्चिम समुद्रतट पर 500 किमी के फासले से नशीले पदार्थों पर दो छापों से हमें पता चला कि देश में नारकोटिक्स की समस्या कितनी बड़ी है. राजस्व गुप्तचर निदेशालय ने 15 सितंबर को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर नशीले पदार्थों की भारत की सबसे बड़ी खेपों में से एक पकड़ी—करीब 15,000 करोड़ रुपए की 3 टन अफगान हेरोइन. एक पखवाड़े बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई में पार्टियां मनाने वाले कुछ लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन के लिए गिरफ्तार किया. इनमें एक प्रमुख फिल्मी सितारे का बेटा भी था.

भारत में ड्रग की समस्या लंबे वक्त से है. अब लगता है यह बढ़ रही है. पहले देश नारकोटिक्स को एक से दूसरे जहाज में चढ़ाने का रास्ता हुआ करता है. अब खपत की अहम जगह बन गया है. माना जाता है कि करीब 5 करोड़ हिंदुस्तानी ड्रग लेते हैं. महामारी में तनाव बढ़ने से इनका सेवन बढ़ा ही हो सकता है. नशे की आदत अपराध और परिवारों में टूट-फूट को हवा दे रही है और देश के सामाजिक तानेबाने पर असर डाल रही है. यही नहीं, ड्रग पर निर्भरता मानसिक-सामाजिक-चिकित्सा समस्या भी है, जो हादसों, हिंसा और खुदकुशी की तरफ ले जा सकती है.

नशे का सेवन सामाजिक लांछन नहीं रह गया, यह चिंता की बात है. एनसीबी के डायरेक्ट जनरल एस.एन. प्रधान ने हमसे कहा, ''शराब पीना नई बात नहीं रही. आप फैशनेबल और 'नए चलन के' हैं, तो आपको ड्रग लेने चाहिए.''

इस बीच जबरदस्त इलाकाई बदलावों ने इस कारोबार की चाल-ढाल बदल दी है. अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी सबसे मनहूस घटना है. यह झुंड नशे के कारोबार से मुनाफा कमाने के लिए जाना जाता है. दुनिया की 80 फीसद से ज्यादा अवैध अफीम अफगानिस्तान में उगती है. इससे हेरोइन बनाई और दुनिया भर में भेजी जाती है. नाजुक माली हालत और आमदनी के सीमित स्रोतों को देखते हुए तालिबान अपने देश को नशीले पदार्थों की नार्को-स्टेट में बदल सकता है. यह भारत के लिए अच्छा शगुन नहीं है, खासकर जब यहां नौजवानों की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है और हेरोइन की लत बढ़ रही है. अफगानिस्तान से तस्करी करके पाकिस्तान होकर भारत लाई जाने वाली नशीले पदार्थों की मात्रा बीते दो सालों में बढ़ी है. सीमा सुरक्षा बल ने पिछले साल 507 किलो अकेले पंजाब से बरामद की, जो 2018 और 2019 में कुल बरामद ड्रग से ज्यादा था. मुंद्रा में पकड़ी गई खेप बताती है कि ऐसी बरामदगियां इस गोरखधंधे का सिरा भर हैं.

30 सितंबर, 2020 का आवरण

कुछ मोटा-मोटी अनुमान भर हैं कि भारत में नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार कितना बड़ा है. हमारी सरकारी एजेंसियां इसे करीब 30,000 करोड़ रुपए का (साल भर में जब्त 3,000 करोड़ रुपए की ड्रग और उनके कुल ड्रग का 10 फीसद होने के आधार पर) आंकती हैं. फिर भी यह ड्रग कार्टेल के लिए इतना मुनाफेदार है कि इसमें निवेश करते और जोखिम उठाते रहें. अपने खेल को और ऊंचा उठाते हुए सरगना अब अपना साम्राज्य कहीं दूर बैठकर छुटभैयों के नेटवर्क के जरिए चलाते हैं, पैसों का लेन-देन डार्कनेट पर करते हैं और नशेड़ियों तक अवैध माल कूरियर से पहुंचाते हैं.

हमारे यहां करीब 60 करोड़ या आबादी के तकरीबन आधे लोग 25 साल से कम उम्र के हैं, जो तस्करों को बंधा-बंधाया बाजार मुहैया करते हैं. नशीले पदार्थों का सेवन सामान्य बात होना और युवाओं में ड्रग आजमाने की बढ़ती उत्सुकता आबादी के इस हिस्से की लाचारगी बढ़ा देती है.

दक्षिण अमेरिका से निर्यात करके समुद्री और हवाई रास्तों से तस्करी के जरिए भारत लाई जा रही कोकीन देश के नामी-गिरामी लोगों की पंसदीदा ड्रग बनी हुई है. भारत में कोकीन के करीब 10 लाख तलबगार एक ग्राम के लिए 5,000 रुपए या उससे ज्यादा चुकाना गवारा कर सकते हैं.

गरीब भी इतने ही लाचार हैं. माना जाता है कि भारत में नशीले पदार्थों के आधे से ज्यादा उपभोक्ता गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों से आते हैं, जो स्मैक से लेकर ब्राउन शुगर तक तमाम सस्ती ड्रग लेते हैं. ज्यादा चिंताजनक यह कि मादक पदार्थों की आसान उपलब्धता से बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं. एनडीपीएस कानून के तहत दर्ज किशोर उम्र से जुड़े मामलों में सालाना 21 फीसद का इजाफा हुआ. ये 2010 में 82 और 2015 में 123 से बढ़कर 2020 में 264 हो गए.

हमने दिल्ली के बीचोबीच बने जिस ड्रग पुनर्वास केंद्र का दौरा किया, वहां 10 साल जितने छोटे बच्चों का इलाज किया जा रहा था. वे और भी कम उम्र में लती बन गए होंगे.

लिहाजा यह बेहद जरूरी है कि ड्रग के खतरे से लड़ने वाले सरकारी तंत्र का कायापलट किया जाए. तमाम ड्रग विरोधी अभियान तीन स्तंभों पर टिके होते हैं—ड्रग की आपूर्ति में कमी या आपूर्ति में बाधा डालना, मांग में कमी या कोशिश करना कि लोग ड्रग लेना ही न चाहें, और नुक्सान कम करना या नशेड़ियों का पुनर्वास और बहाली. हमारे यहां एनसीबी सरीखी केंद्रीय एजेंसी है, लेकिन इसे यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी सरीखे दुनिया भर में मौजूद संगठनों की तर्ज पर ज्यादा असरदार बनाने की जरूरत है. टेक्नोलॉजी और ड्रग से जुड़ी खुफिया जानकारियां जुटाने और उनका विश्लेषण करने को प्राथमिकता देने की जरूरत है. नारकोटिक्स विरोधी अभियान हमारी राजकाज की बहसों का प्रमुख हिस्सा होने चाहिए. अगस्त 2020 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नशीले पदार्थों की सबसे ज्यादा खपत वाले 272 जिलों को लक्ष्य करके 'ड्रग मुक्त भारत' अभियान चलाया था. यह अभियान महिलाओं और बच्चों सहित 1.2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का दावा करता है. हमें ऐसी कई और पहल की जरूरत है.

हमें एनडीपीएस कानून के कुछ निश्चित प्रावधानों की भी जांच करने की जरूरत है. यह कानून उपभोक्ता, स्ट्रीट पेडलर और बड़े ड्रग डीलर के बीच कम ही फर्क करता है. सरकार की क्षमताएं और संसाधन चूंकि सीमित हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह अपनी प्राथमिकता तय करे और पेडलरों पर ऊर्जा जाया करने के बजाए बड़ी मछलियों को पकड़े.

सरकार को भांग सरीखी आम तौर पर ली जाने वाली ड्रग को कानूनी बनाने पर विचार करना चाहिए. सरकारें इससे राजस्व कमा सकती हैं, जैसे वे तंबाकू और शराब से कमाती हैं. इससे प्रवर्तन एजेंसियां हेरोइन और कोकीन सरीखे अहम खतरों पर ध्यान दे पाएंगी.

हमारी आवरण कथा 'हेरोइन: नशे की गिरफ्त' पड़ताल करती है कि नए नारकोटिक्स के खतरों ने हाल के महीनों में कैसे नया रूप धारण कर लिया है. इसे मैनेजिंग एडिटर संदीप उन्नीथन ने लिखा है. डिप्टी एडिटर कौशिक डेका मादक पदार्थों के खिलाफ असम की जंग का जायजा ले रहे हैं और सीनियर एसोसिएट एडिटर किरण डी. तारे मुंबई में ड्रग के चिंताजनक परिदृश्य पर नजर डाल रहे हैं. इससे पहले कि यह हाथ से बाहर निकल जाए, ड्रग के खतरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बिल्कुल साफ जरूरत है.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर, आशीष मिश्र (लखनऊ)
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरो:, अभिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला

एसोसिएट पब्लिशर: विद्या मेनन (इंपैक्ट)
इंपैक्ट टीम
नेशनल हेड: सुपर्णा कुमार (गवर्नमेंट ऐंड पीएसयू)
सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरू)
डिप्टी जनरल मैनेजर: इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: योगेश गोधनलाल गौतम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 35; अंक: 47; 14-20 अक्तूबर, 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.

- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित.**

संपादक: राज चेंगप्पा

सुर्खियां
ममता बनर्जी: अब दिल्ली में 'खेला होबे'
पेज 6

अर्थात्: सब बिन सब अधूरा
पेज 15

फुरसत
किताबें/विक्रम सेठ: छंदों में बुना जीवन
पेज 62

सवाल-जवाब/पंडित हरिप्रसाद चौरसिया: दिखता है बस दरवाजा
पेज 64

भीतर

20
आवरण कथा

हेरोइन: नशा सिर चढ़ा

गोल्डन क्रेसेंट क्षेत्र से अफीम के अवैध व्यापार में वृद्धि ने भारत को एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब और बड़ा उपभोक्ता बना दिया है.

अमरिंदर सिंह

31 राजा की बगावत

पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाता कांग्रेस से टूटना और पंजाब की सियासत में नए अध्याय की शुरुआत लगभग तय.

उत्तर प्रदेश

16 हिंसा ने बढ़ा दी चुनौती

लखीमपुर खीरी में हालिया कांड ने भाजपा को मुश्किल में डाला.

हेल्थगीरी अवार्ड

42 सबसे ऊपर सेहत

हेल्थगीरी अवार्ड में कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन हुआ.

इंडिया टुडे

इंडिया टुडे मैगजीन मिलने में दिक्कत हो रही है?
9311409555 पर नाम पता या 'हेलो' संदेश भेजें.
या मेल करें: Moreinfo@intoday.com
हम आपसे संपर्क कर लेंगे.

आवरण: बंदीप सिंह, डिजिटल इमेजिंग: अमरजीत सिंह नागी

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

मध्य प्रदेश:
आदिवासी ताल पर
पेज 10

सुर्खियां

आंध्र प्रदेश: दरवाजे
पर सरकार
पेज 12

देवज्योति चक्रवर्ती

जीत का दम
टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

ममता बनर्जी

अब दिल्ली में 'खेला होबे'

रोमिता दत्ता

भवानीपुर उप-चुनाव से पहले 26 सितंबर को एक नुक्कड़ बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया: ''भबानीपुर थेके आर एकटा खेला शूरू हॅबे. ई खेला शेष हॅबे भारतबर्ष जॉय कॅरे (भवानीपुर में एक नया खेल शुरू हुआ है, जिसकी परिणति भारत को जीतने में होगी).'' तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ने हाल-फिलहाल यह संदेश देना शुरू किया है कि उनकी पार्टी बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद हासिल अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाएगी और अब इसकी निगाहें दिल्ली पर टिक गई हैं. उसी सभा में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इसे थोड़ा खुलकर कहा, ''याद रखिए, आप सिर्फ दीदी के लिए वोट नहीं कर रहे, आप दिल्ली में बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं.''

यहां एक साथ दो अभियान चल रहे हैं: पहला 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए एक लचीला विपक्षी गठबंधन बनाना है; दूसरा ममता बनर्जी को उस समूह के नेता के रूप में पेश करना है. पिछले एक या दो महीने में, टीएमसी के दिग्गजों ने इस बात पर चर्चा को बढ़ावा दिया है कि नेतृत्व करने के लिए सबसे अच्छा कौन है. इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि भाजपा के खिलाफ टीएमसी की लड़ाई सबसे विश्वसनीय थी—विशेष रूप से, चुनावों में मोदी/शाह के नेतृत्व वाले चौतरफा हमले झेल पाने के

कारण—अभिषेक जैसे टीएमसी नेताओं ने संभावित दावेदार पर ममता के दावे पर बात करना शुरू कर दिया है. उदाहरण के लिए, वे कांग्रेस नेताओं के बारे में कहते हैं कि उन्होंने या तो हार मान ली है या छिप गए हैं. उनकी नई मुखरता कमजोर विपक्षी एकता को आसानी से नुक्सान पहुंचा सकती है, लेकिन टीएमसी नेताओं का मानना है कि ममता के लिए शीर्ष स्थान के लिए दांव खेलने का समय आ गया है.

कई मामलों में, भाजपा इस वक्त बैकफुट पर है—ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, महंगाई बढ़ रही है और पिछले डेढ़ साल में महामारी ने गहरा आर्थिक संकट पैदा किया है. कुछ लोगों का तर्क है कि इससे निश्चित तौर पर सत्ता विरोधी लहर उठेगी और ममता को खुद को भाजपा के विकल्प के तौर पर पेश करने का उतना ही अच्छा मौका मिलेगा. राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे के अनुसार, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसी ही स्थिति मौजूद थी, जब घोटाले से ग्रस्त यूपीए-दो सत्ता विरोधी लहर से जूझ रहा था, जो अंततः उसकी हार का कारण बना. उस समय, भाजपा ने संकट का फायदा उठाते हुए नरेंद्र मोदी को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया था जो 'अच्छे दिन' की शुरुआत कर सकता था, उन्हें तीन बार के मुख्यमंत्री के रूप में सफल बताते हुए और भारत की आर्थिक परेशानी के लिए विकास के गुजरात मॉडल को रामबाण बताया. टीएमसी भी उसी तर्ज पर चल रही है—इस बार उसका टैग लाइन ''भारत निजेर मेयेकेइ चाइ (भारत को अपनी ही बेटी चाहिए).'

हालांकि ममता ने अब तक खुले तौर पर संभावित विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व का दावा करने से परहेज किया है, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल के रास्ता दिखाने के बारे में अपने बयानों से संभावना की ओर इशारा किया है. कड़े मुकाबले में लड़े गए विधानसभा चुनाव में अपनी बड़ी जीत के तुरंत बाद, उन्होंने घोषणा की: ''बंगाल ने भारत को बचा लिया है.'' टीएमसी के राज्यसभा सांसद और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार कहते हैं कि इस चुनावी जीत ने उन्हें बिलाशक राष्ट्रीय कद का बना दिया है. वे कहते हैं, ''प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल का 18 बार दौरा किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 बार. इन्होंने चुनाव को जीवन-मरण का प्रश्न बना लिया. ममता इस असाधारण जीत को विपक्ष के एकजुट करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं. जो (भाजपा के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की) छापेमारी से हिला हुआ नजर आ रहा है, पर वे डरने वाली नहीं हैं.'' इस संदर्भ में, ममता का 'तृणमूल ही काफी है' नारा भाजपा के खिलाफ अभियान शुरू करने में अन्य विपक्षी दलों की भी चुनौती जैसी लग रही है.

सरकार कहते हैं कि टीएमसी की आक्रामक बयानबाजी में उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता, जो आमतौर पर कांग्रेस पर निशाना साधती प्रतीत होती है. वे कहते हैं, ''ममता (अपना यह विश्वास) नहीं छिपाती हैं कि कांग्रेस को और अधिक ऊर्जावान होने की जरूरत है.'' रे भी ऐसी ही बात कहते हैं कि ममता विपक्ष को तेजी से एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि देरी का फायदा भाजपा को ही मिलेगा. वे कहते हैं, ''हम बैठकर कांग्रेस के अधिक सक्रिय होने का इंतजार नहीं कर सकते. बड़ा सवाल यह नहीं है कि नेतृत्व कौन कर रहा है, बड़ा सवाल भाजपा से लड़ने के लिए एक बैनर के तहत एक साथ आने का है.''

यह भी सच है कि कई नेताओं का कांग्रेस नेतृत्व से मोहभंग हो गया है, जिससे ममता के लिए शीर्ष स्थान का दावा करने के लिए मैदान खुला है. कांग्रेस के दिग्गज नेता और गोवा के दो बार के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फलीरो टीएमसी में शामिल होने वालों में से एक हैं. 29 सितंबर को टीएमसी प्रमुख से राज्य मुख्यालय नवन्ना में मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, ''ममता ने पहले ही साबित कर दिया है कि वे भाजपा को हरा सकती हैं. अब वक्त आ गया है कि हम एक नए नेता को प्रोजेक्ट करें जो देश को एक नई दिशा दे सकता है.''

पश्चिम बंगाल की जीत का मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत बड़ा है. इस तथ्य के बावजूद कि टीएमसी की राष्ट्रीय उपस्थिति नगण्य है और देश के अन्य हिस्सों में उसका कोई विधायक नहीं है, कई सियासी पर्यवेक्षक पहले से ही टीएमसी को एक क्षेत्रीय दल से कहीं अधिक देखते हैं. हालिया संघर्ष ने पार्टी को नई प्रतिष्ठा दिलाई है. उदाहरण के लिए, केवल फलीरो और गोवा में उसके 10 सहयोगियों को अपने साथ लाने की कामयाबी ने पार्टी को राज्य में एक खिलाड़ी बना दिया है.

हालांकि ममता ने अब तक खुले तौर पर संभावित विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व का दावा करने से परहेज किया है, लेकिन वे कहती हैं कि बंगाल ही रास्ता दिखाता है

उत्तर प्रदेश में वह समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ की कोशिश कर रही है. बंगाल में भाजपा के पूर्व दिग्गज बाबुल सुप्रियो और कांग्रेस की सुष्मिता देव ने भी दल-बदल लिया है. इस तरह के घटनाक्रम ममता को राष्ट्रीय नेता के रूप में समर्थन देने का संकेत देते हैं, वैसे अभी इसके शुरुआती दिन हैं.

आने वाले दिनों में, टीएमसी अधिक से अधिक वरिष्ठ नेताओं को शामिल करके ममता के दावे को और मजबूत करने की कोशिश करेगी. इससे पहले कि वह अगले दो वर्षों में अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में मुट्ठी भर सीटें जीतने की कोशिश करे वह अन्य राज्यों में सियासी पदचिन्ह बनाना चाहेगी—खासतौर पर छोटे राज्य, जहां यह आसान हो सकता है. देव और फलीरो के अलावा, जिनके पास अपने खास समर्थक हैं, टीएमसी त्रिपुरा के प्रद्योत देबबर्मा, राज्य के सबसे बड़े स्थानीय समूह, टीआइपीआरए (द इंडिजीनस पीपल्स रीजनल अलायंस) मोथा के मुखिया—जैसे नेताओं को भी शामिल करना चाह रही है. टीएमसी के एक नेता नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं, ''ममता ऐसे लोगों

समय का संकेत
हावड़ा में 29 सितंबर को गोवा के पूर्व सीएम लुइजिन्हो फलीरो (बाएं) के साथ ममता बनर्जी

एएनआइ

को साध रही हैं, जो मुखर होंगे और जो संसद में असर छोड़ेंगे. इसके साथ ही वे टीएमसी की आवाज को पूरे राष्ट्र में पहुंचाएंगे.''

ममता ने अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के जरिए कांग्रेस के जी-23 नेताओं से बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे हैं, जो विभिन्न मामलों में वकील के रूप में राज्य और टीएमसी का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे पहले ही अन्य विपक्षी नेताओं से तारीफ बटोर चुकी हैं—मनीष तिवारी ने उन्हें 'झांसी की रानी' बताया तो गुलाम नबी आजाद ने उन्हें 'पूरब की शेरनी' कहा है. सलमान खुर्शी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनकी जीत को ''राहत और सुकून'' करार देते हुए कहा कि इससे जाहिर हो गया कि ''भाजपा को स्थायी चुनौती देने के लिए नए सिरे से योजना विकसित करने की जरूरत'' है.

सियासी प्रेक्षकों का कहना है कि भाजपा को चुनौती देने के लिए ममता के साथ कांग्रेस से अलग हुए गुट के शामिल होने की प्रबल संभावना है. उन्हें एक विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, यह सुझाव बढ़ता रहा है और टीएमसी अगले दो वर्षों में विधानसभा चुनावों में—उदाहरण के लिए, त्रिपुरा, गोवा या मेघालय में—सीटें जीतने में अगर सक्षम होती है तो ये आवाजें अधिक मुखर हो जाएंगी.

यशवंत सिन्हा जैसे नेता, जो इस साल मार्च में में टीएमसी में शामिल हुए, मोदी-शाह की भाजपा में बीते आठ साल से निष्क्रिय थे, इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि ममता की पार्टी के पास अभी तक एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में चुनावी वैधता नहीं है. सिन्हा खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में वित्त और विदेश मामले संभाले थे. सिन्हा कहते हैं कि उन्हें ममता के नेतृत्व की साख के बारे में तनिक भी संदेह नहीं है. वे पूछते हैं, ''ममता ने कई वर्षों तक केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है. उन्हें केंद्र सरकार के कामकाज की बहुत स्पष्ट समझ है. प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी को वित्त या विदेश मामलों में क्या अनुभव था?''

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में ममता के अनुभव का मतलब यह भी है कि उन्हें इस बात का स्पष्ट अंदाजा है कि वे किस तरह के शासन की पक्षधर हैं—एक कल्याणकारी राज्य. अन्य लोग मॉडल से सहमत हों या नहीं, यह परखा हुआ मॉडल है, जिसमें कई योजनाओं का श्रेय उन्हें जाता है. इनमें कन्याश्री (उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए वजीफा), खाद्यसाथी (सब्सिडी वाले चावल का राशन), स्वास्थ्यसाथी (पांच लाख रुपए तक का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा), लोखीर (लक्ष्मी) भंडार (गृहिणियों को नकद हस्तांतरण), छात्रों को 10 लाख रुपए की क्रेडिट सीमा के साथ स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सॉफ्ट लोन के साथ ही पेंशन, बेरोजगारी भत्ता आदि शामिल हैं.

अपने कल्याणवाद को प्राथमिकता देने से—इससे राज्य के खजाने से हर साल लगभग 24,255 करोड़ रुपए खर्च होते हैं—ममता को उनके राजनैतिक विरोधी राज्य की माली हालत को लेकर लापरवाह नेता के रूप में देखते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि यह ध्यान विकास की कीमत पर नहीं आया है. सरकार कहते हैं, ''जीडीपी की वृद्धि सकारात्मक रही है. और यही कल्याणकारी राज्य है. पुलों या सड़कों या पूंजीगत संपत्ति के निर्माण से ठेकेदारों को फायदा होता है, जबकि ममता के मॉडल से गरीबों को फायदा होता है.''

एसबीआइ रिसर्च के अनुसार, पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में 13.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 15.1 लाख करोड़ रुपए की हो गई है. उस पर अभी भी लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए कर्ज का भारी बोझ है. उनके कल्याणकारी मॉडल की एक और चर्चित विशेषता बिचौलियों को दूर करने और लाभ का दावा करने के लिए लोगों को प्रशासनिक कार्यालयों तक जाने को आवश्यकता खत्म करने की है. 'दुआरे सरकार' और 'दुआरे राशन' जैसी योजनाओं के तहत राशन और अन्य लाभों को दरवाजे तक पहुंचाया गया है.

समाज विज्ञानी और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमिरेटस प्रशांत रे कहते हैं, ''यह प्रशासन के विकेंद्रीकरण और बिचौलियों को दूर करने की अनूठी मिसाल है. विधानसभा चुनाव से तीन महीने पहले दुआरे सरकार को लॉन्च करके ममता ने अपने प्रशासन में लोगों की आस्था मजबूत बना ली. मतदान प्रक्रिया और सामाजिक कल्याण योजनाओं में महिलाओं की बड़ी भागीदारी ने राज्य में भाजपा की किस्मत पर ताला जड़ दिया.''

एक और तरीका है जिसमें ममता मोदी की भाजपा का मजबूत और अलग विकल्प पेश करती हैं, वह है भारत की 'समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक' पहचान के प्रति प्रतिबद्धता का सार्वजनिक समर्थन, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में निहित है. सरकार कहते हैं, ''ममता श्लोकों (हिंदू धार्मिक ग्रंथों से) का पाठ कर सकती हैं, वे कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब से भी उद्धरण दे सकती हैं और आसानी से उर्दू शेर भी पढ़ सकती हैं. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका धर्म मानवतावाद है.'' वे अपने प्रमुख विरोधी जैसी तानाशाही भरे रवैए वाली भी हो सकती हैं, लेकिन भारत की उनकी समावेशी दृष्टि मोदी के भारत के 'न्यू नॉर्मल' के एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ी है. ■

मध्य प्रदेश

आदिवासी ताल पर

राहुल नरोन्हा

राही फेरा: पीएमओ

हाल के महीनों में, मध्य प्रदेश में घटनाओं का पूरा एक सिलसिला चला जिसने साबित किया कि भाजपा ने संभावित लुभावनी सूची में एक नए समुदाय को शामिल कर लिया है. और वह है आदिवासी वोटर. मार्च में राज्य सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जनजातीय सम्मेलन में दमोह आमंत्रित किया था. 18 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1857 के जनविद्रोह के जनजातीय नायकों शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ की शहादत की 164वीं सालगिरह में हिस्सा लेने जबलपुर गए. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नियमित रूप से सूबे के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के आदिवासी-बहुल जिलों का दौरा कर रहे हैं और इन समुदायों के लिए कई योजनाओं की घोषणा भी कर रहे हैं.

मध्य प्रदेश में करीब 2 करोड़ जनजातीय आबादी है या राज्य की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीबन 21 प्रतिशत है. मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं और यहां की 29 लोकसभा सीटों में से छह इस समुदाय के लिए हैं. यह समुदाय सरकार बना या गिरा सकता है, यह बात सियासी दलों के जेहन में है—2013 में भाजपा ने 47 में से 30 सीटें जीती थीं और उसकी सरकार बनी थी. 2018 में बाजी पलटी और कांग्रेस ने इस समुदाय की 47 में से 30 सीटें जीतीं और 15 सालों में पहली बार उसकी सरकार बनी थी, जो कि अल्पजीवी साबित हुई. ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके वफादारों के भाजपा में जाने की वजह से कमलनाथ की अगुआई वाली कांग्रेस सरकार गिर गई और उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान ने कुर्सी संभाली.

आदिवासियों को रिझाने की भाजपा की कोशिशों में (यह कई राज्यों में चल रहा है) पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से की गई कई घोषणाएं शामिल हैं. मसलन, जबलपुर में गृह मंत्री शाह ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार आदिवासी नेताओं के सम्मान में देश भर में 200 करोड़ रुपए की लागत से नौ संग्रहालय बनवाएगी, जिनमें से एक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में होगा जो शंकर और रघुनाथ शाह पर केंद्रित होगा. भाजपा के प्रदेश सचिव राहुल कोठारी बताते हैं, ''हमारी पार्टी वनवासी समुदाय को मुख्यधारा में लाना चाहती है. इस दिशा में आदिवासी नायकों के इतिहास को सामने लाने का हमने कदम उठाया है.''

उसी दिन मुख्यमंत्री चौहान ने भी ऐलान किया कि ऐसे आदिवासी गांव जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं, उन्हें राशन साप्ताहिक हाटों में उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए गाड़ियां स्थानीय लोगों से 26,000 रुपए प्रति माह की दर पर किराए पर ली जाएंगी. पार्टी को उम्मीद है कि ऐसे कदमों से सियासी नफा होगा—जबलपुर में गृह मंत्री के दौरे के कुछेक दिन पहले, पार्टी के प्रदेश एसटी मोर्चे की बैठक में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, ''मोर्चे को अपनी पूरी ताकत के साथ आगे आना चाहिए ताकि पार्टी को आदिवासी समर्थन मिल सके.''

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18 सितंबर को ऐलान किया कि जनजातीय नायकों की स्मृतियां संजोकर रखने के लिए 200 करोड़ रु. की लागत से देश भर में संग्रहालय बनाए जाएंगे

भाजपा आदिवासी क्षेत्रों के लिए और अधिक स्वायत्तता का वादा कर रही है—उसी बैठक में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य केंद्र के पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायत विस्तार) अधिनियम के कार्यान्वयन में सुधार करेगा. इसी की संभावना खंगालने को फरवरी में राज्य सरकार ने राज्य के आदिवासी अनुसंधान संस्थान, आदिम जाति कल्याण विभाग, पंचायत और ग्रामीण कल्याण विभाग और वन विभाग के सदस्यों के साथ एक समिति का गठन किया. इसने अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं को अधिक स्वायत्तता देने के दो तरीकों की पहचान की है—उन्हें गैर-लकड़ी वन उपज (या लघु वन उपज, जैसे तेंदू पत्ते) से आय का एक प्रतिशत रखने की अनुमति

धुन हमारी, नाच उनका
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जबलपुर में; (नीचे) पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल में 9 अगस्त को एक विरोध प्रदर्शन में

देकर और उन्हें छोटे-मोटे विवादों का निबटारा खुद करने की अनुमति देकर.

अब मुख्यमंत्री को फैसला करना है कि इन्हें लागू किया जाए या नहीं. यह कठिन फैसला है, इसलिए नहीं कि राज्य की नौकरशाही इन प्रस्तावों के सख्त खिलाफ है, बल्कि इसलिए भी कि इस फैसले से राज्य के खजाने पर भी बोझ पड़ेगा. राज्य में करीब 12,000-15,000 करोड़ रुपए कीमत की गैर-लकड़ी वनोपज होती है. वन विभाग के एक अधिकारी कहते हैं, ''अगर गैर-लकड़ी वनोपज कारोबार को ग्रामसभा को सौंप दिया गया, तो न सिर्फ सरकार को राजस्व का घाटा होगा, इसके साथ ही सियासी संरक्षण देना भी मुश्किल होगा, जो सरकार हर साल वेतन और बोनस के रूप में देती है.'' वे बताते हैं कि इसको भाजपा के खिलाफ खड़े वाम धड़ों की जीत के रूप में भी देखा जाएगा, जो पेसा अधिनियम को लागू करने की जोरदार मांग करते रहे हैं.

कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस ने भी पेसा प्रावधानों के अधिक कार्यान्वयन के लिए इस समय पर जोर देने पर सवाल उठाया है. जबकि मध्य प्रदेश भारत के उन 10 राज्यों में से एक है, जिन्हें पेसा-पालन करने वाला माना जाता है (इसने भूमि अधिग्रहण, जल निकायों के प्रबंधन आदि से संबंधित कुछ प्रावधानों को लागू किया है), जबकि इसके कार्यान्वयन के लिए ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ मध्य प्रदेश को भी अभी नियम बनाना है. वास्तव में, इसका मतलब यह है कि दूसरे कानूनों के साथ पेसा का टकराव होने पर पेसा कमजोर पड़ जाता है. इसका मतलब यह भी है कि इसके प्रावधानों को लागू न करने पर एजेंसियों, विभागों या अधिकारियों को दंडित करने का कोई तरीका भी नहीं है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता कहते हैं, ''भाजपा को बताना चाहिए कि 15 साल से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बावजूद उसने पहले पेसा क्यों लागू नहीं किया?''

राजनैतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि पेसा को भाजपा ने अचानक गले इसलिए लगाया है क्योंकि उसे चिंता है कि यह जय आदिवासी युवा शक्ति (जेएवाइएस) और पुनरुत्थानवादी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) जैसी आदिवासी इकाइयों के मुकाबले अपनी राजनैतिक जमीन खो रही है. जेएवाइएस जहां पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा है, वहीं जीजीपी पूर्वी मध्य प्रदेश और महाकौशल में अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है. भाजपा की निगाह में जेएवाइएस कांग्रेस की बी टीम है—2018 के विधानसभा चुनावों में जेएवाइएस के सदस्य डॉ. हीरालाल अलावा ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता था. इसी तरह, कांग्रेस जीजीपी को भाजपा की बी टीम मानती है.

इस बीच, कांग्रेस भी आदिवासियों के बीच अपने आधार को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है—मिसाल के तौर पर, 2019 में, तब के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आदिवासियों के सारे कर्ज माफ करने की घोषणा की थी. एक वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी कहते हैं, ''पार्टी के भीतर इस बात की चिंता है कि भाजपा और आरएसएस के सांस्कृतिक एजेंडे को अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के भीतर पैरोकार मिल गए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस के साथ उनके संपर्क कमजोर हो गए हैं.'' वे यह भी कहते हैं, ''बहरहाल, आदिवासी अभी भी कांग्रेस समर्थक हैं.'' पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में आदिवासी अभी भी इसके कट्टर समर्थक है—यहां तक कि राज्य के मुस्लिम समुदाय में भी विरोध की आवाजें हैं (जो आबादी में सात प्रतिशत हैं) कि कांग्रेस उनके समर्थन में आगे नहीं आती जब दक्षिणपंथी हिंदू समूह उन पर हमला करते हैं. नतीजतन, एआइएमआइएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन) और एसडीपीआइ (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया) ने भी खुद को विकल्प के रूप में पेश करके कामयाबी हासिल करनी शुरू कर दी है.

एसटी के लिए आरक्षित जोबट सहित तीन सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के मद्देनजर ऐसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है. हाल के हफ्तों में कांग्रेस राज्य भर में आदिवासियों पर हमलों का मुद्दा उठाती रही है. ऐसी ही एक घटना अगस्त के अंत में नीमच में हुई थी, जब एक सड़क किनारे विवाद के कारण एक आदिवासी पर आठ लोगों ने हमला किया और फिर उसे एक वाहन के पीछे बांधकर घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

बहरहाल, भले ही भाजपा और कांग्रेस खुद को आदिवासियों के लिए संरक्षक के रूप में पेश करते हैं, एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) के आंकड़े एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं. उसकी वार्षिक रिपोर्ट 'क्राइम इन इंडिया' में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचारों में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है—2020 में 2,401 मामले दर्ज किए गए जबकि 2019 में 1,922 मामले दर्ज किए गए थे. राजनैतिक दलों को चाहिए कि वे सही मायने में जनजातीय कल्याण की चिंता करें, न कि चुनावी नफे पर निगाह टिकाए हुए कोरी लफ्फाजी करें. ■

आंध्र प्रदेश

दरवाजे पर सरकार

लोगों के लिए
पूर्वी गोदावरी जिले में नरेंद्रपुरम ग्रामीण सचिवालय में पहुंचे लोग

अमरनाथ के. मेनन

हर महीने एक से तीन तारीख के बीच आंध्र प्रदेश सरकार 61 लाख लाभार्थियों को वाइएसआर पेंशन कानुका के तहत पेंशन देती है, जिसमें 1,420.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं. लाभार्थी चाहे कहीं भी हों, उन्हें यह पेंशन दी जाती है, यहां तक कि घर से विस्थापित हुए लोगों को भी. इसके पारदर्शी और लक्षित वितरण के लिए राज्य सरकार बॉयोमीट्रिक पहचान पर निर्भर है.

पेंशन का समय पर वितरण 541 सेवाओं में एक है—जिसमें 30 से ज्यादा कल्याणकारी कार्यक्रम शामिल हैं—जिसे आंध्र प्रदेश सरकार गांव और वार्ड सचिवालय के अपने विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से प्रदान करती है. इस तरह सालाना लगभग एक लाख करोड़ रुपए का वितरण होता है. पेंशन के अलावा, इन सेवाओं में चावल कार्ड, आरोग्यश्री स्वास्थ्य कवर कार्ड, घर के दस्तावेज, जाति और आय प्रमाण पत्र शामिल हैं, जो सभी 11,162 ग्राम सचिवालय और शहरी क्षेत्रों में 3,842 वार्ड सचिवालय तय समय के भीतर मुहैया कराते हैं. लोगों की सहायता के लिए वालेटियर की एक फौज है, जिनमें प्रत्येक के पास औसतन 50 घरों की जिम्मेदारी होती है. वे घरों का सर्वेक्षण करते हैं और लोगों को सरकारी अधिकारियों से जुड़ने में मदद करते हैं.

मुख्यमंत्री वाइ.एस. जगन मोहन रेड्डी की 2 अक्तूबर को शुरू की गई यह व्यवस्था विकेंद्रीकृत प्रशासन और जमीनी स्तर के शासन में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है. हालांकि सरकार की कल्याणकारी पहुंच राजनैतिक गणना के बिना नहीं है. इसका लक्ष्य हर आदमी, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग या राजनैतिक पार्टी से संबद्ध हो–को सरकारी योजना या सेवा का लाभ मिले. ग्राम सचिवालय शिकायतों की भी सुनवाई करती है. लोगों को संतुष्ट करने की यह रणनीति निश्चित रूप से चुनावी लाभ भी देगी. ग्राम स्वयंसेवक/वार्ड स्वयंसेवक और ग्राम सचिवालय/वार्ड सचिवालय (जीवीडब्ल्यूवी और वीएसडब्ल्यूएस विभाग) नागरिक केंद्रित वितरण मॉडल चलाता है. एक संयुक्त कलेक्टर सभी 13 जिला मुख्यालयों पर होने वाले काम की निगरानी करता है.

एक ग्राम सचिवालय के तहत लगभग 2,000 की आबादी है, जबकि एक वार्ड सचिवालय के तहत शहरी क्षेत्रों में लगभग 4,000 लोग हैं. सभी गांव और वार्ड के स्वयंसेवकों को स्मार्ट फोन (राज्य ने 2,70,000 उपकरण वितरित किए हैं) और फिंगरप्रिंट स्कैन दिए जाते हैं. कोविड सलाह, योजनाओं के क्रियान्वयन पर फीडबैक, कार्यक्रम के असर का सर्वेक्षण और अन्य संदेश बहुत कम समय में 1.2 करोड़ से अधिक घरों में भेजे जाते हैं.

लोगों को अब मंडल, जिला या संभाग कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते. स्वयंसेवक उनके दरवाजे पर उनसे मिलने जाता है. जीवीडब्ल्यूवी और वीएसडब्ल्यूएस विभाग के विशेष मुख्य सचिव अजय जैन कहते हैं कि विभिन्न योजनाओं के वितरण और समय-सीमा तय है और हर महीने ऑनलाइन डैशबोर्ड से निगरानी की जाती है.

ग्रामीण/वार्ड सचिवालय व्यवस्था का लक्ष्य हर योग्य व्यक्ति तक कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ ऐसे पहुंचे कि वह संतुष्ट हो जाए

नतीजतन, जिला कलेक्टरों के कार्यालयों और राज्य सचिवालय में आने वालों का प्रवाह तेजी से घट गया है. सबसे पहले तेलुगू देशम पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री दवंगत एन.टी. रामराव ने ऐसी योजना शुरू की थी. जगन ने इसे एकदम दरवाजे पर पहुंचाया है. जैन कहते हैं, ''मुख्यमंत्री का इरादा है कि कोई भी योग्य छूटे नहीं और कोई भी अपात्र पाए नहीं.'' ग्राम पंचायत सचिव के अलावा प्रत्येक कार्य दिवस में अपराह्न 3 से 5 बजे के बीच ग्राम स्तर के शासकीय पदाधिकारियों का स्थानीय सचिवालय में उपस्थित होना अनिवार्य है.

इस बीच, कई राज्यों ने इस मॉडल को समझने के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा है. सत्तारूढ़ वाइएसआरसी का मानना है कि इस प्रणाली ने स्थानीय निकाय चुनावों में उसकी चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. राजनैतिक टिप्पणीकार रवि कोमारराजू कहते हैं, ''जगन अपनी छवि ऐसे नेता की बनाने में सफल रहे हैं, जो वादे पूरा करता है.''

हालांकि राज्य का बढ़ा हुआ वित्तीय बोझ जगन के लिए चुनौती है. अर्थशास्त्री के.सी. रेड्डी कहते हैं, ''वैज्ञानिक अध्ययन के बाद यह राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जा सकती है. 1992 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के बाद से स्थानीय प्रशासन की बातें तो होती हैं, लेकिन ये चुनावी घोषणापत्रों तक ही सीमित रह जाती हैं.'' ■

अर्थात्

सब बिन सब अधूरा

अंशुमान तिवारी

अमेरिका और यूरोप में उत्सवी सामान (थैंक्सगिविंग-क्रिसमस) की कमी पड़ने वाली है. चीन में कोयला कम है, बत्ती गुल है, कारखाने बंद हैं. यूरोप में गैस की कीमतें उबल रही हैं. ब्रिटेन में कामगारों की किल्लत है. रूस में मीट नहीं मिल रहा. यूरोप की कार व इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के पास पुर्जे नहीं हैं.

दुनिया में तो मंदी है, मांग का कोई विस्फोट नहीं हुआ है फिर यह क्या माजरा है?

कहते हैं, अगर अमेरिकी राज्य न्यू मेक्सिको में कोई तितली अपने पंख फड़फड़ाए तो चीन में तूफान आ सकता है. यानी दुनिया इतनी पेचीदा है कि छोटी-सी घटना से बड़ी उथल-पुथल (बटरफ्लाइ इफेक्ट या केऑस थ्योरी) हो सकती है.

हवा पानी के बाद अगर कोई चीज हमें चला रही है तो वह सप्लाइ चेन है जो करीबी दुकान से लेकर भीतरी चीन, या दक्षिण अमेरिका के सुदूर इलाकों तक फैली हो सकती है. सामान, सेवाओं, श्रमिकों, ईंधन, खनिज आदि की ग्लोबल आपूर्ति का यह पर्तदार और जटिल तंत्र इस कदर बहुदेशीय और बहुआयामी है कि *द वर्ल्ड इज फ्लैट* वाले थॉमस फ्रीडमैन कहते रहे हैं कि अब दुनिया में युद्ध नहीं होंगे क्योंकि एक ही सप्लाइ चेन में शामिल दो देश एक-दूसरे से जंग नहीं कर सकते. इसे डेल (कंप्यूटर) थ्योरी ऑफ कन्फलिक्ट प्रिवेंशन कहते हैं.

दुनिया में लगभग सभी जरूरी चीजों की उत्पादन क्षमताएं पर्याप्त हैं फिर भी कारोबारी धमनियों में उतनी सप्लाइ नहीं है लंबी बाजार बंदी के बाद जितनी जरूरत थी.

विश्व की पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाएं—अमेरिका, चीन, जर्मनी, यूके, रूस और ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ा गई हैं. यही पांच देश दुनिया की सप्लाइ चेन में बड़े ग्राहक भी हैं और आपूर्तिकर्ता भी. इनके संकट पूरी तरह न्यू मेक्सिको की तितली जैसे हैं यानी स्थानीय. लेकिन सामूहिक असर पूरी दुनिया की मुसीबत बन गया है. किल्लत अब लाखों सामान की है लेकिन वह चार बड़ी आपूर्तियां टूटने का नतीजा है, जो ग्लोबल सप्लाइ चेन की बुनियाद हैं.

ऊर्जा या ईंधन में चौतरफा आग लगी है. कोविड से पहले 2020 और '21 की भीषण सर्दियों में यूरोप ने अपने ऊर्जा भंडारों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया. उत्पादन बढ़ता इससे पहले कोविड आ गया. एक साल में यूरोप में नेचुरल गैस 300 फीसद महंगी (स्पॉट प्राइस) हो गई. बिजली करीब 250 फीसद महंगी हुई हालांकि उपभोक्ता बिल नहीं बढ़े. भंडार क्षमताएं बीते बरस से 19 फीसद कम हैं.

चीन दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला इस्तेमाल करता है. सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से आयात रोक दिया था. चीन में कोयला महंगा है लेकिन सरकार बिजली सस्ती रखती है. नुक्सान बढ़ने से कोयले का खनन कम हुआ. बिजली की कटौती से कारखाने रुके तो अमेरिका-यूरोप व भारत में जरूरी आपूर्ति टूटने लगी.

इधर, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ओपेक कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए इंतजार करना चाहता है इसलिए पूरा ऊर्जा बाजार ही महंगाई से तपने लगा है.

महामारी वाली मंदी से उबर रहे विश्व को यह अंदाज नहीं था कि अब तक की सबसे जटिल शिपिंग किल्लत उनका इंतजार कर रही है. बीते एक साल में कई बंदरगाहों पर जहाज फंस गए. इस बीच कंटेनर बनाने वाली कंपनियों (तीनों चीन की) ने उत्पादन घटा दिया. अब मांग है तो कंटेनर और जहाज नहीं. नतीजतन, किराए चार साल की ऊंचाई पर हैं. यह संकट दूर होते एक साल बीत जाएगा. लेकिन तब अमेरिका में क्रिसमस गिफ्ट, रूस में खाने का सामान, ऑस्ट्रेलिया को स्टील की कमी रहेगी. भारतीय निर्यातक महंगे भाड़े से सांसत में हैं.

मध्य और पूर्वी यूरोप के मुल्कों में कामगारों की कमी हो गई है. अमेरिका और यूरोप में बेरोजगारी सहायता स्कीमें बंद होने वाली हैं. कई जगह लोग वर्क फ्रॉम होम से वापस नहीं आना चाहते. कमी है तो मजदूरी महंगी हो रही है जो कंपनियों की लागत बढ़ा रही है. ब्रिटेन में पेट्रोल, खाद्य और दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए कामगारों की कमी हो गई है. ब्रेग्जिट के बाद प्रवासियों को आने से रोकना अब महंगा पड़ रहा है.

कहते हैं कि अगर ट्रंप की अगुआई में चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध के दौरान सेमीकंडक्टर या चिप ग्राहकों ने दोगुनी खरीद के ऑर्डर न दिए होते तो आज यह नौबत नहीं आती. चिप नया क्रूड आयल है. कोविड के कारण कारों का उत्पादन प्रभावित हुआ तो चीन व ताइवान की कंपनियों ने स्मार्ट फोन, कंप्यूटर वाले चिप का उत्पादन बढ़ा दिया. ऑटोमोबाइल की मांग लौटी तो उत्पादन क्रम में फिर बदलाव हुआ. अब सभी के लिए चिप की किल्लत है.

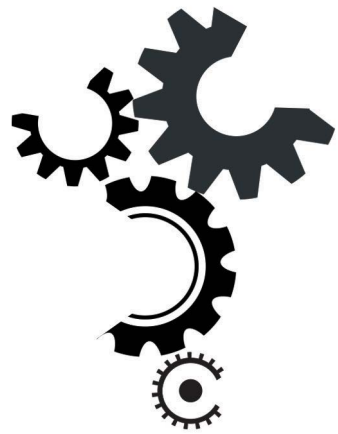

दुनिया में तो मंदी है, मांग का कोई विस्फोट नहीं हुआ है फिर भी यह महंगाई कहां से आ रही?

ईंधन, परिवहन, चिप और श्रमिक के बिना आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल है. इनकी कमी स्टैगफ्लेशन को न्योता दे रही है. यानी महंगाई और आर्थिक सुस्ती एक साथ. दुनिया के देशों को सबसे पहले सप्लाइ चेन यानी आपूर्ति की धमनियों को दुरुस्त करना होगा. सस्ता कर्ज मंदी से उबरने का शर्तिया इलाज रहा है लेकिन महंगाई के सामने यह दवा बेकार है. कर्ज महंगे होने लगे हैं.

नेपोलियन बज़ा फरमाते थे: नौसिखुए कमांडर जंग में टैक्टिक्स (रणनीति) की बात करते हैं जबकि पेशेवर लड़ाके लॉजिस्टिक्स (साधनों) की. सनद रहे कि जंग अब महामारी और मंदी के साथ महंगाई से भी है.

@anshuman1tiwari

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

खास रपट | उत्तर प्रदेश

हिंसा ने बढ़ा दी भाजपा की चुनौती

लखीमपुर खीरी में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत ने राज्य में भाजपा को मुश्किल में डाल दिया है. किसानों की नाराजगी के साथ-साथ नए सियासी समीकरण भी उभर रहे

आशीष मिश्र

लखनऊ से करीब ढाई सौ किलोमीटर दूर नेपाल की सीमा से सटे लखीमपुर खीरी की निघासन तहसील के तिकुनिया कस्बे में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा कोड़ीवाला घाट हिमालय की तराई में बसे सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थान है. मान्यता है कि इसका निर्माण सिखों के प्रथम गुरु नानक देव ने कराया था. हर महीने की अमावस्या को यहां विशेष पाठ और कीर्तन का आयोजन होता है जिसमें आसपास के जिलों से लाखों की संख्या में सिख श्रद्धालु शामिल होते हैं. इस बार 6 अक्तूबर को पड़ी अमावस्या में इस गुरुद्वारा के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा था. हर बार जुटने वाले श्रद्धालुओं के एक चौथाई भी इस अमावस्या में शामिल नहीं हुए. इसकी वजह 3 अक्तूबर को गुरुद्वारा कोड़ीवाला घाट से तीन किलोमीटर दूर तिकुनिया से बेलराया रोड पर किसानों और केंद्रीय गृह राज्य

प्रतिशोध लखीमपुर के तिकुनिया कस्बे में बेलराया रोड पर आक्रोशित किसानों ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्र की जीप जला दी

सभी फोटो: मनीष अग्निहोत्री

मंत्री अजय मिश्र 'टेनी' के पुत्र आशीष मिश्र के काफिले के बीच हिंसक टकराव थी जिसमें चार किसान समेत 8 लोग मारे गए. कृषि कानूनों और अजय मिश्र 'टेनी' की विवादास्पद टिप्पणी का विरोध कर रहे किसानों ने 3 अक्तूबर को तिकुनिया कस्बे के बाहर बने हेलीपैड पर कब्जा जमा लिया था. इस कारण उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहां हेलीपैड पर उतर कर अजय मिश्र 'टेनी' के गांव बनवीरपुर में दंगल की शुरुआत करने नहीं जा सके थे. इसी दौरान आशीष पर आरोप है कि उनकी कार ने किसानों को रौंदा जिसके बाद से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसान आक्रोशित हो गए. गुस्साए किसानों ने मंत्री के बेटे की गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा थी. लखीमपुर खीरी से करीब 100 किलोमीटर दूर तिकुनिया कस्बे की यह घटना आग की तरह फैल गई. देश भर में तिकुनिया की घटना के विरोध में प्रदर्शन होने लगे.

करीब पांच महीने बाद विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रही उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई. प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में धरने पर बैठ गए तो कृषि कानूनों की वापसी के लिए आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मृत किसानों के परिजनों से मिलने लखीमपुर खीरी पहुंच गए. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के यूपी विधानसभा चुनाव के प्रभारी भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया गया. कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह पर तीन-तीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए गए. प्रियंका गांधी 48 घंटे नजरबंद रहने के बाद राहुल गांधी के साथ लखीमपुर में तिकुनिया घटना में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने पहुंचीं.

तिकुनिया की घटना के बाद मचे सियासी घमासन को थामने के लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी. लखीमपुर खीरी में इंटरनेट को बंद कर दिया गया. जिले की ओर आने वाली हर सड़क को सील कर दिया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार को मौके पर भेजा. छह दौर की बातचीत के बाद प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हो गया. सरकार ने तिकुनिया में हुई हिंसा की जांच सेवानिवृत्त जज से कराने के साथ मारे गए किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए और नौकरी देने की घोषणा की. किसानों के दबाव के कारण केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू समेत 20 लोगों पर हत्या, गैर इरादतन हत्या, बलवा समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया. घटना के 24 घंटे के भीतर जिस तरह किसानों की मांगें मानकर आंदोलन खत्म हुआ उससे यह संकेत मिला कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी योगी सरकार किसी भी तरह का खतरा मोल लेने की हालत में नहीं है. पर अगले दिन जैसे ही आशीष मिश्र की गाड़ी से किसानों को कुचलने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ किसान संगठनों में उबाल आ गया. भाकियू के नेता आशीष की गिरफ्तारी के साथ मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं. सियासी घमासान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 अक्तूबर को अजय मिश्र को दिल्ली तलब किया और तिकुनिया की घटना पर उनका पक्ष जाना.

लखीमपुर खीरी: सियासी दांव

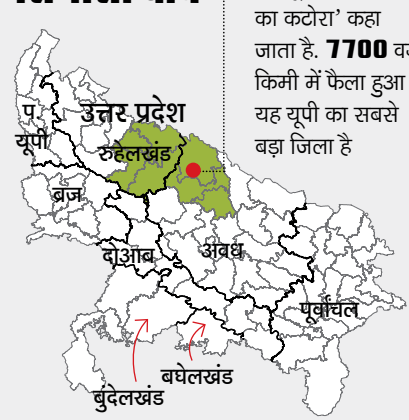

लखीमपुरखीरी को यूपी का 'चीनी का कटोरा' कहा जाता है. **7700** वर्ग किमी में फैला हुआ यह यूपी का सबसे बड़ा जिला है

● 36 विधानसभा सीटों वाले इस क्षेत्र में सियासी आंच लगनी लगभग तय है

80 प्रतिशत किसान चीनी की खेती करते हैं

भाजपा का गढ़ है लखीमपुर और आसपास का इलाका. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां की सात लोकसभा सीटों (रुहेलखंड की बरेली, आंवला, पीलीभीत, शाहजहांपुर और अवध की खीरी, धौरहरा, बहराइच लोकसभा सीट) की 36 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 32 और सपा ने 4 जीती थीं.

ब्राह्मण (12 प्रतिशत), कुर्मी (15 प्रतिशत) इन इलाकों की प्रमुख जातियां हैं. यहां पर सिखों की आबादी 4 प्रतिशत के करीब है. बड़े काश्तकार होने के कारण सिखों का प्रभाव दूसरी जातियों पर भी है.

नेपाल से सटा लखीमपुर खीरी 7,700 वर्ग किलोमीटर में फैला यूपी का सबसे बड़ा जिला है. यहां के 80 फीसद किसान गन्ने की खेती करते हैं और यहां पर नौ चीनी मिलें हैं. इसी वजह से लखीमपुर खीरी जिले को 'शुगर बाउल' भी कहते हैं. इस जिले में सिखों की आबादी कुल जनसंख्या का 2.6 प्रतिशत है. तिकुनिया की घटना के बाद से यूपी की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत राजनैतिक विश्लेषक देख रहे हैं. रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली में समाजशास्त्र विभाग के रिटायर्ड प्रोफेसर और लखीमपुर खीरी के रहने वाले देवीदयाल अवस्थी बताते हैं, ''तिकुनिया की घटना के बाद जिस तरह केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे की गाड़ी ने सिख किसानों को रौंदा उसके प्रतिक्रियास्वरूप दूसरी जातियों के

बातचीत

“तिकुनिया कांड के बाद भाजपा का समर्थन बढ़ गया है”

तिकुनिया कांड के बाद किसानों और विपक्षी दलों के निशाने पर आए लखीमपुर खीरी से सांसद और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री **अजय मिश्र ‘टेनी’** ने 5 अक्तूबर की दोपहर 12 बजे अपने संसदीय कार्यालय में *इंडिया टुडे* के एसोसिएट एडिटर **आशीष मिश्र** से बातचीत में अपना पक्ष रखा.

●तिकुनिया की घटना के जड़ में आपका एक विवादास्पद वीडियो है जिसमें आप किसानों को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं?

यह 25 सितंबर को संपूर्णानगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रांगण में आयोजित किसान गोष्ठी का वीडियो है. वहां कुछ अराजक तत्वों ने पोस्टर बैनर फाड़ दिए थे. मेरे वीडियो को काट-छांट कर पेश किया जा रहा है. मैंने कुछ गलत नहीं कहा था. मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भारतमाता और प्रधानमंत्री के पोस्टर फाड़ने वाले किसान नहीं हो सकते.

●तिकुनिया कांड के बाद से किसानों की भाजपा के प्रति नाराजगी बढ़ गई है?

लखीमपुर में जितने किसान हैं उसके पांच प्रतिशत भी कृषि कानूनों के विरोध में नहीं हैं. इसीलिए साजिश करने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था. तिकुनिया कांड के बाद भाजपा का समर्थन बढ़ गया है. लोगों को लगता है कि बाहर से लोग आकर जिले और प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं.

●आपकी आपराधिक छवि पर प्रश्न उठ रहे हैं. आपकी हिस्ट्रीशीट भी खुली थी?

मेरे खिलाफ साजिश कर हिस्ट्रीशीट खोली गई थी. हाइकोर्ट ने आदेश पर मेरे सारे मुकदमे वापस लिए गए. यह मेरी उपलब्धि है कि मैं न कभी थाने में बंद हुआ हूं और न ही कभी जेल गया हूं.

●आप रुहेलखंड इलाके में भाजपा के ब्राह्मण चेहरा बने हैं. लखीमपुर खीरी की घटना के बाद ब्राह्मण और सिख आमने-सामने आ गए हैं?

मैं ब्राह्मण चेहरा नहीं बल्कि जनता का चेहरा हूं. मुझे सभी लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है कि अभी चुनाव हो जाएं तो मेरे वोट पिछली बार की तुलना में दोगुने हो जाएंगे.

● आप अपने बेटे आशीष मिश्र को निघासन सीट से अगला विधानसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं?

मेरा पूरा परिवार भाजपा का कार्यकर्ता है. अगर पार्टी कहेगी तभी आशीष चुनाव लड़ेंगे.

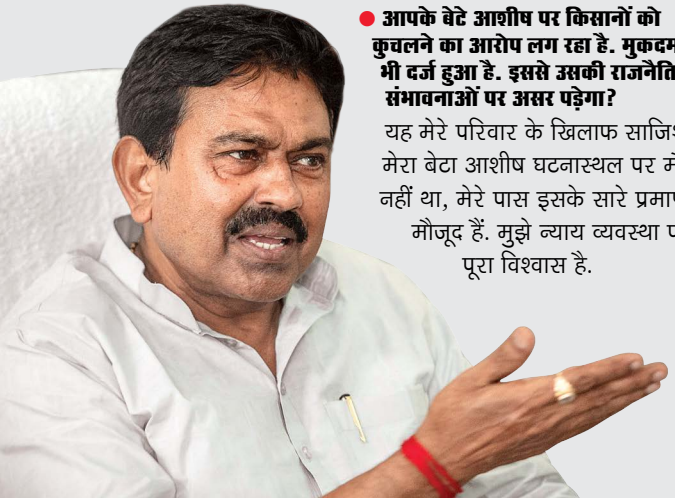

● आपके बेटे आशीष पर किसानों को कुचलने का आरोप लग रहा है. मुकदमा भी दर्ज हुआ है. इससे उसकी राजनैतिक संभावनाओं पर असर पड़ेगा?

यह मेरे परिवार के खिलाफ साजिश है. मेरा बेटा आशीष घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, मेरे पास इसके सारे प्रमाण मौजूद हैं. मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है.

गन्ना भुगतान न होने से भी नाराजगी

अक्तूबर में नए पेराई सत्र के आगाज के बीच किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान का मुद्दा भी गरम है. निजी चीनी मिलें ही नहीं, सहकारी चीनी मिलें भी किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान का पैसा नहीं दे पा रही हैं. यूपी के तराई इलाके में ‘चीनी का कटोरा’ नाम से मशहूर लखीमपुर खीरी जिले में कुल नौ चीनी मिले हैं. इनमें दो सहकारी चीनी मिलें हैं. इन चीनी मिलों को पांच लाख से ज्यादा

लोगों को मारा गया. इससे हिंदू और सिख आमने सामने आ गए हैं. वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समर्थक वोटबैंक में दरार पड़ना भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं है.’’ रुहेलखंड और लखीमपुर खीरी के आसपास की 36 विधानसभा सीटों में प्रत्येक में पिछड़ी जाति कुर्मी की आबादी कुल जनसंख्या का 15 प्रतिशत से अधिक है और अगड़ी जातियों में ब्राह्मण की आबादी भी 12 प्रतिशत से अधिक है. सिखों की आबादी करीब 4 प्रतिशत है, लेकिन बड़े काश्तकार होने के कारण दूसरी जातियों में इनका काफी प्रभाव है. अब भाजपा के सामने इन तीन जातियों में संतुलन बिठाने की चुनौती है. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में हिंदू और सिख मतदाताओं का एकतरफा समर्थन भाजपा को मिला था. यही वजह है कि रुहेलखंड की चार लोकसभा सीटों बरेली, पीलीभीत, आंवला, शाहजहांपुर और अवध इलाके की खीरी, घौरहरा, सीतापुर लोकसभा सीटों के तहत आने वाली कुल 36 विधानसभा सीटों में भाजपा ने 32 तथा सपा ने चार सीटें जीती थीं. बाकी किसी पार्टी का खाता ही नहीं खुला था.

अजय मिश्र 1996 में राजनीति में आए जब वह युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में शामिल हुए. 1998 में वे लखीमपुर खीरी के जिला सहकारी बैंक के निर्विरोध संचालक और उपाध्यक्ष चुने गए. 2005 में उन्होंने लखीमपुर खीरी के जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता. 2007 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर निघासन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और 1008 वोटों के करीबी अंतर से हारे. करीबी अंतर से हारने का सिलसिला वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा. 2009 के लोकसभा चुनाव में खीरी सीट से अजय मिश्र 18,000 वोटों से चुनाव हारे. हार का सिलसिला वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में टूटा और 32,000 वोटों से जीत कर वे निघासन सीट से विधायक बने. दो साल बाद वे 2014 के लोकसभा चुनाव में खीरी सीट से भाजपा के टिकट पर जीतकर सांसद बने. 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दोबारा जीत दर्ज

किसान गन्ना आपूर्ति करते हैं. लखीमपुर की निघासन तहसील के उमरा गांव के रहने वाले शत्रुघ्न पटेल का दो लाख रुपए का गन्ना भुगतान बेलरायां चीनी मिल पर बकाया है. वे बताते हैं, ''नियम है कि गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के अंदर किसानों के खातों में भुगतान पहुंच जाएगा पर ऐसा नहीं हो रहा है.'' हालात यह है कि जिले की चीनी मिलों पर किसानों का अभी भी करीब दस अरब रुपया बकाया है. किसान भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. अगर सहकारी चीनी मिलों की बात करें तो सहकारी चीनी मिल संपूर्णानगर पर किसानों का 82 करोड़ 48 लाख रुपया बकाया है. जबकि बेलरायां चीनी मिल पर किसानों का 53 करोड़ 11 लाख रुपया अभी भी बकाया है. निजी चीनी मिलों पर भुगतान कराने के लिए सरकार दबाव बना रही है पर सहकारी चीनी मिलों का भुगतान कराने पर उसका ध्यान नहीं है. बेलरायां चीनी मिल के जनरल मैनेजर राहुल यादव बताते हैं, ''चीनी मिल पहले से घाटे में हैं. इस बार देर तक चीनी मिल चली. बजट की कमी से किसानों के भुगतान में देर हो गयी. जल्द ही किसानों को पैसा दे दिया जाएगा.'' लखीमपुर के जिला गन्ना अधिकारी बृजेश पटेल बताते हैं, ''जिले की चीनी मिलों पर किसानों का कुल 999 करोड़ रु. बकाया है. उसके भुगतान को लेकर चीनी मिलों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है. सहकारी चीनी मिलों को सरकार की ओर से बजट मिला है. जल्द ही भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.'' किसानों के दावों के उलट यूपी में गन्ना विभाग के मंत्री सुरेश राणा के अनुसार, गन्ना किसानों को सरकार की नीतियों से लाभ पहुंचा है. वे कहते हैं, ''प्रदेश की चीनी मिलों पर 25 सितंबर तक कुल देय गन्ना मूल्य 33,014 करोड़ रु. के सापेक्ष 28,015 करोड़ रु. का भुगतान हो चुका है जो कुल देय का 85 फीसद है.''

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्र जिन पर किसानों को गाड़ी से रौंदने का आरोप है

लखीमपुर खीरी जाने से रोके जाने पर 4 अक्तूबर को अखिलेश यादव लखनऊ में सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे

की. रुहेलखंड इलाके में ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में अजय मिश्र को बतौर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री शामिल किया था. केंद्रीय राज्यमंत्री बनने के बाद अजय मिश्र आर्शीवाद यात्रा निकालकर रुहेलखंड और आसपास के जिलों में तीन दर्जन से अधिक सभाएं कर ब्राह्मण वोटरों और किसानों को भाजपा से जोड़ने की कोशिश में लग गए थे. इसी क्रम में 25 सितंबर को लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील के संपूर्णानगर में एक किसान गोष्ठी में वे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे. इस कार्यक्रम में उनके भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ जिसमें वह किसानों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, ''आओ मेरा सामना करो, मैं तुम्हें सुधार दूंगा.'' मिश्र के इस बयान के बाद से किसान आक्रोशित थे और वे 3 अक्तूबर को तिकुनिया में उपमुख्यमंत्री के सामने अपना विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे.

तिकुनिया की घटना के बाद किसानों के बीच असंतोष से अजय मिश्र और इनके बेटे आशीष मिश्र के सियासी भविष्य पर संकट मंडरा रहा है. आशीष मिश्र ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में निघासन सीट पर भाजपा से टिकट के लिए दावेदारी पेश की थी. भाजपा ने आशीष की दावेदारी दरकिनार कर कुर्मी नेता रामकुमार पटेल को टिकट दिया था. पटेल ने 46 हजार वोटों से चुनाव जीता था. 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आशीष मिश्र एक बार फिर निघासन से भाजपा उम्मीदवार के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे थे. विधानपरिषद सदस्य और जनसंपर्क यात्रा के जरिए रुहेलखंड में सपा का जनाधार बढ़ाने में जुटे आनंद भदौरिया कहते हैं, ''अजय मिश्र और इनके बेटे आशीष मिश्र की छवि पूरे इलाके में दागदार है. अजय मिश्र हिस्ट्रीशीटर रहे हैं. जनता को अब इनकी असलियत पता चल गई है.'' सियासी विश्लेषकों का मानना है कि ब्राह्मण वोटों की चाह में अजय मिश्र को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री का पद देने का भाजपा का दांव उल्टा पड़ गया है. चुनाव से पहले इसका डैमेज कंट्रोल करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा.

तिकुनिया कांड के बाद उपजी किसानों की नाराजगी को खत्म कर पाना भी आसान नहीं होगा. भाकियू के अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा बताते हैं, ''लखीमपुर खीरी जिला कृषि कानून विरोधी आंदोलन का गढ़ बनता जा रहा है. इस जिले के पलिया, निघासन, संपूर्णानगर समेत कई इलाकों से किसान जनवरी में दिल्ली में आयोजित रैली में डेढ़ सौ से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे. सितंबर में मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत में लखीमपुर खीरी के किसान बड़ी संख्या में मौजूद थे.''

भाकियू लखीमपुर के जरिए किसान आंदोलन को पूर्वी यूपी में मजबूत करना चाहता है. इसके लिए वह पूर्वी यूपी के ब्लॉक में किसान चौपाल लगाकर तिकुनिया कांड में भाजपा नेताओं की बर्बरता उजागर करने की रणनीति बना रहा है. इस तरह तिकुनिया कांड ने यूपी की राजनीति में नए समीकरण बनने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है. ■

हेरोइन ने अब मचाया हाहाकार

दक्षिण अफगानिस्तान के अफीम के खेतों से भारत की सड़कों तक, अफगान-पाकिस्तान से हेरोइन की खेपों की एकाएक तेज हुई आवक ने भारत में मादक द्रव्यों की पहेली को और जटिल कर दिया

संदीप उन्नीथन

फोटो इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

श के सबसे बड़े समुद्री बंदरगाह

मुंद्रा में बड़े करीने से सजाए हजारों कंटेनरों के बीच ईरान से आए दो जंग खाए धूसर भूरे रंग के कंटेनर भी दबे थे. शिपमेंट पर नजर रखने वाले राजस्व खुफिया विभाग (डीआरआइ) के अधिकारियों के मुताबिक विशाल भंडार में ये दो कंटेनर गैरजरूरी थे. ये 20 फुट ऊंचे कंटेनर ईरान बंदर अब्बास से आए और गुजरात के कच्छ जिले में भेजे गए जो कि भूसे के ढेर में सूई की तरह थे. हर साल 56 लाख ऐसे कंटेनर बंदरगाह पर आते हैं. लेकिन इसे भेजने वाले के नाम से अधिकारियों की दिलचस्पी जगी. यह थी दक्षिण अफगानिस्तान के कंधार में स्थित फर्म हसन हुसैन लिमिटेड. कॉस्मेटिक्स बनाने का कच्चा माल टेल्क स्टोन का शिपमेंट आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के लिए भेजा जाना था और वहां से यह चेन्नै में रहने वाले दंपति मचवरम सुधाकर और वैशाली के पास पहुंचना था. डीआरआइ के दल ने 15 सितंबर को कंटेनरों को खोला तो सैकड़ों सफेद रंग के सिंथेटिक बैग मिले, इनमें हरेक इतने बड़े थे कि कोई बड़ा आदमी उस पर बैठ सकता है. टेल्क स्टोन के नीचे तीन टन शुद्ध अफगान हेरोइन थी. यह देश में पकड़ी गई ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप थी. एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, यह मुंबई के 1.2 करोड़ लोगों को नशे में धुत होने के लिए काफी है. अगर इसे न्यूयॉर्क की गलियों में बेचा जाए तो 2 अरब डॉलर या 15,000 करोड़ रु. हासिल किए जा सकते हैं. यह इतना था, जितना सरकारी एजेंसियों ने 2019 से 31 अगस्त, 2021 तक जब्त किया. 31 अगस्त, 2021 की तारीख तक इस बरामदगी की तुलना साल 2019 और 2020 में क्रमश: 3.2 टन और 3.8 टन की बरामदगी से की जा सकती है.

मुंद्रा शिपमेंट से देश के सुरक्षा प्रतिष्ठान के कान खड़े हो गए. इससे देश के ड्रग कंट्रोल अधिकारियों की सबसे बुरी आशंकाएं सही साबित हो गईं कि अफगान हेरोइन की बाढ़ सूनामी बनती जा रही है. यह उस देश के लिए अच्छी खबर नहीं है, जहां नशीले पदार्थों का इस्तेमाल 2.06 फीसद है, यानी दुनिया भर की औसत 0.7 फीसद से तीन गुना है. यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अफीम का नशा करने वालों का प्रतिशत 2.06 है जो वैश्विक औसत 0.7 प्रतिशत से तीन गुना है

की 'देश में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल का पैमाना' शीर्षक 2019 की रिपोर्ट का नतीजा है. देश में नशीले पदार्थ कानून पर अमल की नोडल एजेंसी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान कहते हैं, ''भारत भारी खपत, बिक्री और सप्लाइ रूट है.'' (देखें बातचीत)

सामाजिक न्याय मंत्रालय की अपनी तरह की पहली 2019 की रिपोर्ट आकलन करती है कि भारत में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग कितना बड़ा है. उसके मुताबिक, करीब 5 करोड़ लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं. प्रधान कहते हैं, ''यह विशाल बाजार है और तेजी से फैल रहा है. यह किसी ड्रग सप्लायर के स्वर्ग की तरह है.''

आपूर्ति में तेजी

मुंद्रा में पकड़ा गया हेरोइन अफगानिस्तान से पहुंचा था. यानी हजारों किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम से, जिस इलाके को ड्रग कंट्रोल एजेंसियां अपने शब्दों में गोल्डन क्रेसेंट या 'स्वर्णिम अर्द्धचंद्र' कहती हैं. अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के इसी गलियारे से दुनिया भर में 83 फीसद अफीम का उत्पादन और वितरण होता है. यह चिपचिपा गहरे भूरे रंग का पदार्थ अफीम के पौधों के फूल से निकलता है, फिर ड्रग लैब में परिष्कृत करके पहले उसे अफीम बनाया जाता है और फिर उससे झक सफेद पाउडर बनाया जाता है, जिसे हेरोइन कहा जाता है. यह पाउडर पैकेटबंद करके यूरोप, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के जरिए दुनिया भर के अनुमानित 5.78 करोड़ नशेड़ियों की नसों और सांस तंत्र में पहुंचाया जाता है. अफगानिस्तान से निकलते वक्त हेरोइन की कीमत 10,000 रु. प्रति किलो होती है. मुंबई पहुंचने पर कीमत 50 लाख रु. हो जाती है. आधी दुनिया पार कर जाइए तो न्यूयॉर्क की गलियों में उतनी ही मात्रा काफी मिलावट के साथ 1,33,000 डॉलर या 1 करोड़ रु. में मिलती है. इसी वजह से ड्रग्स या नशीले पदार्थों का कारोबार इस कदर मुनाफा देने वाला है.

1980 के दशक में सोवियत संघ के अफगानिस्तान में दखल से बाल्कन वाला रूट बंद हो गया और हेरोइन मुंबई और दिल्ली की सड़कों पर दिखने लगी जो कि बाद में दो सबसे बड़े खपत केंद्र बने. इसका बहुत ज्यादा मिलावटी रूप 'ब्राउन शुगर' या 'स्मैक' के

‘आकर्षण की बड़ी वजह यहां के 5 करोड़ नशेड़ी’

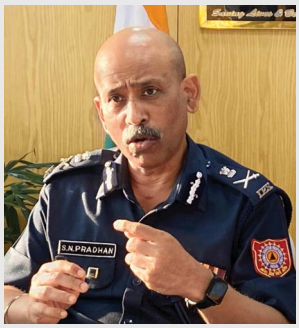

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक **सत्य नारायण प्रधान** ने हाल ही में मुंद्रा बंदरगाह जैसी नशीले पदार्थों की बड़ी बरामदगी से उजागर खतरे, अफगानिस्तान में अफीम की पैदावार में आई उछाल के भयावह नतीजों और नामी-गिरामी दौलतमंदों के बीच ड्रग की व्यापक स्वीकृति के बारे में ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर (पब्लिशिंग) **राज चेंगप्पा** और मैनेजिंग एडिटर **संदीप उन्नीथन** के साथ बातचीत की. पेश हैं उसी के कुछ चुनिंदा अंश:

● अफगानिस्तान में अफीम की पैदावार में आई उछाल आखिर कितनी चिंताजनक है?

अफगानिस्तान में अफीम की पैदावार तालिबान के वहां कब्जा करने के पहले से ही बढ़ रही थी. 2019-20 में अफीम की खेती के तहत आने वाली जमीन में 37 फीसद की बढ़ोतरी हुई और पूरे 2,24,000 हेक्टेयर इलाके में इसकी खेती होने लगी. यह अभी तक की सबसे ज्यादा है. दुनिया की यही कोई 83 फीसद अफीम अफगानिस्तान में ही उगाई जाती है. साल-दर-साल इसमें बढ़ोतरी होती गई. मादक द्रव्य एक तो अफगानिस्तान और दूसरे ईरानी समुद्रतट के बंदरगाह से होकर आती है. यहां तक कि इन मादक पदार्थों को ठेल भले ही अफगानी रहे हों पर वे इसके लिए गठजोड़ पाकिस्तानियों से ही करते हैं. पाकिस्तानी ही हैं जो नशीले पदार्थों की तस्करी के इस तंत्र को खाद-पानी दे रहे हैं.

● मुंद्रा में जितनी बड़ी खेप मिली है, उसे लेकर किस तरह की चिंताएं हैं? ऐसा दोबारा होने से रोकने के लिए क्या किया जा रहा है?

परेशान होने वाली बात यह है कि मुमकिन है, ऐसी खेपें पहले भी कई बार आई हों और हमें इसकी खबर न लग पाई हो. 30 किलो से सीधे 3 टन की खेप (शिपमेंट). ऐसा उछाल अचानक नहीं आया. यह कई बार हुआ होगा. उन्होंने कई बार 1,000 किलो या शायद 4,000 किलो की खेप भी भेजी होंगी. हमने ऐसे शिपमेंट का पता लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल बढ़ाया है.

● नशीले पदार्थों की यह विशाल आवक भारत के लिए आखिर किस तरह की चुनौतियां लेकर आती है?

समस्या के तीन पहलू हैं—सप्लाइ, पारगमन और उपभोक्ता. भारत में तीनों हैं—हमारे यहां बड़े पैमाने पर उसका उपभोग हो रहा है, हम पारगमन स्थल हैं और हम सप्लाइ रूट भी हैं. हमारे यहां पांच करोड़ से ज्यादा सेवन करने वाले हैं जो आदतन इस पर निर्भर हैं. यह बड़ा बाजार है और बढ़ रहा है. किसी भी ड्रग पेडलर के लिए स्वाभाविक रूप से यह बड़ा आकर्षण है.

● सुशांत सिंह राजपूत के मामले और क्रूज लाइनर वाले मामले में कोई समानता आप देखते हैं?

वे इस हकीकत की ओर इशारा करते हैं कि नौजवान अब शराब से अलहदा किस्म के रोमांच की तरफ बढ़ रहे हैं. यह ठोस किस्म का बदलाव है. नई पीढ़ी की नजर में, अगर आप किसी किस्म की ड्रग नहीं लेते, तो आप ‘नए चलन’ वाले नहीं हैं. उन पर संगी-साथियों का दबाव होता है और कई बार नशे की अपनी ही तलब मिटाने के लिए इसके उपभोक्ता छोटे-मोटे विक्रेता बन जाते हैं.

● महामारी के बाद ड्रग की तस्करी में नए रुझान क्या हैं?

ड्रग तस्कर नशीले पदार्थों की डिलिवरी के लिए कूरियर एजेंसियों का और लेन-देन के लिए डार्कनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं. फरवरी 2020 और कूरियर बूम के बाद कूरियर के जरिए नशीले पदार्थों की डिलिवरी आसमान पर पहुंच गई है. कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए छोटे-छोटे पैकेट की सामग्री को खोजना और पता लगा पाना मुमकिन नहीं. हम तस्करी के पारंपरिक आपूर्ति मार्गों को दक्षिण की ओर राजस्थान और गुजरात की तरफ खिसकते भी देख रहे हैं.■

रूप में बिकने लगा. 1990 के आसपास सुस्त पड़ने के बाद स्मैक पिछले पांच सालों में फिर से दिखने लगी है. मुंबई पुलिस में ऐंटी नार्कोटिक्स सेल के डीसीपी दत्ता नलवाडे कहते हैं, ‘‘ज्यादा लोग सस्ती हेरोइन (स्मैक) के आदी हैं जो 1,500 रुपए प्रति ग्राम के भाव पर मिलती है.’’ दिल्ली में स्मैक की एक खुराक 300 रु. तक की सस्ती दर पर उपलब्ध है. सप्लाइ में उतार-चढ़ाव को बेकिंग सोडा की मिलावट से पूरा किया जाता है. नशेड़ियों से संबद्ध एक वॉलंटियर का कहना है, ‘‘उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ रही है, यह आसानी से उपलब्ध है जिसका मतलब है बाजार में नशीले पदार्थ की बाढ़ है.’’

ड्रग्स की तस्करी सीमाओं से होती है. अफीम की तस्करी भारत और पाकिस्तान की सीमा से होती है, गांजा भारत-नेपाल के रास्ते तो एंफेटामाइन टाइप स्टीमुलेंट (एटीएस), मेथमफेटामाइन और हेरोइन भारत-म्यांमार के रास्ते आती है.

देश में अवैध नशीले पदार्थों के धंधे के पैमाने के बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है. एक सरकारी एजेंसी का अनुमान करीब 30,000 करोड़ रु. का है (इसका हिसाब यह है कि सालाना करीब 3,000 करोड़ रु. की जब्ती होती है और उसे सिर्फ 10 फीसद ही माना जाता है). यह धंधा इतना मुनाफे वाला है कि ड्रग कार्टेल कानून से एक कदम आगे रहने और अपना जानलेवा धंधा जारी रखने के तरीके निकाल लेते हैं. एनसीबी के अधिकारियों के मुताबिक, ड्रग तस्कर सौदेबाजी में डार्कनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो इंटरनेट सर्च इंजन पकड़ नहीं पाते. यूएनओडीसी (संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय) की 2019 की एक रिपोर्ट में एक अध्ययन का हवाला दिया गया कि भारत से 1,000 से ज्यादा ड्रग लिस्टिंग 50 क्रिप्टो-मार्केट प्लेटफॉर्म पर डाली गई. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि डार्कनेट पर बड़े ड्रग मार्केट अब सालाना 31.5 करोड़ डॉलर (2,300 करोड़ रु.) का है. तस्कर अब अपने उपभोक्ताओं तक छोटे-छोटे पैकेट कूरियर कंपनियों के जरिए पहुंचाते हैं. एनसीबी ने अगस्त में कोलकाता के एक ड्रग तस्करी नेटवर्क को पकड़ा, जो उच्च ग्रेड का गांजा डार्क वेब के जरिए दुनिया भर में पहुंचा रहा था.

यूएनओडीसी की जून 2021 की रिपोर्ट से पता चलता है कि महामारी से तस्करी

सुनहरे चांद का फिर बना रास्ता

भारत अब अवैध अफीम का बड़ा बाजार और इधर से उधर पहुंचाने का बड़ा केंद्र बन गया है. हमारे युवाओं में नशा काफी उफान पर पहुंच गया है

मादक द्रव्यों की तस्करी जोरों पर

दुनिया भर में उत्पादन
(2020 में; टन में)

7,410
अफीम पैदा हुई

1,205-1,512
अफीम के रूप में सेवन

454-694
अफीम से हेरोइन बनाई गई

दुनिया भर में जब्त मादक द्रव्य
(2019 में; टन में)

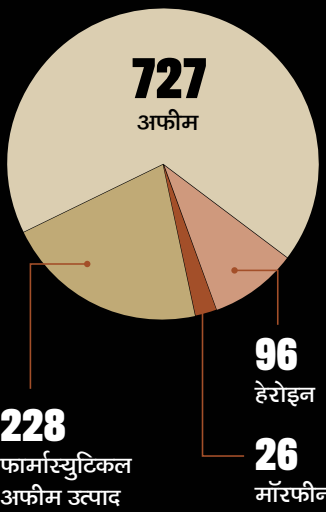

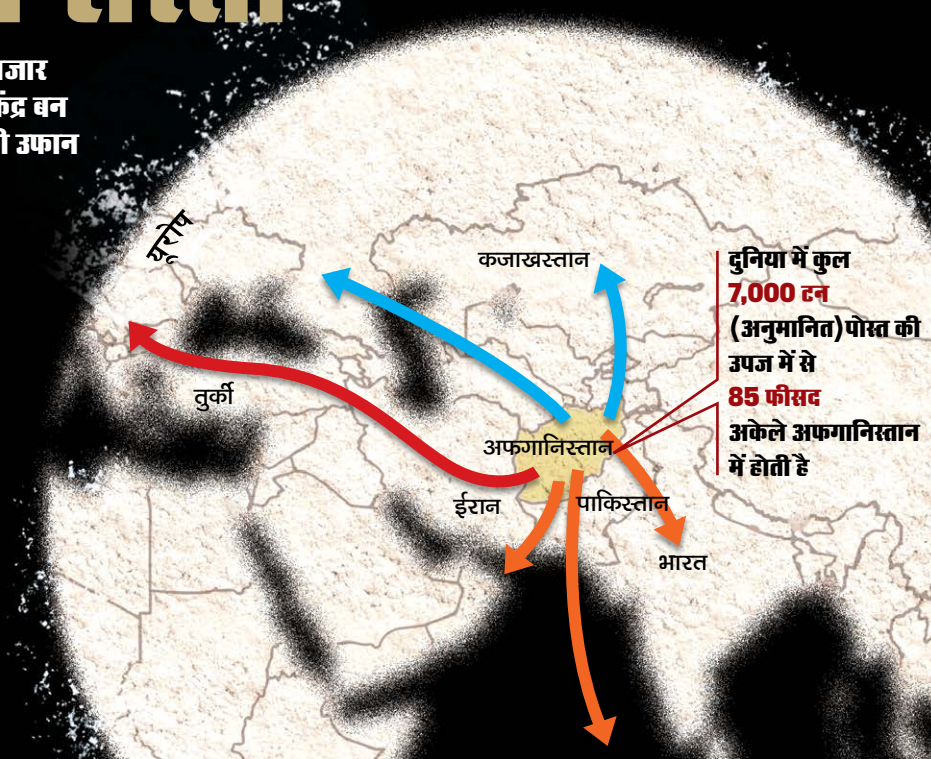

स्रोतः यूएनओडीसी; समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय

ग्राफिक: तन्मय चक्रवर्ती

भारत में बढ़ती बरामदगी

सभी एजेंसियों की ओर से की गई मादक द्रव्यों की बड़ी बरामदगियां

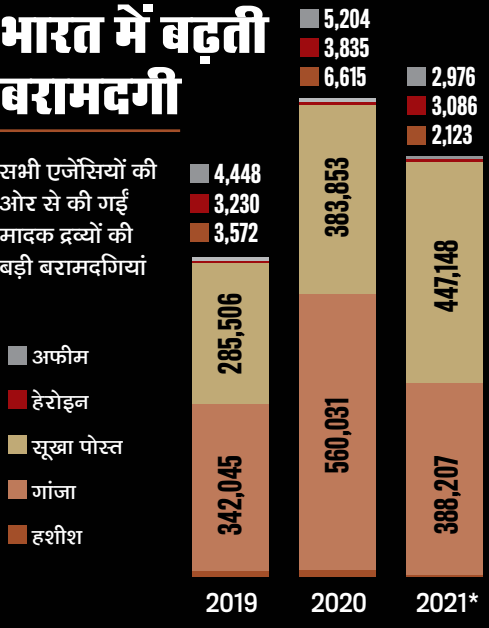

31 अगस्त तक

पंजाब की सीमा पर हुई मादक द्रव्यों की खेप की जब्ती

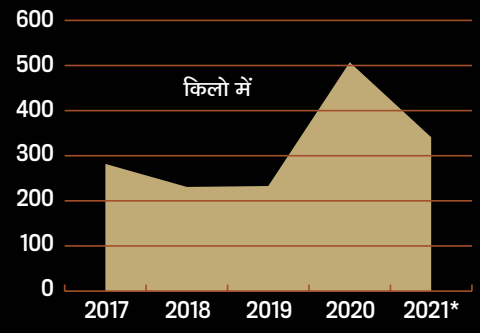

20 सितंबर तक

अलग-अलग उम्र वालों में नशे का चलन

भारत में नशा करने वालों की अनुमानित संख्या (लाख में)

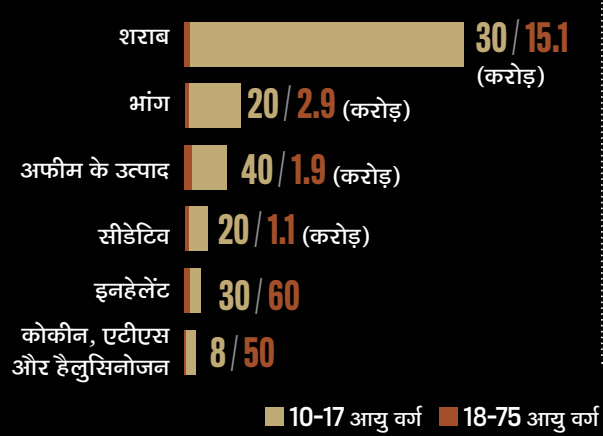

घातक चुनौती

अफीम के उत्पाद

- 1.14% भारतीय हेरोइन के आदी हैं, 0.96% अफीम से बने फार्मास्युटिकल्स उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं और 0.52% अफीम का
- 60 लाख लोगों को अफीम उत्पादों के उपयोग की बीमारी
- देश में अफीम उत्पाद के आदियों की आधी संख्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात के
- प्रभावित आबादी के प्रतिशत के हिसाब से राज्य: मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली

2.3 करोड़ नशा करने वालों की कुल संख्या

77 लाख के लिए अब यह समस्या बन गया

28 लाख जो इस पर निर्भर हो चुके

मादक द्रव्य पहुंचाने के नए तरीके

कोविड के बाद के दिनों में ड्रग तस्करी के नए चलन

जितना चौकन्ना शहर, उतनी ही ज्यादा चिंता

सेलेब्रिटी और नशीले पदार्थों के रिश्ते का भंडाफोड़ और अंतरराष्ट्रीय तस्करी का सुचारु नेटवर्क मुंबई की एक बढ़ती समस्या सामने लाया

एएनआइ

अक्तूबर की 2 तारीख को करीब 1,000 मेहमान कॉर्डेलिया क्रूजेज कंपनी के गोवा रवाना हो रहे जहाज पर सवार होने ही जा रहे थे कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई के अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर छापा मारा. ज्यादातर मेहमान उत्तर भारतीय राज्यों के थे, जिन्हें दिल्ली की एक कंपनी लेकर आई थी. टिकट 80,000 से 3 लाख रुपए के बीच थे. जहाज अंतरराष्ट्रीय सफर के अपने तीसरे पड़ाव पर था.

एक ड्रग पेडलर से जहाज में रेव पार्टी का सुराग मिलने पर एनसीबी के अफसर जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुआई में मेहमान बनकर क्रूज पर सवार हो गए. तलाशी के दौरान उन्होंने आठ लोगों को दबोचा. इनमें बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के 23 वर्षीय बेटे आर्यन खान, उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा भी थे. एजेंसी को आर्यन के कब्जे से ड्रग तो नहीं मिली, पर वह उसके नशे में होने का दावा कर रही है. क्रूज कंपनी ने आर्यन और अरबाज को मुफ्त वीआइपी पास दिए थे, इस उम्मीद से कि वे पार्टी की चर्चा को हवा देंगे.

एनसीबी ने 5 अक्तूबर तक इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया. इनमें इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़े चार लोग भी हैं. आर्यन और उसके दोस्तों पर मादक पदार्थ और मनप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) कानून की धारा 27 (मादक पदार्थ या मनप्रभावी पदार्थ का सेवन), 8सी (मादक पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, रखना, बेचना या खरीदना) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. एनसीबी दावा कर रही है कि उसने आर्यन के कुछ दोस्तों से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी (मेफेड्रोन), 21 ग्राम चरस और

मुंबई पुलिस की नार्कोटिक्स इकाई के एक अफसर का दावा है कि शहर में हर महीने 500 किलो गांजे की खपत होती है. और यहां अवैध मादक द्रव्यों का कारोबार 500 करोड़ रु. सालाना का है

नेटवर्क उबर गया है और अब सप्लाइ के लिए बिना संपर्क वाला तरीका निकाल लिया गया है, ड्रग की बड़ी खेप समुद्री रास्ते और निजी विमान से भेजी जा रही है. ऑनलाइन बिक्री ने ड्रग की पहुंच इतनी आसान बना दी है, जो पहले नहीं देखी गई. केंद्र सरकार के अधिकारी बताते हैं कि दक्षिण एशिया में ड्रग तस्कर लेन-देन का ठिकाना समुद्र में बनाते हैं, जो देशों की सीमा के बाहर और कानूनी एजेंसियों के दायरे से बाहर होती है.

देश के सामाजिक तानेबाने को तार-तार करने के अलावा ये ड्रग शिपमेंट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मानते हैं कि हेरोइन की ऐसी बड़ी खेप का आना पाकिस्तान के डीप स्टेट की सांठगांठ के बिना संभव नहीं है. ज्युरिख के ईटीएच में सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज के वरिष्ठ शोधार्थी प्रेम महादेवन कहते हैं, ''ड्रग अब पेट्रोलियम की तरह है, उससे गोला-बारूद से लेकर आतंकवाद और मानव तस्करी सब आसान हो जाती है.'' उनका मानना है कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र से ड्रग के प्रवाह में भारत को मोहरा बनाने की कई वजहें हैं. वे कहते हैं, ''ड्रग्स लंबे समय से पाकिस्तानी आइएसआइ का छद्म युद्ध का औजार रहा है. ड्रग तस्करी को राह भारत के सीमा सुरक्षा तंत्र से मिलती है और छद्म युद्ध के लिए फंड भी हासिल होता है. भारत का पंजाब सूबा पहले और अब भी आइएसआइ की नापाक गतिविधियों का केंद्र है, क्योंकि यह रणनीतिक रूप से खास है.''

इसलिए सरकार ने समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करने वाले नार्कोटिक्स तस्करों पर नजर रखने के लिए नौसेना और कोस्ट गार्ड को भी जोड़ा है. नौसेना खासकर अरब सागर और हिंद महासागर में बड़े जहाजों के आवागमन पर नजर रखने के काबिल है. नौसेना एक प्रवक्ता ने बताया कि कैसे संदिग्ध गतिविधि वाले जहाजों पर नजर रखी जा रही है. वे कहते हैं, ''हमारे युद्धपोत अब हिंद महासागर के विभिन्न ठिकानों पर तैनात हैं इसलिए हम संदिग्ध गतिविधियों पर तेजी से नजर रखकर जवाब दे सकते हैं.''

इस साल 19 अप्रैल को नौसेना के युद्धपोत *आइएनएस सुवर्णा* ने श्रीलंका के फिशिंग ट्रॉलर *शेनया दुवा* को पकड़ा और कोच्चि तट से 3,000 करोड़ रु. की 300 किलो हेरोइन जब्त की. अफगानी हेरोइन 'दक्षिणी रूट' से लाई गई और ट्रॉलर पर पांच श्रीलंकाइयों ने उसे हासिल किया. उसके पहले 18 मार्च को कोस्ट गार्ड ने केरल तट से आगे लक्षद्वीप के पास से 300 किलो हेरोइन तीन श्रीलंकाई ट्रॉलर से पकड़ी.

बड़े पैमाने पर बरामदगी के बावजूद,

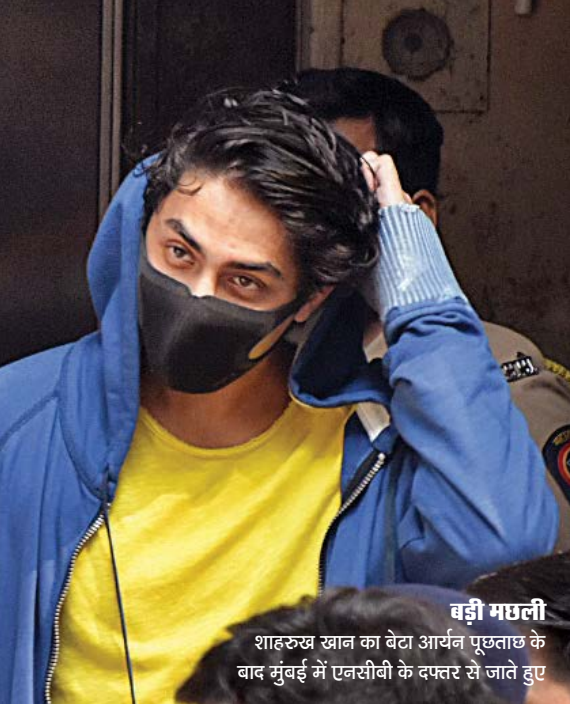

बड़ी मछली
शाहरुख खान का बेटा आर्यन पूछताछ के बाद मुंबई में एनसीबी के दफ्तर से जाते हुए

सुशांत सिंह राजपूत की खुदकशी के बाद मुंबई के नामी और रसूखदार लोगों के ड्रग लेने पर ध्यान गया था. अभिनेता के फोन रिकॉर्ड से पता चला कि वह कई ड्रग पेडलर के संपर्क में था. 2 अक्तूबर की गिरफ्तारियां इशारा करती लगती हैं कि नशीले पदार्थ मुंबई में अब भी आसानी से मिल रहे हैं. राजपूत के मामले के बाद एनसीबी ने कई नामी-गिरामी लोगों को गिरफ्तार किया था. हाल में उसने इस मामले में 50,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जो बॉलीवुड अदाकारों, उनके दोस्तों और ड्रग पेडलरों के बीच नापाक सांठगांठ की झांकी पेश करती है.

मुंबई पुलिस की नार्कोटिक्स शाखा के एक अफसर दावा करते हैं कि शहर में हर महीने 500 किलो गांजे की खपत होती है. गैरकानूनी नशीले पदार्थों का कुल बाजार सालाना 500 करोड़ रुपए का बताया जाता है. मुंबई नशीले पदार्थों के उतरने का सुरक्षित ठिकाना माना जाता है. इसमें राजनैतिक संरक्षण भी जोड़ लें तो यह शहर ड्रग कारोबारियों के लिए खास आकर्षण रहा है.

सितंबर 2020 के बाद एनसीबी ने नशीले पदार्थों के सेवन और बिक्री के लिए एनडीपीएस कानून के तहत 114 मामले दर्ज किए और 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 34 विदेशी और कुछ बॉलीवुड सितारे भी हैं. एनसीबी दावा करती है कि उसने अब तक 12 ड्रग सिंडिकेट खत्म किए हैं और मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से 150 करोड़ रुपए की ड्रग बरामद की हैं. मुंबई के नामी-गिरामी और रसूखदार लोग नशीले पदार्थों की मांग और ऊंची खुदरा कीमतें बढ़ाते रहते हैं. पुलिस अफसर कहते हैं कि मुंबई में एक ग्राम कोकीन की कीमत 5,000 रुपए है, जो गोवा से करीब दोगुनी है. एनसीबी का रिकॉर्ड कहता है कि बीते दो सालों में श्रीलंका, पोर्ट एलिजाबेथ और पनामा से पकड़ी गई कम से कम 2,499 किलो कोकीन भारत आने वाली थी. रिकॉर्ड यह भी कहता है कि दिसंबर 2018 में करीब 300 किलो कोकीन एक सिंडिकेट के जरिए मुंबई आई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक किलो कोकीन 5 करोड़ रुपए में जाती है.

सत्तारूढ़ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार की घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक का आरोप है कि एनसीबी केवल गैर-भाजपा शासित राज्यों को निशाना बना रही है. पर वानखेड़े स्पष्ट करते हैं: ''हमारा मुख्य उद्देश्य संगठित ड्रग सिंडीकेटों को तहस-नहस करना है. बस.''

—किरण डी. तारे

एमडीएमए (मेथीलीनडायोक्सी-मेथम्फेटामाइन को मिलाकर बनाई गई ड्रग) की 22 गोलियां बरामद कीं. आरोप साबित होने पर उन्हें साल भर की जेल हो सकती है. एनसीबी के एक अफसर कहते हैं, ''आर्यन हमारे लिए सरप्राइज कैच था. जब हमने उसे दबोचा, हमें नहीं पता था कि वह एसआरके का बेटा है.'' खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने इन रिपोर्टों का खंडन किया कि उनके मुवक्किल ने ड्रग का सेवन किया था. आर्यन के खिलाफ मामला व्हाट्सऐप पर एक ड्रग पेडलर के साथ उनकी कथित चैट पर टिका लगता है.

पिछले साल 14 जून 2020 को अभिनेता

डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी बताते हैं कि देश के बड़े शहरों में मेथीलेनेडोक्सिन-मेथाफेटामाइन (एमडीएमए) से लेकर हेरोइन तक का सेवन बड़े पैमाने पर हो रहा है. मुंबई के एल.एच. हीरानंदानी अस्पताल के सोशल साइकियाट्रिस्ट डॉ. हरीश शेट्टी कहते हैं, ''ब्राउन शुगर और हेरोइन का इस्तेमाल फिर बढ़ गया है. यह हमारी पुलिसिंग एजेंसियों की नाकामी ही है-लंबे समय तक सप्लाइ में कमी करने के लिए निगरानी को गंभीरता से नहीं लिया गया.''

बेतहाशा बढ़ती मांग

पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी का निवासी 10 वर्षीय आदिल (बदला हुआ नाम) तीन महीने से घर से दूर है. उसके पिता ई-रिक्शा चलाते हैं और मां गृहिणी हैं. वह अपने माता-पिता के पास जल्द से जल्द वापस लौटना चाहता है. लेकिन दोस्तों के पास नहीं. वह कहता है, ''उन्होंने मुझे परेशानी में डाल दिया...'' उसके माता-पिता उसे दिल्ली गेट स्थित तिमंजिले नशामुक्ति केंद्र में ले आए. आदिल अंतत: ब्राउन शुगर की 'लत' से बाहर आ गया है. नशामुक्ति केंद्र में 40 अन्य किशोर हैं. राष्ट्रीय राजधानी में ऐसे तीन केंद्र चलाने वाले सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ ऐंड मासेज (एसपीवाइएम) के कार्यकारी निदेशक डॉ. राजेश कुमार कहते हैं, ''कम उम्र के बच्चे अब नशे की लत के शिकार होते जा रहे हैं. कुछ साल पहले, हमारे सबसे कम उम्र के मरीज 15-16 साल के होते थे. अब, हमें अक्सर 10-12 साल के बच्चे मिलते हैं.'' शुरुआत अक्सर गलियों के छोटे-छोटे गिरोहों के रूप में होती है. अपने माता-पिता या पुलिस की ओर से नशामुक्ति केंद्र में लाए जाने से पहले वे अपनी नशीले पदार्थों की लत को पूरा करने के लिए चोरी की कई वारदातें कर चुके होते हैं. आदिल कहता है, ''मैं ब्लेड मारता था... लोगों पर हमला करता था और पैसे छीनता था... ताकि हम ड्रग्स खरीद सकें.''

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नशे की लत के कारण अपराध में लिप्त युवाओं की इस प्रवृत्ति का रिकॉर्ड तैयार करता है. पिछले महीने जारी एक रिपोर्ट में, यह बताया गया कि नार्कोटिक्स ऐंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत किशोरों के खिलाफ दर्ज मामले 2020 में, 21 प्रतिशत बढ़कर 264 हो गए. 2015 में 23 और 2010 में 82 मामले दर्ज हुए थे.

सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 5 करोड़ ड्रग्स के आदी लोग हैं, इनमें 2.3 करोड़ अफीम से तैयार नशे का सेवन करते हैं. हेरोइन सबसे आम है जिसे 1.1 प्रतिशत नशेड़ी लेते हैं. यही नहीं देश में ओपिओइड के सेवन से लगभग

60 लाख विकारग्रस्त (हानिकारक या आश्रित पैटर्न) लोगों में से आधे से अधिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात में हैं.

नशेड़ी हेरोइन का इंजेक्शन लगाते हैं, सुड़कते हैं, सूंघते हैं या फिर सिगरेट में भरकर पीते हैं. अत्यधिक व्यसनकारी हेरोइन मस्तिष्क में तेजी से प्रवेश करती है और आनंद तथा पीड़ा की अनुभूति कराने वाली कोशिकाओं के साथ ओपिओइड रिसेप्टर्स को बांध देती है जो हृदय गति, नींद और सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं. उल्लास और उन्माद की स्थिति या 'हेरोइन रश' से मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शिथिल पड़ जाता है. लगातार हेरोइन का सेवन हृदय और फेफड़ों को नुक्सान पहुंचाता है. डॉ. राजेश कुमार कहते हैं, ''हेरोइन लोगों को जड़ कर देती है.''

समृद्ध वर्ग के नशे के आदी लोगों के बीच अत्यधिक महंगी दक्षिण अमेरिकी कोकीन सबसे ज्यादा पसंद की जाती है. अप्रैल में एनसीबी ने

सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 5 करोड़ ड्रग्स के आदी लोग हैं, इनमें 2.3 करोड़ अफीम से तैयार नशे का सेवन करते हैं. हेरोइन सबसे आम है जिसे 1.1 प्रतिशत नशेड़ी लेते हैं

मुंबई को भारत की कोकीन राजधानी कहा था. एजेंसी ने कहा कि नाइजीरिया और पेरू, ब्राजील तथा चिली जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों के ड्रग माफिया भारत में, खासकर मुंबई में अपना जाल फैला रहे हैं. अगस्त में, एनसीबी ने मुंबई के पास पालघर में चलाए जा रहे 'डायल-ए-ड्रग' नेटवर्क का भंडाफोड़ किया. यह कॉल सेंटर नाइजीरिया से चलाया जा रहा था. ऑनलाइन पेमेंट करने पर ग्राहकों को कोकीन की घर पर डिलिवरी मिलती थी.

तीन तरफा प्रहार की दरकार

राजस्व की कमी से जूझ रहा अफगानिस्तान

एएनआइ

असम में तो नशे को जैसे लगा दी आग

असम के कर्बी आंगलांग जिले के खटखटी पुलिस थाने का एक छोटा-सा पुलिस जत्था 17 जून को नगालैंड से सटे एक छोटे-से गांव जनक पुखुरी में ''क्वीन'' के इंतजार में बैठा था. नहीं, यह राजशाही की अगवानी करने वाला जत्था नहीं था. वे दरअसल नशीली दवाओं के साम्राज्य की 'क्वीन' था पाओने का इंतजार कर रहे थे. हालांकि पुलिस को पक्का यकीन न था कि यह रानी जनक पुखुरी से महज 10 किमी दूर नगालैंड में दीमापुर के अपने गुप्त ठिकाने से खुद-ब-खुद बाहर आएगी ही, पर उन्हें उम्मीद थी कि एक फर्जी ग्राहक के जरिए मादक पदार्थों की विशाल खेप का ऑर्डर देकर उन्होंने जो चारा फेंका है, वह इतना लुभावना है कि उसकी अनदेखी वह नहीं कर पाएगी. पुलिस तीन महीने से पाओने के भीतरी घेरे को भेदने के लिए जाल बिछा रही थी.

आखिरकार वह 7 करोड़ रुपए की हेरोइन के 164 बंडल लेकर सस्ती-सी मारुति अल्टो में आ ही गई. पारंपरिक मणिपुरी कपड़े पहने, मृदुभाषी, कमजोर-सी कदकाठी की पाओने कहीं से भी नशीले पदार्थों की खतरनाक महारानी नहीं लगती थी. पर 50 बरस की यह महिला दीमापुर को असम के नगांव से जोड़ने वाले एनएच 36 और मणिपुर के मोरेह को असम के नुमलीगढ़ से जोड़ने वाले एनएच 39 के रास्ते असम आने वाले 60 फीसद नशीले पदार्थों के लिए जिम्मेदार थी.

पाओने पूर्वोत्तर में काम कर रहे नशीले पदार्थों के उन 2,730 सरगनाओं में है जिन्हें असम पुलिस ने मई में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा के कमान संभालने के बाद छेड़े गए मादक द्रव्य-विरोधी विशेष अभियान में गिरफ्तार किया है. पहले 100 दिनों के भीतर पुलिस ने 198 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए और 2021 के पहले आठ महीनों में राज्य में नशे से जुड़ी गिरफ्तारियों में पिछले साल के मुकाबले 65 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई. फिर भी राज्य सरकार मानती है कि हो सकता है यह इस भीमकाय गोरखधंधे का सिरा भर हो. सरमा कहते हैं, ''मान लें कि जब्त नशीले पदार्थ असम में तस्करी के जरिए लाए जा रहे मादक पदार्थों के महज 10 फीसद हैं, तो कह सकते हैं कि राज्य में गैरकानूनी नशे का कारोबार करीब 5,000 करोड़ रु. सालाना का है.''

जेएनयू के दो प्रोफेसरों ने राष्ट्रीय

सरकारी सफाई
असम के करबी आंगलांग जिले में जब्त मादक द्रव्यों को आग लगाते मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा

परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2015-2016 के आधार पर 2019 में एक सर्वे किया, जिसमें पाया कि पूर्वोत्तर के लोगों में ड्रग की लत बाकी हिंदुस्तान से 20 फीसद ज्यादा है. यह इलाका भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8 फीसद है, लेकिन नशे की लत के आगे बेबस देश के 272 जिलों में से 41 इसी इलाके में हैं.

इस लत की वजह से पूर्वोत्तर में एचआइवी के मामलों में खतरनाक उछाल आया है. इसकी मुख्य वजह 15 से 20 साल के युवाओं में नशीले पदार्थ नसों के भीतर लेने का रुझान है. पिछले साल राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) की एक रिपोर्ट से पता चला कि भारत में प्रति 1,00,000 आबादी पर एड्स से जुड़ी मृत्यु दर सबसे ज्यादा मणिपुर (36.86) और फिर मिजोरम (28.34) तथा नगालैंड (26.20) में थी.

नशे के इस खतरे की असल जड़ म्यांमार से इस इलाके की भौगोलिक नजदीकी है. लाओ पीडीआर और थाईलैंड के साथ म्यांमार नशे के कारोबार के स्वर्णिम त्रिकोण का हिस्सा है. पूर्वोत्तर की 1,643 किमी सरहद म्यांमार से सटी है, उसी म्यांमार से जो इस त्रिकोण में उगाई जाने वाली कुल अफीम की 95 फीसद के लिए जिम्मेदार है. इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स ऐंड क्राइम (यूएनओडीसी) के अनुसार, म्यांमार मेथम्फेटामाइन या ''क्रेजी ड्रग'' याबा के गैरकानूनी उत्पादन का मुख्य स्रोत भी है. इसके अलावा, म्यांमार से अफीम की आपूर्ति के चलते पूर्वोत्तर भारत में नशीले पदार्थों के सेवन का प्रचलन खासा बढ़ा है. 2019 की एक रिपोर्ट 'मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया' के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम सरीखे राज्यों में कुल आबादी के 20 फीसद से ज्यादा लोगों ने साल में कम से कम एक बार नशीले पदार्थों का सेवन किया, जबकि राष्ट्रीय औसत महज 2 फीसद से कुछ ज्यादा है. 2018 के बाद से हेरोइन की बरामदगी में 485 फीसद का उछाल आया. इसी अवधि के दौरान पुलिस ने असम में 380 फीसद ज्यादा अफीम और बीते चार सालों में 80 लाख से ज्यादा याबा की गोलियां जब्त कीं.

म्यांमार से नशीले पदार्थ कई रास्तों से होकर असम पहुंचते हैं, जिनमें से ज्यादातर नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम से आते हैं. असम सरकार ने तो यहां तक दावा किया कि अगस्त में दो पड़ोसी राज्यों में हुए भूभागीय टकराव में भी मिजोरम में सक्रिय नशे की सांठगांठ का हाथ था, ताकि असम पुलिस का ध्यान नार्कोटिक्स के कारोबार से भटकाया जा सके. मिजोरम ने इस आरोप से इनकार करते हुए दावा किया कि उसने तो इस साल मेटाम्फेटामाइन की रिकॉर्ड जब्ती की है. फिर भी यह मानी हुई बात है कि म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी साझा सरहद के चलते मिजोरम नशीले पदार्थों का आसान रास्ता बन गया है. कुछ ड्रग उत्पादक भी अफीम की खेती के लिए मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज के इलाकों का इस्तेमाल करते हैं. बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ माफिया जत्थे भी असम के बरपेटा, दक्षिण सल्मारा और कामरूप सरीखे जिलों में अफीम की खेती करने लगे हैं. मई के बाद असम पुलिस ने 31 बीघे में उगाई जा रही भांग और 15 बीघे में उगाई जा रही अफीम नष्ट की है.

अलबत्ता नशे के कारोबार की मंजिल असम नहीं है. असम में दाखिल या उत्पादित हो रहे नशीले पदार्थों का पांचवां हिस्सा ही राज्य में बेचा जाता है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, राज्य का इस्तेमाल तस्कर नशीले पदार्थ भारत के दूसरे हिस्सों और बांग्लादेश ले जाने के लिए करते हैं. यही वजह है कि नशीले पदार्थों के खिलाफ असम सरकार का अभियान राज्य की भौगोलिक सरहदों के पार भी अहम हो जाता है. इसे लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला है, पर इसने कुछ शंका-आशंकाएं भी पैदा की हैं. कई आलोचकों ने कहा कि नशीले पदार्थों के मामले में असम की सजा दिलवाने की बहुत कम दर—42 फीसद के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले महज एक फीसद से कुछ ज्यादा—बड़ी अड़चन है. 2020 में राज्यसभा में एक जवाब से खुलासा हुआ कि 2019 में गिरफ्तार 1,237 लोगों में महज 10 को सजा दिलवाई जा सकी. मगर असम पुलिस के महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत मानते हैं कि हालात में नाटकीय सुधार आना तय है. पुलिस बल सुधार के बहुत-से उपायों पर काम कर रहा है, जैसे तलाश, जब्ती और गिरफ्तारी की अलग-अलग स्थितियों से निबटने के लिए एफआइआर के चार मॉडल बनाना, जांच अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण, सभी पुलिस थानों में विस्तृत दिशानिर्देशों का प्रसार और ड्रग से जुड़े मामलों की शीर्ष स्तर पर निगरानी.

इसी साल मई में हेमंत बिस्व सरमा के असम का मुख्यमंत्री बनने के बाद से राज्य की पुलिस ने पूर्वोत्तर के राज्यों में सक्रिय 2,730 ड्रग तस्करों को दबोचा है

मगर चिंता की और भी वजहें हैं. ड्रग तस्करों के साथ कथित मिलीभगत के लिए एक डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट सहित दो पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी कई लोगों के लिए यह मानने की वजह है कि मौजूदा कार्रवाई में महज कुछ छोटे खिलाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि मुख्य सरगनाओं की गिरफ्तारी से नशीले पदार्थों के बड़े गिरोहबाजों और शीर्ष अफसरों के बीच सांठगांठ का भांडा फूट सकता है. एक पुलिस अफसर याद करते हैं कि किस तरह मिजोरम की सीमा से सटे करीमगंज जिले के बदरपुर और पाथरकंडी के दो सबसे कुख्यात ड्रग सरगना काफी सबूत होने के बावजूद पुलिस के चंगुल से बच निकले. असम पुलिस की एक आंतरिक रिपोर्ट भी इस संभावना को स्वीकार करती है: ''ये गिरफ्तारियां इशारा करती हैं कि कानून लागू करने वाले अधिकारियों के एक हिस्से की इन गैरकानूनी गतिविधियों के साथ सांठगांठ है...''

असल में, व्यापक सामाजिक-राजनैतिक संदेश देने के लिए ही असम ने राज्य के चार ठिकानों—दिफू, गोलाघाट, नगांव और होजाई—में नशीले पदार्थों के निबटारे का दो दिन का आयोजन किया. इन जगहों से होकर नशीले पदार्थ ले जाए जाते हैं. 170 करोड़ रु. के नशीले पदार्थों को खुद मुख्यमंत्री सरमा ने आग लगाकर नष्ट किया. —कौशिक डेका

चंद्रदीप कुमार

छोड़ आए हम दिल्ली में नशा छुड़ाने वाले एसपीवाइएम केंद्र में मौजूद बच्चे

नशे का कारोबारी राष्ट्र बनने की कगार पर खड़ा है जहां अवैध मादक पदार्थों का धंधा, वैध संस्थानों के जरिए होता है. भारतीय ड्रग्स कंट्रोल अधिकारियों का मानना है कि स्थिति और खराब हो सकती है और मादक पदार्थों की खेप बढ़ सकती है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने स्वीकार किया कि अगर मादक पदार्थों की आवक बढ़ जाती है तो उससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि भारत के राज्यों और केंद्र की क्षमताएं बहुत सीमित हैं. उनका कहना है कि अगर हमें मादक पदार्थों के खिलाफ जंग छेड़नी है तो एक नेशनल ड्रग मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी होगी जिसका मुख्यालय दिल्ली में हो और उसके हितधारक जिला स्तर तक हों.

सभी वैश्विक मादक नशा विरोधी अभियान तीन स्तंभों पर टिके हुए हैं—आपूर्ति में कमी या ड्रग्स आपूर्ति बाधित करना, मांग में कमी या लोगों को ड्रग्स नहीं लेने के लिए प्रेरित करना और नुक्सान में कमी या नशा करने वालों का पुनर्वास व सुधार सुनिश्चित करना.

मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अंतरराष्ट्रीय खतरे का मुकाबला करने वाली भारत की मुख्य एजेंसी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे विश्वस्तरीय संगठन की तर्ज पर और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है. भारत में ड्रग्स की खेप की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी के साथ ड्रग्स से संबंधित खुफिया जानकारी जुटाने और उसकी जांच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. डार्कनेट, जहां ज्यादातर ड्रग्स के सौदे होते हैं, पर नजर रखने के लिए ब्यूरो को तकनीकी विशेषज्ञों की सख्त जरूरत है. इसे नशीली दवाओं के व्यापार के नए खतरों और पैटर्न को लेकर ज्यादा चौकस करने की जरूरत है.

यूएनओडीसी की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कैसे अफगानिस्तान इस क्षेत्र में मेथामफेटामाइन (एमडी) का एक प्रमुख स्रोत बनता जा रहा है. एक शक्तिशाली और अत्यधिक नशे की लत पैदा करने वाला एमडीएमए, जिसे क्रिस्टल मेथ के रूप में भी जाना जाता है, छोटी गुप्त प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है. यह भारत में 2,700 रुपए प्रति ग्राम में बिकता है और कुछ महानगरों के अमीर नशेड़ियों के एक वर्ग में कोकीन से भी ज्यादा पसंद किया जा रहा है.

पूर्व आइआरएस अधिकारी अजय अग्निहोत्री का कहना है कि ड्रग और राजस्व खुफिया एजेंसियों को प्रमुख आपूर्ति मार्गों की निगरानी करने की जरूरत है. वे कहते हैं, ''हमें अफगानिस्तान से खुफिया जानकारियों की जरूरत है. समस्या यह है कि डीआरआइ और एनसीबी के पास न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर में, उन जगहों की तुलना में अधिक कर्मचारी हैं जहां हमें वाकई लोगों की जरूरत है.''

सरकार के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए, विशेषज्ञों का कहना है कि गलियों में ड्रग्स बेचने वालों का पीछा करने के बजाए प्राथमिकता नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल बड़ी मछलियों को पकड़ने और एमडीएमए, हेरोइन और कोकीन की आपूर्ति रोकने की होनी चाहिए. उदाहरण के लिए, मुंद्रा तस्करी नेटवर्क शिमला में बैठा अफगान मूल का एक सरगना चला रहा था, जिसका पूरे देश में नशे के कारोबारियों का एक नेटवर्क था. (सरगना अब पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच एनआइए कर रही है).

एनसीबी के पूर्व डीजी रोमेश भट्टाचार्जी का कहना है कि प्राथमिकताओं में बदलाव केवल गांजा-भांग जैसे पदार्थों को अपराध श्रेणी से मुक्त करने के साथ ही हो सकता है. वे कहते हैं, ''आपको कानूनों को बदलना होगा, आपको पौधों से तैयार की जाने वाली ड्रग्स की खपत को वैध बनाना होगा. सरकार को इनका वितरण करना चाहिए ताकि तस्करों और ड्रग्स बेचने वालों के लिए कोई प्रोत्साहन ही न बचे.'' 2001 और 2011 के बीच पंजाब में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमे का सामना कर चुके 25,000 से अधिक व्यक्तियों पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि उनमें से बमुश्किल एक दर्जन ही तस्कर थे, बाकी छोटे-मोटे पेडलर और ड्रग्स का सेवन करने वाले लोग थे.

एनसीबी के पूर्व डीजी रोमेश भट्टाचार्जी का तो मानना है कि पौधों से तैयार किए जाने वाले मादक द्रव्यों की खपत को वैध बनाकर इनका वितरण सरकार को करना चाहिए ताकि तस्करों के लिए गुंजाइश ही न बचे

आपूर्ति में कमी लाने के साथ-साथ ही इस त्रिकोण के दूसरे महत्वपूर्ण पक्ष—मांग को कम करने और ड्रग्स की लत से दूर रखने के लिए जन जागरूकता अभियान—पर भी गंभीरता से काम होना चाहिए. पिछले अगस्त में, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सबसे अधिक नशीली दवाओं की खपत वाले 272 जिलों को लक्षित करते हुए 'नशा मुक्त भारत' अभियान शुरू किया था. यह अभियान महिलाओं और बच्चों सहित 12 करोड़ लोगों तक पहुंचने का दावा करता है. नशा करने वालों की काउंसलिंग के लिए सरकार की ओर से संचालित हेल्पलाइन में 12 प्राथमिक परामर्शदाता हैं जो हर महीने 2,000 से अधिक कॉल का जवाब देते हैं. मंत्रालय में संयुक्त सचिव राधिका चक्रवर्ती कहती हैं, ''नशा मुक्त भारत का पूरा फोकस युवाओं और किशोरों पर है. हम किसी सरकारी संगठन या एनजीओ की तरह एक संस्था-आधारित दृष्टिकोण की जगह एक समुदाय-आधारित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं.'' नशे के खिलाफ भारत के युद्ध में इन सब के साथ-साथ और भी बहुत कुछ करने की जरूरत होगी. ■

—साथ में किरन. डी. तारे

महाराजा की बगावत

कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाता कांग्रेस से टूटना और पंजाब की सियासत में नए अध्याय की शुरुआत लगभग तय

अनिलेश एस. महाजन

संदीप सिंह

नए सिरे से शुरुआत पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह

नई दिल्ली में कई सियासी नेताओं के साथ तीन दिनों तक बंद कमरे में बैठक के बाद, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 30 सितंबर को अपने गृह राज्य लौट गए. चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर उन्होंने प्रतीक्षा कर रहे मीडियाकर्मियों को स्पष्ट कर दिया कि वे कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले पर अटल हैं—और कांग्रेस को औपचारिक रूप से अलविदा कहने की तारीख की घोषणा बाद में करेंगे—लेकिन वे भाजपा में भी शामिल नहीं होने जा रहे हैं. तरह-तरह की अटकलें हैं. चर्चा है कि कैप्टन अपनी नई राजनैतिक पार्टी बनाने की योजना बना रहे हैं और एक पखवाड़े के भीतर, शायद दशहरे के आसपास, इसकी घोषणा करेंगे.

कैप्टन की बगावत से पहले से ही उथल-पुथल वाली पंजाब की राजनीति और पेचीदा हो गई है. विधानसभा चुनावों में कुछ ही महीने बचे हैं, इसलिए कैप्टन को राज्य में अपनी अलग राजनैतिक जगह बनाने के लिए पार्टी की फंडिंग से लेकर संगठन जैसी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. अमरिंदर को अकेले चलने वाले और एकांत-प्रिय

नेता के रूप में जाना जाता है. फिर, भले अब वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं हैं लेकिन उन्हें अब भी अपनी साढ़े चार साल की सरकार के खिलाफ नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है. उनके करीबी लोगों का मानना है कि उन्हें राष्ट्रवाद के अपने नजरिए से लोगों का समर्थन हासिल होगा और उसी तरह उदार सिख की उनकी छवि भी उनके पक्ष में माहौल बनाएगी. उनके एक करीबी सहयोगी कहते हैं, ''जहां तक बात उनकी उम्र की है, तो उम्र महज एक संख्या है. 2012 में, जब प्रकाश सिंह बादल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो वे 84 वर्ष के थे.''

सूत्रों के मुताबिक, चुनावी लड़ाई के लिए कमर कसने के उनके फैसले के पीछे बड़ी वजह पिछले कुछ हफ्तों में कांग्रेस से मिला 'अपमान और बेइज्जती' है. इस मामले में भी विरासत पर नजर डाली जा सकती है. मसलन, अमरिंदर के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन वही बात राहुल के साथ उनके रिश्तों के बारे में नहीं कही जा सकती. 2013 और 2017 के बीच राहुल ने कांग्रेस की पंजाब इकाई की शक्ल बदलने के कई असफल प्रयास किए, जिसमें प्रताप सिंह बाजवा को प्रदेश कांग्रेस प्रमुख बनाकर सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र बनाने का प्रयास भी शामिल था. लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले अमरिंदर ने अपना पांव अड़ा दिया और धमकी दे डाली कि अगर उन्हें खुली छूट नहीं दी गई तो वे पार्टी छोड़ देंगे. तब सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद राहुल पीछे हटे और उस चुनाव में सिर्फ दो रैलियों को ही संबोधित किया. अमरिंदर ने चुनाव अभियान कांग्रेस के बल पर नहीं, बल्कि अपनी छवि पर खड़ा किया था और 'कैप्टन दी सरकार' (कैप्टन की सरकार) का नारा देकर जीत हासिल की थी. और पिछले चार वर्षों में, उन्होंने राहुल को पंजाब में सरकार और पार्टी दोनों से दूर ही रखा. गांधी परिवार के दबाव के बावजूद, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और गांधी परिवार के कई अन्य वफादार नेताओं को किसी तरह के पद से दूर रखा.

कांग्रेस आलाकमान और अमरिंदर सिंह के बीच कटुता और फूट में भाजपा की पंजाब में नई दिलचस्पी जग गई है. भगवा पार्टी पिछले सितंबर से ही राज्य में लड़खड़ा रही है, जब शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के साथ उसका 25 साल पुराना गठबंधन केंद्र के नए कृषि कानूनों के बाद टूट गया था. सितंबर के अंत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अमरिंदर सिंह के बीच हुई बातचीत से पता चलता है कि भगवा पार्टी उन्हें अपने पाले में लाने के लिए उत्सुक है क्योंकि अकाली दल के साथ छोड़ने से हुए नुक्सान की भरपाई के लिए उसे एक नए साथी की जरूरत है.

पंजाब में, भाजपा का वोट बैंक मुख्य रूप से सवर्ण हिंदू हैं, हालांकि इसने शहरी दलितों के बीच भी पैठ बनाई है. अकाली दल के साथ गठबंधन से उसे राज्य के कुछ खास हिस्सों में सवर्ण सिखों का भी समर्थन मिल जाया करता था, जिस पर अब वह भरोसा नहीं कर सकती. राज्य में हिंदू मतदाताओं की संख्या 38.5 प्रतिशत है और 45 शहरी सीटों पर हिंदू या तो बहुसंख्यक हैं या फिर जीत-हार तय करने की हैसियत रखते हैं. भाजपा को राज्य में एक ऐसे सहयोगी की तलाश है जिसकी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी पकड़ हो, जहां जाट सिखों का वर्चस्व है. जाट सिख राज्य के कुल मतदाताओं का 18 प्रतिशत हिस्सा हैं और केंद्र के नए कृषि कानूनों के जोरदार विरोध के पीछे उनकी सबसे अहम भूमिका है.

पंजाब में हिंदू वोटरों का रुझान बदलता रहता है. पिछले दो दशकों से हिंदू वोटर अकाली-भाजपा गठजोड़ के बदले बड़ी तादाद में कांग्रेस की ओर झुके. उसकी एक वजह अमरिंदर सिंह की उदार छवि रही है. हालांकि, वे उनके वोट तय मानकर नहीं चल सकते थे. 2007 में हिंदू वोट बड़े पैमाने पर अकाली-भाजपा गठजोड़ की ओर चला गया और उसने शहरी केंद्रों भारी जीत हासिल करके सरकार बनाई.

तब से, अमरिंदर सिंह ने अपनी राष्ट्रवादी छवि बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करते रहे हैं. 2017 में उन्होंने कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन से मिलने से इनकार कर दिया. उन्होंने सज्जन को 'खालिस्तानियों का हमदर्द' बताया. फरवरी 2018 में, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अमृतसर की यात्रा पर आए तो उनसे मिलने के लिए पार्टी आलाकमान ने अमरिंदर पर बहुत दबाव बनाया था. फिर भी, अमरिंदर ने बैठक में स्पष्ट किया कि वे ट्रूडो कैबिनेट में सिख कट्टरपंथियों को मिल रही तवज्जो से नाखुश हैं. उन्होंने ट्रूडो को कनाडा में सक्रिय नौ खालिस्तानी समर्थक आतंकवादियों की सूची भी सौंपी.

कैप्टन की यह राष्ट्रवादी रुझान नवजोत सिंह सिद्धू की छवि से उलट है. 2018 में प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में वे कैमरे पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को गले लगाते हुए नजर आए थे. अमरिंदर अक्सर इस बात को उठाते रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के लिए खतरा है, विशेष रूप से पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में जहां हिंसा भड़काने के लिए वह उपद्रवी तत्वों को हथियार, ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित पदार्थ मुहैया करा रहा है. कहा जाता है कि यह सारा कुछ पंजाब के शहरी क्षेत्रों में समर्थन हासिल करने के लिए किया जाता है, जहां बहुत से लोगों के जेहन में खालिस्तान समर्थक हिंसा की खौफनाक यादें अभी भी ताजा हैं.

खासकर इस संदर्भ में अमरिंदर सिंह की राष्ट्रवादी छवि उनकी सबसे बड़ी पूंजी बनी हुई है. उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर ऐसा ही अफसाना गढ़ने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान ने सिद्धू को खुश करने के लिए उन्हें हटने पर मजबूर किया. इसका मकसद हिंदुओं और उदारवादी सिखों में अपने पक्ष में सहानुभूति जगाने की कोशिश है, ताकि साढ़े चार साल की उनकी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना का मुकाबला किया जा सके, जो सत्ता से बाहर होने के बावजूद उन पर भारी पड़ सकती है.

राजनैतिक जानकारों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के साथ पींगें बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें केंद्र के कृषि कानूनों पर अपने नजरिए पर पुनर्विचार करना होगा और जाट सिख समुदाय के गुस्से को शांत करने के लिए वह सब करना होगा, जो वे कर सकते हैं. उनके करीबी लोगों का कहना है कि वे इस मामले में प्रताप सिंह बाजवा के साथ काम कर रहे हैं, जो पहले उनके विरोधी थे पर अब दोस्त बन गए हैं. उनके जरिए किसान यूनियनों से बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि

29 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री के पद से बेदखल होने के बावजूद, अमरिंदर अभी भी गैर-अकाली और गैर-कम्युनिस्ट समर्थित किसान यूनियनों के बीच काफी प्रभाव रखते हैं. वे प्रभावशाली अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रमुख हैं, और पूर्ववर्ती पटियाला रिसायत के महाराजा हैं. पंजाब की राजनीति और इतिहास की अच्छी समझ रखने वाले टिप्पणीकार जगतार संधू कहते हैं, ''पंजाब में अमरिंदर का राजनैतिक कद कांग्रेस नेता से ज्यादा सिख नेता और क्षत्रप का है.''

यह तो समय बताएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री किसानों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए अपने प्रभाव का कितना लाभ उठाने में सक्षम होंगे. किसान आंदोलन महीनों से जारी है और रह-रहकर उसमें नई चिंगारियां उठने लगती हैं. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हाल की घटना से आंदोलन फिर सुर्खियों में आ गया है. वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कथित तौर पर भाजपा के केंद्रीय मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई. भाजपा का राज्य और केंद्रीय नेतृत्व बैकफुट पर है. स्थानीय प्रशासन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से बच नहीं पाया. हालांकि यह जनता के गुस्से को थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन विपक्ष के नेता और किसान यूनियनें भगवा पार्टी पर लीपापोती के आरोप लगा रही हैं.

एएनआइ

नई दोस्ती: दिल्ली में 29 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह

मुख्यमंत्री के पद से अपने इस्तीफे के बाद, अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और जता दिया है कि विधानसभा चुनावों में सिद्धू की हराने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाएंगे. सूत्रों का कहना है कि वे गांधी परिवार से भी कड़वाहट की हद तक निराश हैं. और वे अकेले नहीं हैं. 2014 के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदय और भाजपा का चुनावी दबदबा कायम हुआ, तो देश भर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ी है. हेमंत बिस्वा सरमा, विजय बहुगुणा और ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर रीता बहुगुणा जोशी, एस.एम. कृष्णा और जितिन प्रसाद तक, इन सभी को भाजपा में नया ठिकाना मिला है. सुष्मिता देव और अशोक तंवर जैसे अन्य वरिष्ठ नेता अन्य राजनैतिक दलों में भविष्य तलाश रहे हैं. उनमें अधिकांश ने पार्टी संचालन को लेकर गांधी परिवार के रवैये के प्रति कभी न कभी अपनी निराशा जरूर जताई है.

अमरिंदर सिंह के बाहर जाने से कांग्रेस को निश्चित तौर पर बड़ा राजनैतिक नुक्सान उठाना होगा. पंजाब में उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ साल में मोदी लहर के बावजूद उन्होंने कांग्रेस को लगातार चुनावी जीत दिलाई है. 2014 में, उन्होंने अमृतसर के चुनावों में भाजपा के कद्दावर नेता अरुण जेटली को हराया; 2017 के विधानसभा चुनावों में उनकी अगुआई में चले चुनाव अभियान में कांग्रेस के 77 सदस्य विधानसभा पहुंचे, जो आतंकवाद के बाद के युग में राज्य में कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन था. 2019 के लोकसभा चुनाव में, पंजाब देश के केवल उन दो राज्यों में था (दूसरा केरल), जहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया. पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर आशुतोष कुमार का कहना है कि यकीनन कांग्रेस को नुक्सान हुआ है, सोचने वाली बात बस इतनी है कि नुक्सान कितना होगा.

अमरिंदर के लिए कांग्रेस में समर्थन और सहानुभूति है. पंजाब की हालिया घटनाओं पर मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेताओं ने अपनी आवाज उठाई. आने वाले दिनों में कई अन्य नेता आवाज उठा सकते हैं. मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद से कांग्रेस आलाकमान ने उनसे संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की है, केवल जी-23 के नेता उनके संपर्क में बने हुए हैं, जिन्होंने अगस्त 2020 में सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी संगठनात्मक चुनाव और स्पष्ट नेतृत्व की मांग की थी.

सूत्रों के मुताबिक, लगभग तय है कि अमरिंदर दशहरे तक नई पार्टी की घोषणा करें, और पर्दे के पीछे कांग्रेस से तोड़कर एक धड़े को लाने की बात भी चल रही है. कुछ का कहना है कि वे 22 विधायकों को तोड़कर चरणजीत सिंह चन्नी सरकार गिराने की कोशिश भी कर सकते हैं. उनमें 18 तो टूटकर उनके साथ जाने को तैयार बताए जाते हैं. कई सांसद, जैसे उनकी पत्नी परनीत कौर (पटियाला), मोहम्मद सादिक (फरीदकोट), जीएस औजला (अमृतसर), मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब) और संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) भी उनके साथ पुख्ता तौर पर बताए जाते हैं. नए मुख्यमंत्री चन्नी ने अपने मंत्रिमंडल में अमरिंदर के तीन वफादारों—उप-मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी, ब्रह्म मोहिंद्रा और विजय इंदर सिंगला—को शामिल किया है लेकिन तय नहीं है कि ये मुख्यमंत्री के साथ बने रहेंगे.■

कर दिखाया इंडिया टुडे हेल्थगीरी अवार्ड 2021 के विजेता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन तथा प्रधान संपादक अरुण पुरी के साथ

सबसे ऊपर सेहत

भारत के कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन, भारत में कोविड की स्थिति पर विशेषज्ञों के साथ बातचीत और संगीत के धड़कते सुरों से बंधा समां—इंडिया टुडे हेल्थगीरी अवार्ड 2021 में यह सब कुछ था

किरण डी. तारे

न

ई दिल्ली के होटल ली मेरीडियन में 2 अक्तूबर को करीब 200 प्रेक्षकों की तालियों के बीच 23 शख्सियतों और संस्थाओं के प्रतिनिधि तस्वीर खिंचवाने के लिए खड़े हुए. ये इंडिया टुडे हेल्थगीरी अवार्ड के विजेता थे. इनमें डॉक्टर, प्रशासक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा कॉर्पोरेट संगठन भी शामिल थे. इन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीयों को सुरक्षित रखने और फर्ज को अंजाम देने से कहीं आगे बढ़कर समाज की सेवा करने के लिए चुना गया था.

समारोह का सबसे मर्मस्पर्शी पल शायद वह था जब गुजरात काडर के 1986 बैच के आइएएस अधिकारी दिवंगत गुरुप्रसाद महापात्र को महामारी के विभिन्न पहलुओं से

यादिर इकबाल

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

MESSAGE

From Safaigiri to Healthgiri, the commendable initiatives by India Today Group are rooted in the eternal values of selfless service and compassion that have been integral to our traditions and culture. The virtual presentation of India Today Healthgiri Awards on October 2, 2021 reflects the guiding principle recommended by our ancient scriptures – उप सर्प मातरं भूमिम् meaning 'Serve the Motherland'.

What better day to present the Awards than Gandhi Jayanti! October 2 is a day that symbolises the collective spirit of our nation and its people nurtured by the life and ideals of Pujya Bapu.

Healthcare has been in focus for nations and societies the world over during the times of Corona pandemic. The undying commitment, determination and putting service before self of our healthcare professionals including doctors, scientists and technicians in saving precious lives, not caring for their own, has been exemplary.

The health of a nation and its people are intimately connected. The collective resolve and efforts of 130 crore people have powered our fight against Corona.

The social responsibility of media institutions has helped spread positivity for the larger good. The seventh edition of India Today Healthgiri Awards celebrates the steely resolve and indefatigable efforts of our Corona warriors. I am sure that the Healthgiri Awards will inspire the people and media professionals alike to strive to do their best for the nation.

May the India Today Healthgiri Awards 2021 be a resounding success. Best wishes to India Today Group for its future endeavours.

(Narendra Modi)

New Delhi
आश्विन 09, शक संवत् 1943
01st October, 2021

मुहर प्रधान की हेल्थगीरी अवार्ड जैसी पहलकदमी के लिए इंडिया टुडे ग्रुप की सराहना करते हुए लिखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र

निबटने वाली केंद्र की अधिकार-प्राप्त समितियों में से एक के प्रमुख के रूप में उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए 'उपेक्षित हीरो' अवार्ड से मरणोपरांत सम्मानित किया गया. कोविड से जुड़ी परेशानियों की वजह से इस साल जून में महापात्र का देहांत गया. उनकी पत्नी और उनके बेटे ने जब उनकी ओर से यह अवार्ड प्राप्त किया, तो सारे प्रेक्षकों ने उनके सम्मान में खड़े होकर हॉल को देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजा दिया.

सम्मान समारोह के अलावा, हेल्थगीरी अवार्ड (जैसा कि हमारा ध्यान साफ-सफाई से हटकर स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित होने के कारण सफाईगीरी अवार्ड को उसके छठे और सातवें संस्करणों में अब इसी नाम से जाना जाता है) के इस सातवें संस्करण में बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन की समयावली और संभावित तीसरी लहर के बारे में पैनल चर्चा के अलावा उदित नारायण, रेखा भारद्वाज तथा अमित मिश्र जैसे प्रतिष्ठित गायकों की प्रस्तुतियां भी थीं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस आयोजन का मुख्य भाषण दिया. इसमें उन्होंने कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई की सफलता का श्रेय संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की समर्पित सेवा को दिया. उन्होंने कहा, ''सरकार ने वह सब किया जो कर सकती थी, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने वह सब किया जो वे कर सकते थे और हम सब साथ मिलकर लड़े. यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. हमने इन कोरोना योद्धाओं—डॉक्टरों, नर्सों और सरकारी कर्मचारियों—की जबरदस्त प्रतिबद्धता देखी और ऐसे लोगों का अभिनंदन करना हमारी परंपरा

निर्णायक मंडल

डॉ. नरेश त्रेहन
चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, मेदांता

डॉ. के. श्रीनाथ रेड्डी
प्रेसिडेंट, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया

डॉ. स्वाति पीरामल
वाइस-चेयरपरसन, पीरामल ग्रुप

मनीष सभरवाल
चेयरमैन, टीमलीज़ सर्विसेज लिमिटेड

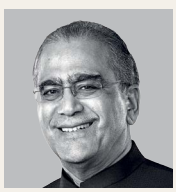

अरुण पुरी
चेयरमैन और प्रधान संपादक, इंडिया टुडे ग्रुप

राजवंत रावत

''सरकार जितना कर सकती थी, उसने किया, स्वास्थ्यकर्मी जितना कुछ कर सकते थे, उन्होंने किया. और इस तरह से हम सबने मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी. यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है''

मनसुख मांडविया,
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

है.'' उन्होंने एक नर्स का उदाहरण दिया, जो अपने तीन महीने के बच्चे को घर छोड़कर हफ्तों अस्पताल में ही रहती और काम करती रहीं, इस डर से कि कहीं वायरस उनके साथ घर न पहुंच जाए.

साधनहीनों के कल्याण के लिए अपने मंत्रालय के 900 करोड़ रुपए के खर्च की चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान नेक लोगों की ओर से चलाए गए खाना बांटने के अभियानों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ''हिंदुस्तान की ताकत देखिए. हम अपने पड़ोसियों को खाली पेट नहीं सोने देते. वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है.'' उन्होंने आगे कहा कि संकट के समय भारत दुनिया की मदद के लिए भी आगे आया और महामारी की पहली लहर के दौरान 123 देशों को दवाइयों की आपूर्ति की.

साफ-सफाई और आरोग्य को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सीखों से जोड़ते हुए मांडविया ने कहा, ''गांधी जी कहते थे कि स्वास्थ्य ही असली धन है. हमें उनके सिद्धांतों पर चलना चाहिए...अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पंच महाभूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) में बारीक संतुलन की जरूरत है. यह संतुलन कायम नहीं रहा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाएगा.''

इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और प्रधान संपादक अरुण पुरी ने स्वागत भाषण में साफ-सफाई के महत्व की चर्चा की और कहा कि कोविड का प्रेत अब भी हमारे पीछे पड़ा है. उन्होंने कहा कि महामारी से दुनिया भर में लाखों जानें गईं, जीवन और आजीविकाएं तहस-नहस और अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गईं. उन्होंने कहा, ''जो जिंदा बच गए हैं, उन्हें और ज्यादा आर्थिक असुरक्षा, दुश्चिंता और जिंदगी के हरेक पहलू में उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है. बहुत-से लोग तो अब भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रहे हैं.''

चेयरमैन और प्रधान संपादक ने इस वक्त के दौरान अथक प्रयासों के लिए कोविड योद्धाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा की. उन्होंने कहा, ''यह सचमुच एक युद्ध था. इसमें लड़ने के लिए योद्धाओं के असाधारण जत्थे की जरूरत थी. देश भर में सरकार के भीतर और लोगों के बीच भी हजारों शानदार स्त्री-पुरुष और संगठन हमारे कोरोना योद्धा थे, जिन्होंने अपने साथी नागरिकों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं दीं, एंबुलेंस चलाईं, जरूरतमंदों को चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई, बाल सहायता कार्यक्रम चलाए, मृतकों के अंतिम संस्कार किए और संकट से निबटने में सरकार की भी सहायता की.''

तीसरी लहर पर चर्चा के सत्र में पैनल में शामिल स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि तीसरी लहर की संभावना को खारिज नहीं किया गया है; यह इस पर निर्भर करता है कि वैक्सीन हमें कितने लंबे समय तक सुरक्षित रखती है और वायरस का कोई नया रूप सामने आता है या नहीं. मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉ. नरेश त्रेहन ने कहा, ''हम कयास ही लगा सकते हैं

हेल्थगीरी अवार्ड 2021 के विजेता

श्रेणी
विजेता

↘ कोविड-19 से लड़ने वाला सर्वश्रेष्ठ सरकारी अस्पताल
लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, दिल्ली

↘ कोविड-19 से लड़ने वाला सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल
कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भुवनेश्वर

↘ कोविड-19 से लड़ने वाला सर्वश्रेष्ठ चैरिटी अस्पताल
टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज बी.वाइ.एल. नायर चैरिटेबल अस्पताल, मुंबई

↘ कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ एनजीओ या अन्य संस्था
इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, नई दिल्ली

↘ कोविड से जुड़े काम में सर्वश्रेष्ठ नवाचार
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), नई दिल्ली

↘ कोविड-19 से लड़ाई में सर्वश्रेष्ठ राज्य
कर्नाटक

↘ सेलेब्रिटी जिन्होंने महामारी के दौरान अनुकरणीय कार्य किया
अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना

↘ अधिक व्यापक सामाजिक प्रभाव के लिए सर्वश्रेष्ठ दूरगामी कॉर्पोरेट योगदान
विप्रो लिमिटेड, बेंगलूरू

↘ सर्वश्रेष्ठ एंबुलेंस सेवा
हेल्पनाउ, मुंबई

↘ ऑक्सीजन डिलिवरी की सर्वश्रेष्ठ पहल
सेवलाइफ फाउंडेशन, नई दिल्ली; दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, नई दिल्ली

↘ सर्वश्रेष्ठ टीका अभियान चलाने वाला राज्य
- **गुजरात;**
- **केरल**

↘ निजी अस्पताल की ओर से सर्वश्रेष्ठ कोविड वैक्सीन डिलिवरी कार्यक्रम
- **नारायण हेल्थ (नारायण हृदयालय लिमिटेड), बेंगलूरू;**
- **सर एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल ट्रस्ट, मुंबई**

↘ विशेष अवार्ड, अंतिम संस्कार में सहायता
शहीद भगत सिंह सेवा दल, नई दिल्ली

↘ सर्वश्रेष्ठ मानसिक स्वास्थ्य परामर्श
- **द सायरस ऐंड प्रिया वंद्रेवाला फाउंडेशन, मुंबई**

↘ सर्वश्रेष्ठ बाल चिकित्सा / सहायता
वर्ल्ड विजन इंडिया

↘ कोविड-19 से लड़ने में सर्वश्रेष्ठ जिला
- **गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश;**
- **फरीदाबाद, हरियाणा**

↘ कोविड वैक्सीन के विकास और उत्पादन में असाधारण योगदान
- **भारत बायोटेक, हैदराबाद**
- **सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे**

↘ विशेष अवार्ड, उपेक्षित हीरो
दिवंगत डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, नई दिल्ली

कि आने वाले महीनों में क्या होगा, मगर पहले की लहरों और अब में मुख्य फर्क यह है कि आबादी के अच्छे-खासे हिस्से को अब टीका लग चुका है.'' जब देश की 70 फीसद वयस्क आबादी को कोविड टीके की कम से कम पहली खुराक लग चुकी है, कई लोग सोच रहे हैं कि वायरस से सुरक्षा के लिए तीसरी बूस्टर खुराक जरूरी है या नहीं. डॉ. त्रेहन ने कहा, ''फिर से होने के संकेत दिखाई दें तो उनके लिए तीसरी खुराक पर विचार कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा हालात अगर बने रहते हैं और फिर से संक्रमण होने के मामले कम ही रहते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं. लिहाजा हमें बाकी आबादी को टीके लगाए बिना स्वास्थ्यकर्मियों को तीसरी खुराक देने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.'' दिल्ली की डॉ. डांग्स लैब के डायरेक्टर डॉ. नवीन डांग ने भी इस पर अपनी सहमति जाहिर की, ''पहले तो पूरी आबादी को टीके लगाएं और फिर बूस्टर शॉट के बारे में सोचें.''

हेल्थगीरी अवार्ड समारोह में चर्चा के लिए एक और विषय रखा गया, जो कइयों के दिल के करीब है—बच्चों को टीका. यह कब तक मिलेगा और क्या सुरक्षित होगा? सर गंगाराम अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल सचदेवा ने कहा, ''मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि अगर वायरस से बच्चों को नुक्सान नहीं होता तो उन्हें टीके की जरूरत क्यों है. मगर माता-पिता भूल जाते हैं कि ठीक होने के बाद बच्चों में बहुत-से अंगों में सूजन आने का खतरा होता है. कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर या बिगड़ी होने के कारण उन्हें कोविड होने का जोखिम होता है.'' विशेषज्ञ शुरुआती दिनों में वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट का अंदाज लगाते हैं, पर यह भी उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन के सुरक्षित होने के बारे में तथ्यों की जानकारी और प्रमाणों से माता-पिता को भरोसा दिलाया जा सकता है कि वे बच्चों को सुरक्षा टीका लगवाएं. मेदांता की पीडिएट्रिक क्रिटिकल केयर इकाई के एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. मनिंदर धालीवाल पूरी तरह इसके पक्ष में हैं. वे कहते हैं, ''मैं कहूंगा कि अपने बच्चे को टीका लगवाएं. यह वैक्सीन सुरक्षित है और न केवल आपके बच्चे की हिफाजत करेगी बल्कि उसे वायरस फैलाने से रोकेगी भी.'' ■

राजवंत रावत

संक्रमण का सैलाब
मई 2021 में एलएनजेपी कोविड केयर सेंटर का नजारा

कोविड-19 से जूझता सर्वश्रेष्ठ सरकारी अस्पताल

विजेता: लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, दिल्ली

जीत की वजह: एलएनजेपी ने महामारी की शुरुआत में ही अपने पूरे परिसर को विशाल कोविड अस्पताल में बदल दिया. मई 2021 में दूसरी लहर के दौरान अस्पताल ने ऑक्सीजन का अतिरिक्त बुनियादी ढांचा स्थापित किया. अथक कोशिशों की कीमत भी चुकाई; अस्पताल के 13 डॉक्टरों को वायरस ने लील लिया

अनवरत सेवा

सोनाली आचार्जी

प्र

तिब्बिया मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) के साथ संबद्ध लोकनायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल 44 साल से ज्यादा समय से मरीजों का इलाज करता आ रहा है. यह अस्पताल इसी जगह 1932 में ब्रिटिश सरकार की ओर से स्थापित एक छोटे-से हेल्थ क्लीनिक से बड़ा हुआ है. आज यह दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और महामारी के दौरान राजधानी का पूर्णत: कोविड को समर्पित सबसे बड़ा अस्पताल रहा.

कोविड के इलाज की सुविधाओं की तत्काल जरूरत को पहचानकर एलएनजेपी ने महामारी की शुरुआत में ही पूरे परिसर को विशाल कोविड अस्पताल में बदल दिया. अब इसमें कोविड के मरीजों के लिए 2,500 आइसोलेशन बिस्तर, 900 आइसीयू बिस्तर और 500 वेंटिलेटर वाले बिस्तर हैं. मई 2021 में दूसरी लहर के दौरान अस्पताल ने ऑक्सीजन का अतिरिक्त बुनियादी ढांचा खड़ा किया—मौके पर ही चार संयंत्र लग चुके हैं और पांचवें का काम जारी है. एलएनजेपी में अब हर माह 56 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की क्षमता है. अस्पताल सरकार के टीका कार्यक्रम से भी जुड़ा है और 1 सितंबर 2021 तक 40,000 से ज्यादा लोगों को पहली खुराक दे चुका था.

महामारी के दौरान एलएनजेपी ने अपनी निजी चुनौतियां भी झेलीं. वायरस ने इसके 13 डॉक्टरों को निगल लिया और इसके 1,000 कर्मचारी संक्रमित हुए. मगर टीम का मनोबल नहीं टूटा. डॉक्टर और नर्स छुट्टी लिए बिना महामारी के हर दिन काम करते रहे और तय समय से ज्यादा काम भी किया, हफ्तों अपने परिवारों से दूर रहे और कई बार मरीजों की खैरियत की खातिर खुद अपनी सुरक्षा खतरे में डालने से नहीं हिचकिचाए. ■

लगातार एक कदम आगे

कोविड-19 से जूझता सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल

विजेता: कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भुवनेश्वर

जीत की वजह: महामारी की शुरुआत में ही कोविड को समर्पित भारत का पहला अस्पताल स्थापित किया और ओडिशा के ग्रामीण इलाकों तक कोविड से जुड़ी सेवाएं पहुंचाईं

रोमिता दत्ता

कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (केआइएमएस) ने बहुत पहले 2 अप्रैल 2020 को ही, जब देश में महामारी फैलनी शुरू ही हुई थी, भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल स्थापित किया. ओडिशा सरकार और ओडिशा खनन निगम के साथ मिलकर केआइएमएस ने भुवनेश्वर के परिसर के भीतर 500 बिस्तरों का अस्पताल बनाया, जो क्रिटिकल केयर इकाइयों, वेंटिलेटरों और 8.6 एमटी क्षमता के चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र से सुसज्जित था. एक भवन के निर्माण का काम चल रहा था और ऐसे में केआइएमएस के संस्थापक प्रो. अच्युत सामंत ने इसे कोविड केंद्र में बदल दिया.

केआइएमएस ने कंधमाल, बलांगीर और मयूरभंज सरीखे पिछड़े जिलों में 200 बिस्तरों के तीन कोविड अस्पताल खोले. भुवनेश्वर में 200 बिस्तर बढ़ाने के साथ इन चार अस्पतालों की क्षमता 1,300 बेड हो गई.

प्रो. सामंत कहते हैं, ''गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य संकट सबसे मुश्किल मानवीय चुनौती बन ही जाता है.'' प्रो. सामंत ने महामारी से निबटने में राज्य सरकार के साथ काम करने के लिए समय रहते संसाधन जुटाना शुरू किया. अगस्त 2021 तक केआइएमएस 86,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट और 15,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज कर चुका था. क्वारंटीन और आइसोलेशन का मरीज के मानसिक स्वास्थ्य पर असर होता है, भुवनेश्वर के अस्पताल ने मरीजों को सीसीटीवी कैमरों और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उनके परिजनों और डॉक्टरों के संपर्क में बनाए रखा. ■

आगे की सोच
भुवनेश्वर का केआइएमएस कोविड अस्पताल

बात भरोसे की नायर हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर रमेश भरमाल (नीली शर्ट में) अपने स्टाफ के साथ

मिलिंद शेल्टे

पथप्रदर्शक

कोविड-19 से जूझता सर्वश्रेष्ठ चैरिटी अस्पताल

विजेता: टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और बी.वाइ.एल. नायर चैरिटेबल अस्पताल, मुंबई

जीत की वजह: नायर अस्पताल की मृत्यु दर मुंबई के अस्पतालों में सबसे कम रही. तीन ऑक्सीजन संयंत्रों के साथ नाजुक मरीजों के लिए इसके पास पर्याप्त सप्लाइ थी

किरण डी. तारे

बी.वाइ.एल. नायर चैरिटेबल अस्पताल कोविड मरीजों के लिए 1,100 बिस्तर समर्पित करने वाला महाराष्ट्र का पहला अस्पताल था. यह कोविड संक्रमित गर्भवती महिलाओं और डायलिसिस की जरूरत वाले मरीजों के लिए बिस्तर आरक्षित करने वाला पहला अस्पताल भी था. छह महीनों में अस्पताल ने 1,100 प्रसव करवाए और 5,000 डायलिसिस उपचार किए. नायर अस्पताल के डीन डॉ. रमेश भरमाल कहते हैं, ''ज्यादातर औरतें आखिरी वक्त में यहां आईं जब उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी.''

नायर अस्पताल ने इलाज का जो मॉडल विकसित किया, उसे बाद में मुंबई के कई दूसरे अस्पतालों ने अपनाया. अस्पताल में फिलहाल कोविड मरीजों के लिए समर्पित 150 बिस्तर हैं. बीते 4 सितंबर को अपने सौ साल का जश्न मनाने वाले इस अस्पताल की मृत्यु दर मुंबई के सभी अस्पतालों में सबसे कम रही. यह शुरुआती चरण से ही रेमडेसिविर, फैबिपिराविर और आइवरमेक्टिन सरीख दवाइयां मुहैया करने में आगे रहा. अस्पताल ने वायरस के जेनोमिक वैरिएंट को समझने के लिए जीनोम सिक्वेसिंग मशीन लगाई. मेडिकल कॉलेज में कक्षाओं पर भले असर पड़ा, पर छात्र कोविड के नियमों का पालन करते हुए प्रैक्टिकल कर पाए. अस्पताल के प्रशासन का काम देखने वाले डॉ. संजय स्वामी कहते हैं, ''कोविड के इंतजाम के मामले में पथप्रदर्शक बनना हमारे लिए गौरव का क्षण है.'' ■

तकनीकी महारत

कोविड से जुड़े कामों में सर्वश्रेष्ठ नवाचार

विजेता: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), दिल्ली

जीत की वजह: डीआरडीओ ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल कोविड के खास किट और उपकरण डिजाइन करने और बनाने में किया

संदीप उन्नीथन

एएनआइ

ताकि सांस चलती रहे मई में एम्स, दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में डीआरडीओ ने उच्च क्षमता वाला मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाया

चेयरमैन जी. सतीश रेड्डी की अगुआई में डीआरडीओ की कोविड टास्क टीम ने महामारी से लड़ने के लिए कई अहम काम हाथ में लिए. एसपीओ2 (ऑक्सीजन कंसंट्रेशन)-आधारित प्रणालियों से लेकर वेंटिलेटर, डायग्नोस्टिक किट और इलाज की अनूठी दवाइयों, मास्क, पीपीई किट, ऑक्सीजन संयंत्र और हैंड सैनिटाइजर तक डीआरडीओ कोविड के खिलाफ जंग में मोर्चे पर था. डीआरडीओ की डिजाइन की हुई करीब 80,000 पीपीई अब रोज बनाई जा रही हैं. एचएलएल ने पिछले साल उद्योगों के लिए ऐसे 35 लाख से ज्यादा पीपीई सूट बनाए.

डीआरडीओ देश भर में ऑक्सीजन की कमी से निबटने की खातिर लड़ाकू विमानों के लिए डिजाइन की गई मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहा है. ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जेनरेशन सिस्टम (ओबीओजीएस) वातावरण की हवा को खींचने और उसे स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस उड़ा रहे पायलटों के लिए ऑक्सीजन में बदलने के लिए बनाया गया था. ट्राइडेंट न्यूमैटिक्स और एलऐंडटी सहित कई निजी फर्म अब ये संयंत्र बनाती और लगाती हैं. वे कई साइज के हैं और अस्पतालों को प्रति मिनट 250, 500 और 1,000 लीटर ऑक्सीजन आपूर्ति कर सकते हैं. ■

एएनआइ

जांच बेंगलूरू रेलवे स्टेशन पर जांच में जुटे स्वास्थ्यकर्मी

जल्द और तेज कार्रवाई

कोविड-19 से जूझता सर्वश्रेष्ठ राज्य

विजेता: कर्नाटक

जीत की वजह: राज्य ने रिकवरी रेट, टीका कार्यक्रम में ऊंचे अंक हासिल किए. बेंगलूरू भारत का पूरी तरह टीकाकृत पहला शहर बना

अरविंद गौड़ा

कर्नाटक ने टेस्ट करने, सर्वश्रेष्ठ तरीके लागू करने, रिकवरी रेट और टीके लगाने सरीखे कई मानदंडों पर ऊंचे अंक हासिल किए. कई पहलकदमियों ने इसकी तस्दीक की. इनमें बेंगलूरू को भारत का पहला पूर्ण टीकाकृत शहर बनाने के लिए लसिका उत्सव आयोजित करना और फार्मा कंपनियों को अपने 2 प्रतिशत सीएसआर बजट का इस्तेमाल कोविड-19 टीकाकरण के लिए करने का निर्देश देना शामिल है. सितंबर के पहले हफ्ते तक राज्य के 4.60 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लग चुके थे.

राज्य के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ सुधाकर के. कहते हैं, ''कोविड से लड़ने में कर्नाटक की कामयाबी तीन-स्तरीय फलसफे का नतीजा है: जल्दी काम करो, तेजी से काम करो और बड़ा काम करो.'' वे कहते हैं, ''महामारी के खिलाफ लड़ाई में समय, रफ्तार और पैमाना बेहद अहम है और कर्नाटक ने इसका इंतजाम बहुत असरदार ढंग से किया. हमने जल्द लॉकडाउन लगाया. लॉकडाउन का ऐलान करने वाले हम पहले राज्य थे. कोविड का बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए हम तेजी से हरकत में आए. आखिर में हमने सब कुछ बड़े पैमाने पर किया, चाहे परीक्षण हो, लॉकडाउन, इन्फ्रास्ट्रक्चर या टीकाकरण.''

पहले चरण में टीके की पहली खुराक लगाने में कोविड के सबसे ज्यादा मामलों वाले राज्य के 23 जिलों को प्राथमिकता दी गई. यह सितंबर में प्राथमिकता पूरा हो गया. आइटी फर्म बड़ी तादाद में सरकार की सहायता से अपने कर्मचारियों को टीके की दोनों खुराकें लगा चुकी हैं. ■

बचाने की पहल

व्यापक सामाजिक असर के लिए बेहतरीन दूरगामी कॉर्पोरेट पहल

विजेता: विप्रो लिमिटेड, बेंगलूरू

क्यों जीता: विप्रो महामारी के दौरान खाद्य सामग्री, दवा, सुरक्षा किट, ऑक्सीजन और अस्पतालों में बिस्तर मुहैया कराके हजारों लोगों का सहारा बनी

एम.जी. अरुण

महामारी ने जिंदगियां और रोजी-रोजगार दोनों तबाह किए. ऐसे में, आइटी दिग्गज कंपनी विप्रो ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन (एपीएफ) के साथ कोविड राहत के मद में शुरुआत में 1,125 करोड़ रुपए खर्च किए और मई 2021 में टीकाकरण के लिए उसे बढ़ाकर 2,125 करोड़ रुपए कर दिया. करीब 1,600 लोगों की एपीएफ की टीम करीब 500 सिविल सोसायटी ग्रुप, 27 राज्यों तथा तीन केंद्रशासित प्रदेशों के स्थानीय प्रशासन, पब्लिक स्कूलों के शिक्षक और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों के साथ राहत कार्य में जुटी रही.

विप्रो के सस्टेनेबिलिटी-ग्लोबल हेड नारायण पी.एस. कहते हैं, ''फौरन मानवीय मदद और लंबे समय के लिए स्वास्थ्य संबंधी चुनौती से निपटने की दरकार थी.'' फौरन मानवीय मदद की मद में विप्रो ने खाद्य सामग्री, पका हुआ भोजन, सैनिटाइजर वगैरह मुहैया करने की मंजूरियां देने में तेजी लाई. उसके पुणे परिसर को 450 बेड वाले कोविड अस्पताल में बदला गया. वंचित इलाकों में डॉक्टरों और प्रशिक्षित नर्सों को नियुक्त किया गया. जयपुर, बेंगलूरू, भोपाल और यदगीर (कर्नाटक) में एंबुलेंस मुहैया कराई गई.

विप्रो ने जरूरतमंदों को 59.4 करोड़ खाद्य सामग्री/पके हुए भोजन के पैकेट बांटे. पके हुए भोजन की योजना बनाई गई और 24 घंटे के भीतर विशेष रेलगाड़ियों से बेंगलूरू छोड़कर जाने वालों में बांटे गए. तकरीबन 1.3 करोड़ राशन पैकेट, करीब 5,00,000 पीपीई किट/एन95 मास्क, करीब 30,000 ऑक्सीमीटर, 750 ऑक्सीजन सिलेंडर और 2,905 ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर बांटे गए. नारायण कहते हैं, ''हम दूरदराज के गांवों में कोविड के टीके लगाने के लिए हजारों लोगों के प्रशिक्षण का काम सहयोगियों के साथ कर रहे हैं.''■

बड़ा नेटवर्क मदद को उतरी विप्रो की कोविड टीम

मदद को तैयार
शिखर अग्रवाल (बाएं) और आदित्य मक्कड़

प्रशांत कुमार

तेज रफ्तार सायरन

बेहतरीन एंबुलेंस सेवा

विजेता: हेल्पनाऊ, मुंबई

क्यों जीता: कोविड मरीजों के लिए समर्पित एंबुलेंस से 24 घंटे मदद मुहैया कराई और एंबुलेंस पहुंचने के समय को 50 मिनट से घटाकर 20 मिनट किया

किरण डी. तारे

आदित्य मक्कड़ के पिता को 2016 में दिल का दौरा पड़ा और फौरन अस्पताल भागना पड़ा. वक्त पर कोई एंबुलेंस नहीं मिली तो परिवार वालों ने अपनी कार में ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया. 2019 में मक्कड़ ने आइआइटी, बंबई के अपने दोस्तों शिखर अग्रवाल और वेंकटेश अमृतवार के साथ मिलकर एंबुलेंस एग्रीगेटर हेल्पनाऊ की स्थापना की ताकि किसी को वह न झेलना पड़े जो उन्हें और उनके परिवार को झेलना पड़ा.

हेल्पनाऊ एंबुलेंस बुलाने की सेवा और एक केंद्रीय कॉल सेंटर बनाने के लिए कई एंबुलेस मुहैया कराने वालों से करार किया. कॉल सेंटर में रोजाना करीब 500 कॉल आती हैं. देश में दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में रोजाना करीब 2,000 फोन आए. अपनी शुरुआत से हेल्पनाऊ करीब 40,000 लोगों को मेडिकल सहायता और अगस्त तक 12,100 मरीजों को एंबुलेंस मुहैया करा चुका है.

सबसे बढ़कर, उन लोगों ने मुंबई के धारावी के लिए फंड जुटाने के अभियान के साथ सैनिटाइजेशन और खाद्य दान की पहल को तेज किया. उन लोगों ने मरीजों की बेहतर सेवा के लिए अस्पताल और कॉर्पोरेट फर्मों को जोड़ा. उन लोगों ने ऐसे लोगों को भी एंबुलेंस मुहैया कराई, जिसका खर्च उठाने की ताकत उनके पास नहीं थी. मुंबई में 350 एंबुलेंस के बेड के साथ हेल्पनाऊ शहर में सबसे बड़ी निजी एंबुलेंस सेवा है. उसने अपनी सेवाओं का पुणे, दिल्ली और बेंगलूरू में विस्तार किया. रोजाना जांच और सुरक्षा की सावधानियों का बारीकी से पालन किया जाता है. वायरस से हेल्पनाऊ के किसी भी ड्राइवर या वालेंटियर की जान नहीं गई है. ■

ताकि सांसों की कड़ी न टूटे

बेहतरीन ऑक्सीजन आपूर्ति पहल

विजेता: दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, नई दिल्ली

जीत की वजह: 'ऑक्सीजन लंगर सेवा' शुरू की और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड के सैकड़ों मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराई गई, महामारी के दौरान हर जरूरतमंद को भोजन और मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया

अनिलेश एस. महाजन

यासिर इकबाल

असरदार सेवा
डीएसजीएमसी ने दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में बनाए गए श्री गुरु तेगबहादुर कोविड केयर ऐंड ट्रीटमेंट सेंटर में कोविड मरीजों को इलाज उपलब्ध कराया

बंदीप सिंह

सम्मान से अंतिम संस्कार
दिल्ली के एक अंत्येष्टि स्थल पर जितेंद्र सिंह शंटी (17 मई 2021)

आखिरी सफर का हमसफर

अंतिम संस्कार में मदद के लिए विशेष अवार्ड

विजेता: शहीद भगत सिंह सेवा दल, नई दिल्ली

जीत की वजह: करीब 4,000 कोविड पीड़ितों के अंतिम संस्कार में मदद की

अनिलेश एस. महाजन

भाजपा के पूर्व विधायक और एनजीओ शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक तथा अध्यक्ष जितेंद्र सिंह शंटी की जिंदगी के सबसे दर्दनाक अनुभवों में एक कोविड पीड़ितों के अंतिम संस्कार में मदद मुहैया कराना था. कई मामलों में मृतकों के लिए परिवार,

राजधानी के गुरुद्वारों का प्रबंधन करने वाली दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (डीएसजीएमसी) पूरी कोविड-19 महामारी के दौरान सक्रिय रही और जरूरतमंदों की सेवा करता रही. इस कमेटी ने लोगों के घर तक लंगर सेवा मुहैया कराई. इसने कोविड पॉजिटिव हुए ऐसे परिवारों को भोजन मुहैया कराया, जो भोजन पकाने की स्थिति में नहीं थे.

कोविड की दूसरी लहर के दौरान देश में संक्रमण के मामलों में बेतहाशा उछाल देखा गया था और दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी किल्लत थी. डीएसजीएमसी ने ऐसे में अपने प्रयास तेज कर दिए और कई जगहों पर 'ऑक्सीजन लंगर सेवा' शुरू कर दी. श्रद्धालुओं से दान लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल किए गए और अस्पतालों से लौटाए गए लोगों को इन लंगरों में ऑक्सीजन मुहैया कराई गई.

इस कमेटी ने नई दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज के भाई लखी शाह वंजारा हॉल में 400 बिस्तरों की सुविधा शुरू की. इसे गुरु तेग बहादुर कोविड केयर ऐंड ट्रीटमेंट सेंटर नाम दिया गया और दिल्ली सरकार के चिकित्सा व्यवस्था सहयोग और लोगों के दान से इसकी स्थापना हुई. कोविड केयर सेंटर दस दिन के भीतर तैयार कर लिया लिया गया और राज्य सरकार ने यहां डॉक्टरों और नर्सों की तैनाती की जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मरीजों का इलाज यहां शुरू किया जा सका. ■

दोस्त और पड़ोसी अपनी वजह या देशव्यापी लॉकडाउन के कारण आगे नहीं आए. ऐसे मामलों में शंटी और उनके जरिए साल 1995 में स्थापित शहीद भगत सिंह सेवा दल के करीब 25 वालेंटियरों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया. अस्पताल या घरों से शवों को उठाना, उन्हें सैनिटाइज करना और पैकेट में बंद करके श्मशान तक वैन से पहुंचाने तक, वॉलंटियर करीब 4,000 कोविड पीड़ितों के अंतिम संस्कार में मदद के लिए दिन-रात जुटे रहे.

इस अभियान में शंटी के पूरे परिवार को दोबारा कोविड संक्रमण हो गया और उनके ड्राइवर की मौत भी हो गई. शंटी कहते हैं, ''एक मौके पर मेरा ब्लड प्रेशर 35 हो गया था. मेरे परिवार का मानना है कि उन लोगों की संवेदना ने मुझे बचा लिया, जिनकी मैंने मदद की.''

महामारी के दौरान इस एनजीओ के बेड़े में करीब 20 एंबुलेंस/गाड़ियां शामिल हो गईं. इस साल पहले जब दूसरी लहर चरम पर थी, इस एनजीओ ने हर रोज 125 अंतिम संस्कार में मदद की, रोज घरों से करीब 40 शव उठाए. शंटी याद करते हैं कि वह बड़ा मुश्किल दौर था, ''वह बड़ा दर्दनाक काम था, लेकिन किसी को तो करना ही था.'' ■

चंद्रदीप कुमार

सेवा सर्वोपरि सेव लाइफ फाउंडेशन के पीयूष तिवारी

ऑक्सीजन मसीहा

बेहतरीन ऑक्सीजन आपूर्ति पहल

विजेता: सेवलाइफ फाउंडेशन, नई दिल्ली

जीत की वजह: दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मेघालय और कर्नाटक में 3,018 जंबो डी-टाइप मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए, जिनमें कुल 99 मीट्रिक टन ऑक्सीजन थी

अनिलेश एस. महाजन

महामारी फैली तो सेवलाइफ फाउंडेशन फौरन युद्धस्तर पर सक्रिय हो गया. आपदा राहत, सैन्य आपूर्ति और आपात सेवा में विशेष दक्षता वाली एक टीम बनाई गई और उसे वैश्विक पैमाने पर मदद के लिए जोड़ा गया. दिल्ली में पहली लहर के दौरान ही नाकाफी एंबुलेंस तंत्र की बात साबित हो गई थी. सेवलाइफ फाउंडेशन के संस्थापक और सीईओ पीयूष तिवारी याद करते हैं, ''एंबुलेंस के पहुंचने में काफी वक्त लगता था. कई मामलों में एंबुलेंस के पहुंचने में 10 घंटे तक का समय लग गया.''

इस फाउंडेशन ने दिल्ली सरकार के 200 एंबुलेंस के बेड़े को बढ़ाने के लिए 400 एंबुलेंस वाहन निजी क्षेत्र से जुटाए. वहीं, डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल से एंबुलेंस पहुंचने का औसत समय 20 मिनट तक लाया जा सका.

दूसरी लहर मेडिकल ऑक्सीजन का एक और संकट ले आई. कोविड मरीजों का इलाज करने वाले दिल्ली के एक अस्पताल ने 23 अप्रैल को आपात संदेश दिया कि उसकी ऑक्सीजन आपूर्ति खत्म होने वाली है. ऐसे एसओएस कई दूसरे अस्पतालों से भी आए. तिवारी कहते हैं, ''23 अप्रैल और 3 मई के बीच दिल्ली अस्पतालों से मेडिकल ऑक्सीजन के लिए 500 एसओएस कॉल आईं, कई मामलों में मौतें हुईं, जिन्हें बचाया जा सकता था.''

इस फाउंडेशन ने यह भी पाया कि वर्षों से बनी ऑक्सीजन क्षमता ऑक्सीजन संकट के दौरान मांग बढ़ने से बुरी तरह ढह गई. दिल्ली में जो प्रयास शुरू किया गया, कुछ ही दिनों में 11 दूसरे राज्यों में भी उसका विस्तार किया गया. इस फाउंडेशन की मदद से दिल्ली सरकार ने करीब 6,000 टाइप-डी ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल किए, जिनकी कुल क्षमता 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की थी. इस फाउंडेशन ने 995 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हासिल किए और उन्हें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा गोवा में बांटा गया. ■

वक्त से आगे

सर्वश्रेष्ठ टीकाकरण अभियान वाला राज्य

विजेता: गुजरात

जीत की वजह: वयस्क आबादी के ज्यादातर लोगों का (पहली खुराक) टीकाकरण; बुजुर्गों, विकलांगों के लिए और आदिवासी इलाकों में विशेष टीकाकरण अभियान

किरण डी. तारे

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का एक दृश्य टीकाकरण के मामले में गुजरात की सफलता को बेहतरीन ढंग से बयान कर देता है. कुछेक वैक्सीन बूथ पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी यात्रियों से अपील करते हैं कि अगर उन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है तो अब अब लगवा लें. चंद मिनटों में टीका लगा दिया जाता है और उसके कुछ देर बाद यात्री अपनी राह लग लेते हैं. टीके की आसानी से उपलब्धता और उसे लगाने के प्रभावी तरीके ने राज्य की टीकाकरण दर पर खासा प्रभाव डाला है.

प्रदेश के 84 फीसद वयस्कों को पहली खुराक और 36 फीसद को दूसरी खुराक (26 सितंबर तक) लग जाने के साथ ही गुजरात सभी बड़े राज्यों के टीकाकरण चार्ट में अव्वल नंबर पर पहुंच गया है. इसका श्रेय राज्य के स्वास्थ्य विभाग की पहल को जाता है, जिसके तहत लोगों का टीकाकरण केंद्रों पर इंतजार करने के बजाए टीके को लोगों तक ले जाया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग के सचिव और निदेशक जयप्रकाश शिवहरे कहते हैं, ''हमने यह पक्का किया कि हमारे स्वास्थ्यकर्मी लोगों तक पहुंचें और उन्हें टीके की अहमियत समझाएं.''

गुजरात ने केंद्र की ओर से भेजे गए टीके का कुशल प्रबंधन किया और कोल्ड स्टोरेज तथा लाने-ले जाने की जबरदस्त व्यवस्था की बदलौत समाज के हर वर्ग तक इसे पहुंचा दिया. उसने आकर्षक नारों और प्रभावशाली लोगों के टीका लेने की तस्वीरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करके जागरूकता पैदा की. ■

प्रभावी रणनीति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के एक टीकाकरण केंद्र पर

एएनआइ

एएनआइ

जोरदार पहल

सर्वश्रेष्ठ टीकाकरण अभियान वाला राज्य

विजेता: केरल

जीत की वजह: स्थानीय निकायों को शामिल कर और मोबाइल टीकाकरण इकाइयां बनाकर जबरदस्त अभियान चलाया

जीमॉन जैकब

केरल में कोविड-पॉजिटिव का पहला मामला 30 जनवरी, 2020 को सामने आया जब मेडिकल का एक छात्र चीन के वुहान से त्रिशूर में घर लौटा. तभी से यह राज्य पूरी प्रतिबद्धता और जन समर्थन के साथ इस महामारी से लड़ने के मिशन पर है, जिनमें इस वायरस को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के आदेश पर कई बार लॉकडाउन लगाया गया. 26 सितंबर तक करीब 44.4 लाख लोग इस वायरस के कहर से उबर चुके थे, और करीब 1,62,000 लोग अपना इलाज करा रहे थे. राज्य में 28 मार्च, 2020 से 24,603 लोग कोविड की वजह से मर चुके हैं.

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के

मौके पर उपलब्ध
कोच्चि में टीकाकरण का एक दृश्य

मुताबिक, देश में प्रति दस लाख व्यक्ति पर सबसे ज्यादा टीका इसी राज्य में लगाया गया है. करीब 2.45 करोड़ लोगों को पहली खुराक और करीब 1.1 करोड़ को दोनों खुराक मिल चुकी है. उन्होंने 25 सितंबर को मीडिया को बताया, ''टीका लेने के बावजूद जिन लोगों की मौत हो गई उनमें से कई बुजुर्ग थे या उन्हें कई गंभीर बीमारियां थीं. इन आंकड़े संकेत करते हैं कि इस खतरनाक संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए टीकाकरण ही सर्वोत्तम इलाज है. टीकाकरण अस्पताल में भर्ती होने की संभावनाओं को कम कर देगा और जल्दी स्वस्थ होने में मदद करेगा. लिहाजा, मैं सबसे अपील करता हूं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवा लें. स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकाय लोगों की मदद से सौ फीसद टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं.'' उन्होंने लोगों को चेताया कि वे टीका लगवाने के बाद भी खुद को संक्रमण से बचाने के लिए कोविड-सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है, ''हम 18 साल से कम उम्र के लोगों को टीका लगवाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हम स्कूल खोलने जा रहे हैं. हमने इस काम के लिए आशाकर्मियों को लगाया है और स्थानीय निकायों से अपील की है कि वे व्यापक टीकाकरण अभियान चलाएं. हमने उन लोगों के टीकाकरण के लिए जोरदार अभियान चलाया जो बीमार हैं, और लोगों को टीका लगाने के लिए मोबाइल इकाइयां शुरू की.'' ■

मदद के मौके पर

सर्वश्रेष्ठ मानसिक स्वास्थ्य परामर्श

विजेता: द साइरस ऐंड प्रिया वंद्रेवाला फाउंडेशन

जीत की वजह: महामारी के दौरान इसने अपनी मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा को दस गुना बढ़ा दिया

सुहानी सिंह

बस एक फोन दूर फाउंडेशन के मुंबई ऑफिस में कर्मचारी; (ऊपर) साइरस और प्रिया वंद्रेवाला

महामारी शुरू होने से पहले तक साइरस ऐंड प्रिया वंद्रेवाला फाउंडेशन में 10 काउंसलर थे. अगले 18 महीनों के दौरान हेल्पलाइनों पर बढ़ती कॉल से निबटने के लिए उनकी संख्या दस गुना बढ़ा दी गई. इस फाउंडेशन के सीईओ डॉ. अरुण जॉन का कहना है, ''इस बीमारी, लॉकडाउन और भविष्य को लेकर लोगों में काफी बेचैनी थी. संबंधों और निजता के मसले भी खड़े हो गए; लोगों ने वित्तीय परेशानियों और नौकरी जाने की वजह से भी कॉल किया.''

फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में क्लाउड टेलीफोनी शुरू की ताकि निरंतर कनेक्टिविटी बनी रहे और यह पक्का हो कि सभी कॉल अटेंड की जा सकेगी. इसकी वजह से कॉल करने वाले की पसंदीदा भाषा में जवाब देना भी आसान हो गया. वेबसाइट चैट्स और व्हाट्सऐप काउंसलिंग भी शुरू की गई, जिससे ''युवा पीढ़ी'' के लिए खासकर परीक्षाओं और करियर की संभावनाओं से जुड़ी चिंताओं को जाहिर करने के लिए ''व्यापक रास्ता खुल गया.'' आत्महत्या की सोच रहे व्यक्तियों को बार-बार कॉल करने की भी व्यवस्था की गई.

हर महीने करीब 25,000 कॉल आती हैं. ऐसे में डॉ. जॉन को मालूम है कि उनके 123 काउंसलर और मनोवैज्ञानिकों का काम निकट भविष्य में कम नहीं होने वाला. उनमें से कुछ देर रात तक काम करते हैं क्योंकि रात में 2 बजे भी कॉल आ जाती है. दरअसल, वे इस फाउंडेशन में काउंसलर की तादाद अप्रैल 2022 तक 300 करने की योजना बना रहे हैं. इसके संस्थापकों में से एक प्रिया वंद्रेवाला का कहना है, ''बढ़ती जरूरतों के मद्देनजर हमने अपने कर्मचारियों की संख्या काफी बढ़ा दी, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में निवेश किया और अपनी सेवाएं बढ़ाना जारी रखा. हमने करीब 10 लाख परामर्श में हिस्सा लेकर मुफ्त परामर्श और संकट के समय मदद की.'' ■

मंजु मणि

आगे बढ़कर डॉ. देवी शेट्टी बेंगलूरू में कोविड का टीका लगवाते हुए

स्वास्थ्य देखभाल दुलार के साथ

निजी अस्पताल की ओर से सर्वश्रेष्ठ टीकाकरण अभियान

विजेता: नारायण हेल्थ (नारायण हृदयालय लिमिटेड) बेंगलूरू

जीत की वजह: झुग्गी बस्तियों, भवननिर्माण स्थलों और गांव में मुफ्त टीकाकरण. नारायण हेल्थ ने ट्रस्ट और आरडब्ल्यूए के साथ भी गठजोड़ किया, और अपने अभियान को व्यापक बनाने के लिए ग्राम पंचायतों तथा आशाकर्मियों को जोड़ा

अमरनाथ के. मेनन

मानवीय संवेदना के साथ स्वास्थ्य सेवा का प्रण करने वाला नारायण हेल्थ कोविड महामारी से लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर रहा है. उसने मुख्य ध्यान टीकाकरण पर लगाया और कुछ सबसे उपेक्षित समुदायों के बीच टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया.

इस स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के आइटी संचालित सेवाओं पर आधारित टीकाकरण कार्यक्रम में चौतरफा तरीका अपनाया गया: अस्पताल में फीस लेकर टीका लगाना; पार्टनर साइट्स पर टीकाकरण, जिसकी लागत अस्पताल और पार्टनर साइट ने साझा रूप से वहन किया; 'गेट वन गिव वन' टीकाकरण अभियान, जिसमें नारायण हेल्थ में टीका लगवाने वाला व्यक्ति किसी जरूरतमंद व्यक्ति को टीके की एक खुराक दान करता है; और वॉल्वो ग्रुप के साथ 'वैक्सीन ऑन व्हील्स' पहल ताकि कर्नाटक के उपनगरीय और ग्रामीण समुदायों तक पहुंचा जा सके.

संस्थापक-चेयरमैन डॉ. देवी शेट्टी का कहना है, ''हम वंचितों की जरूरतों को पूरी करने और पैसा देने वाले मरीजों को आला दर्जे की क्लीनिकल क्वालिटी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. नारायण हेल्थ में समाज को वापस देने के काम को प्राथमिकता दी जाती है.''

टीके के प्रति हिचक को मिटाने के लिए नारायण हेल्थ ने अपने सभी रोगियों को टीका लगाया, चाहे वे ओपीडी सेवाओं के लिए आएं या उसके अस्पतालों में भर्ती हो रहे हों. उसने सभी जगहों पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करके सुरक्षित टीकाकरण की व्यवस्था की.

यह नेटवर्क स्वास्थ्य सेवा के लिए भुगतान के नए मॉडल अपनाता रहा है. इसने कर्नाटक में 'माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम' शुरू की, जिसने राज्य सरकार को ग्रामीण किसानों के लिए यशस्विनी माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस योजना शुरू करने के लिए प्रेरित किया. यह नए जमाने का हॉस्पिटल ऑपरेटिंग सिस्टम भी तैयार कर रहा है. ■

तेज और कुशल

निजी अस्पताल की ओर से सर्वश्रेष्ठ टीकाकरण

विजेता: सर एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल ट्रस्ट, मुंबई

जीत की वजह: कारगर और लोगों के अनुकूल ऐसा टीकाकरण अभियान चला रहा है जिसमें सितंबर तक करीब दस लाख लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है

किरण डी. तारे

तकनीक आधारित व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के जरिए कूपन देने और टीकाकरण का तय बूथ बताने का काम किया जाता है, दोस्ताना रवैए वाला स्टाफ, टीका लेने वाले का ब्लड प्रेशर और शरीर का तापमान देखा जाता है, और टीके के सर्टिफिकेट की प्रिंटेड कॉपी फौरन थमा दी जाती है. ये कुछ ऐसी खूबियां है जिसकी वजह से मुंबई में सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल (आरएफएच)

मिलिंद शेलटे

का टीकाकरण अभियान दूसरों से अलग है. व्यापक इन-हाउस और आउटरीच प्रोग्राम की बदौलत आरएफएच ने सितंबर तक करीब दस लाख लोगों को कोविड का टीका लगा दिया.

इस अस्पताल को चलाने वाले रिलायंस फाउंडेशन के 'मिशन वैक्सीन सुरक्षा' अभियान के तहत कर्मचारियों, पार्टनरों, एसोसिएट और उनके परिजनों के लिए मुफ्त टीकाकरण शुरू किया गया. स्वयंसेवी संगठनों और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) तथा केरल सरकार जैसी सरकारी एजेंसियों के साथ देशभर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है.

रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का कहना है कि वे इस मुसीबत की घड़ी में भारतीयों की मदद करने के लिए जो कर सकते हैं, करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा, ''हमने देशभर में टीकाकरण अभियानों के जरिए इस वायरस के खिलाफ देश के संघर्ष को ताकतवर बनाना जारी रखा है.''

आरएफएच के सीईओ डॉ. तरंग ज्ञानचंदानी इस प्रक्रिया को समझाते हैं. वे बताते हैं, ''हमने हर वैक्सिनेशन बूथ का आउटपुट अधिक रखने की खातिर तेजी से टीककरण सुनिश्चित करने के लिए एसेंबली लाइन मॉडल—टीका लेने वालों के रजिस्ट्रेशन से लेकर टीके के बाद की निगरानी तक—तैयार किया.'' ■

बनाई मिसाल सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल का टीकाकरण केंद्र

बच्चों की देखभाल वर्ल्ड विजन इंडिया के सीईओ माधव बेलमकोंड (सफेद और गुलाबी कपड़े में)

बालगोपाल की फिक्र

सर्वश्रेष्ठ बाल चिकित्सा सेवा/मदद

विजेता: वर्ल्ड विजन इंडिया

जीत की वजह: बाल कल्याण की दिशा में काम करने और स्वास्थ्य, पोषण तथा मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदद और देखभाल करने के लिए

रोमिता दत्ता

वर्ल्ड विजन इंडिया ने 25 राज्यों में अपनी मौजूदगी के साथ ही महामारी के दौरान बच्चों के लिए काम करने को प्राथमिकता दी. इस वायरस ने सबसे ज्यादा संवेदनशील बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित किया और इस संगठन ने उन तक पहुंचने की जरूरत को भांप लिया.

चेन्नै में मुख्यालय वाले वर्ल्ड विजन इंडिया ने मार्च 2020 में कोविड महामारी शुरू होने के समय से ही स्वास्थ्य सेवा, पोषण, शिक्षा, जल, सैनिटेशन और साफ-सफाई के क्षेत्र में 16.8 लाख बच्चों तक अपनी सेवाएं पहुंचाई. इसके अलावा, वे बच्चों की मानसिक-सामाजिक मदद भी कर रहे हैं और चाइल्ड ट्रैफिकिंग तथा यौन शोषण से उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं, जिनके मामले महामारी के दौरान बढ़ गए हैं. वर्ल्ड विजन इंडिया ने गर्भवती महिलाओं और जच्चा के लिए टेली-काउंसलिंग भी शुरू की, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया.

इस संगठन ने केंद्र को एक टोल-फ्री नंबर (1098) शुरू करने के लिए चाइल्डफंड इंडिया, सेव द चिल्ड्रेन इंडिया, प्लान इंडिया और एसओएस चिल्ड्रेंस विलेजेज ऑफ इंडिया के साथ काम किया. इमरजेंसी की घड़ी में बच्चे इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. वर्ल्ड विजन इंडिया ने समुदायों, युवाओं, धार्मिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाज के प्रमुख व्यक्तियों को जोड़कर टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में बड़ी भूमिका भी निभाई. इसमें करीब तीन करोड़ लोगों को शामिल किया गया और उन्हें टीके के लिए मानसिक रूप से तैयार किया गया. ■

समाज सेवा

सेलेब्रिटी जिन्होंने महामारी के दौरान अनुकरणीय कार्य किया

विजेता: अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना

जीत की वजह: अपने वित्तीय योगदान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल संसाधन जुटाने के वास्ते करने के लिए

सुहानी सिंह

अक्षय कुमार महामारी के दौरान कई लोगों के लिए असल जिंदगी के हीरो बन गए. उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपए तो दिए ही, राष्ट्रीय लॉकडाउन की वजह से आजीविका गंवा बैठे सिने ऐंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के 1,500 दिहाड़ी कामगारों की मदद के लिए 45 लाख रुपए का योगदान भी किया. 2020 में उन्होंने पीपीई किट, मास्क और रैपिड टेस्टिंग किट खरीदने में मदद के लिए मुंबई पुलिस को 2 करोड़ रुपए और इसके अलावा बृहन्नमुंबई नगर निगम को भी 3 करोड़ रुपए दान दिए. कुमार और उनकी पत्नी, अभिनेत्री से लेखिका बनी ट्विंकल खन्ना ने दूसरी लहर के दौरान अपनी कोशिशें बढ़ाते हुए दिल्ली के उदय और हेमकुंट फाउंडेशनों और पंजाब के खालसा ऐड इंडिया को 100 ऑ सीजन कंसंट्रेटर भी प्रदान किए. खन्ना ने सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करते हुए हेल्प इंडिया ब्रीद अभियान को चंदा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और ऑ सीजन कंसंट्रेटर के लिए 1 करोड़ रुपए उगाहने में मदद की. ■

जोड़ी नंबर-1 अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना

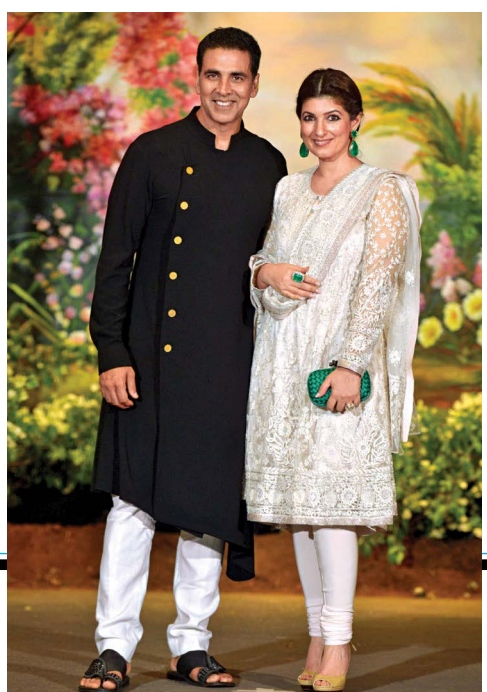

मिलिंद शेल्टे

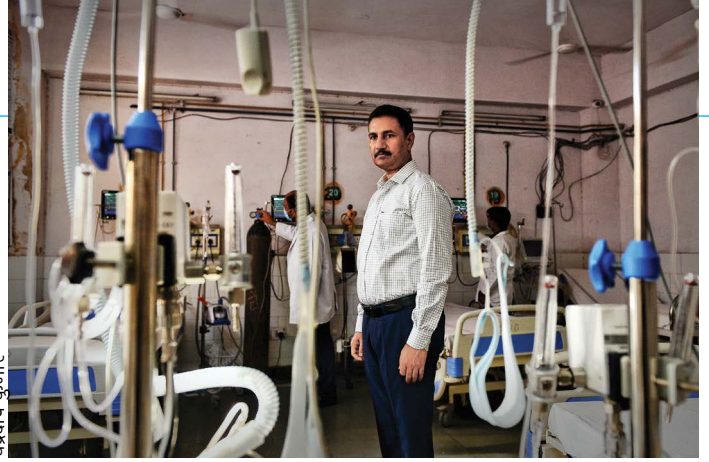

चंद्रदीप कुमार

लंबी छलांग गाजियाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह जिले के एक अस्पताल में

सुरक्षा की मजबूत दीवार

कोविड-19 से लड़ने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला

विजेता: गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

जीत की वजह: टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के मंत्र को अपनाते हुए वायरस का पीछा किया; सर्वे में उन परिवारों को जहां बुखार के मरीज थे, बुनियादी दवाओं की किट दी गई जिससे उनकी हालत गंभीर होने से बची; और युद्धस्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया

मनीष दीक्षित

चालीस लाख की आबादी वाले गाजियाबाद की कोरोना से लड़ने की चुनौती इसलिए भी कठिन हो गई थी क्योंकि यहां के अस्पतालों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों से मरीजों का आना जारी था. लेकिन टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के बुनियादी सिद्धांत को अपनाते हुए गाजियाबाद ने कोविड से लड़ने में आश्चर्यजनक कामयाबी हासिल की.

डेढ़ साल पहले शून्य टेस्ट क्षमता वाले जिला अब 1500 टेस्ट रोज करने की क्षमता हासिल कर रहा है. गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के उन गिने-चुने जिलों में शामिल है जहां दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत सबसे पहले खत्म की गई. गाजियाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह कहते हैं कि 11 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं जिनसे 4000 एलपीएम (लीटर प्रति मिनट) ऑक्सीजन मिल सकेगी. अब जिले में करीब 366 ऑक्सीजन बेड नगर निगम क्षेत्र में और 150 बेड ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं जिनमें आइसीयू बेड भी शामिल हैं.

जिले में जोर-शोर से चल रहे टीकाकरण ने भी कोविड को काबू करने में मदद की है. रिकॉर्ड के मुताबिक, गाजियाबाद में वयस्कों की आबादी 27 लाख है जिसमें 20 लाख से ज्यादा को टीके की एक डोज लग जुकी है जबकि 7.5 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं. गाजियाबाद 110 केंद्रों और करीब 550 स्टाफ के साथ एक दिन में 1.09 लाख टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर चुका है.

तीसरी लहर में प्रशासन का पूरा ध्यान 18 वर्ष से कम के 13 लाख बच्चों को पर है. बच्चों के आइसीयू (पीकू और नीकू) का इंतजाम कर लिया गया है. अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी टैबलेट से लैस कर दिया गया है जिससे वे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य की जानकारी ऑनलाइन कर देंगी. ■

पड़ोस का भी मददगार

कोविड-19 से लड़ने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला

विजेता: फरीदाबाद, हरियाणा

जीत की वजह: फरीदाबाद भारत के सबसे ज्यादा रिकवरी रेट वाले जिलों में है और महामारी की दूसरी लहर के दौरान जब अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने की कगार पर पहुंच गईं तो यह एनसीआर के दूसरे क्षेत्रों—दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम—को भी सहारा दिया

अनिलेश एस. महाजन

कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान जब मामलों में तेज उछाल आया, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अस्पतालों से आग्रह किया गया कि वे दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा सहित एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के दूसरे इलाकों के अस्पतालों के खचाखच भरे होने के कारण यहां के कुछ मरीजों को अपने यहां भर्ती कर लें.

इस औद्योगिक शहर ने न केवल अस्पतालों में मरीजों की सहायता और ऑ सीजन आपूर्ति में सुधार के लिए, बल्कि खाद्य वितरण कार्य योजना और दरवाजे-दरवाजे ऑ सीजन रिफिलिंग व्यवस्था सरीखी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए भी तकनीक का इस्तेमाल किया. यहां कोविड-19 केसों का जल्द पता लगाने के लिए 20 लाख लोगों का एक विशेष सर्वे हुआ. फरीदाबाद में 1 सितंबर तक कुल 99,827 मरीजों में 99,105 ठीक हो चुके थे. यह 99.28 प्रतिशत रिकवरी रेट और 0.72 फीसद की मृत्यु दर है, जो भारत के सबसे अच्छे रिकॉर्ड में है. इस साल 6 सितंबर तक टीके की 16 लाख खुराकें लगाई जा चुकी थीं. उम्मीद है कि नवंबर तक जिले में पूर्ण टीकाकरण हो जाएगा. ■

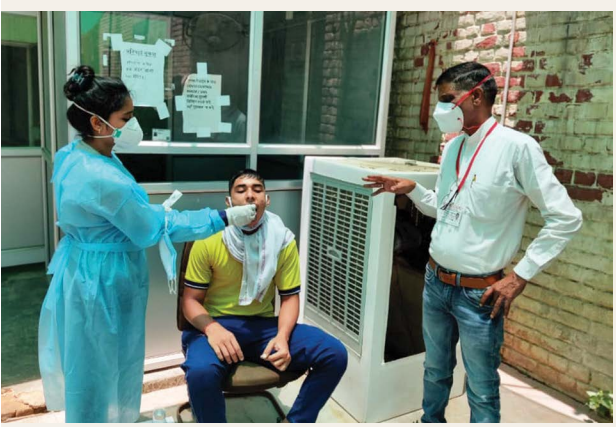

लक्ष्य की ओर फरीदाबाद में कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर

राजवंत रावत

ऊंचा लक्ष्य
आइजीएसएसएस के दिल्ली ऑफिस में जॉन पीटर नेल्सन

कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य सेवा देने वाला सर्वश्रेष्ठ एनजीओ या अन्य संस्था

विजेता: इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, नई दिल्ली

जीत की वजह: 21 राज्यों में 28 जिलों के करीब 16 लाख खासकर ग्रामीण गरीब लोगों को कोविड राहत और भला-चंगा होने में सहायता प्रदान की

मिशन मानकर सेवा

सोनाली आचार्जी

इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी (आइजीएसएसएस) लाभ-निरपेक्ष संगठन है जिसका जोर स्थायी आजीविका, शहरी गरीबी कम करने, युवाओं को चेंजमेकर के रूप में ताकतवर बनाने और लैंगिक समानता पर है. 1960 में बने आइजीएसएसएस की मौजूदगी 25 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में है.

महामारी के दौरान आइजीएसएसएस ने न केवल जरूरतमंदों को राशन और अनिवार्य उपकरण बांटने में बल्कि ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने, आजीविकाएं बहाल करने और स्वास्थ्य, सरकारी सहायता तथा कोविड टीके के बारे में जागरूकता फैलाने में भी मदद की.

आइजीएसएसएस कुल 21 राज्यों के 98 जिलों में 16 लाख लोगों तक राहत और स्वास्थ्य लाभ सहायता लेकर पहुंचा. संगठन ने अब तक करीब 18 लाख मास्क, 3,00,000 सेनिटाइजर, 60,000 सुरक्षा किट, 1,00,000 राशन किट और 66.5 लाख रुपए की अनिवार्य दवाइयां बांटी हैं. अनेक राज्यों के 500 कोविड टीका शिविरों की सहायता करने के अलावा इसने दो कोविड आइसोलेशन केंद्र और एक टीकाकरण केंद्र स्थापित करने में भी मदद की. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उनकी जरूरत के मुताबिक चिकित्सा उपकरण भेजे गए. इससे ग्रामीण गरीबों को कोविड स्वास्थ्य देखभाल घर के नजदीक हासिल करने में मदद मिली.

संस्था ने महामारी पर काबू पाने के लिए लोगों को कोविड की रोकथाम के नियम-कायदों, लक्षणों और टीके के बारे में जागरूक बनाने की अहम जरूरत पूरी की. इसने कई जन जागरूकता शिविर लगाए, जिन्होंने झुग्गी बस्तियों और गांवों के 5,00,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रहने में मदद की. ■

भारत का शस्त्रागार

कोविड वैक्सीन के विकास और उत्पादन में असाधारण योगदान

विजेता: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे

जीत की वजह: जनवरी मध्य से अगस्त की शुरुआत के बीच कोविशील्ड की करीब आधी अरब या पचास करोड़ खुराकें देने और इसे भारत की वयस्क आबादी को टीके लगाने की केंद्र की कोशिश में अहम हिस्सा बनाने के लिए. एसआइआइ ने निर्यात के लिए भी लाखों खुराकें दीं और दूसरी फर्मों के साथ भागीदारी में नए टीके विकसित कर रहा है

सोनाली आचार्जी

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआइआइ) ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में से एक के तौर पर 12 जून को 55 साल पूरे किए. यह किसी भी टीके की करीब 1.5 अरब खुराकें हर साल बना सकता है. इसके पास ऐसी मशीनें हैं जो हर मिनट में 500 कांच की शीशियां भर देती हैं. इसके फौलादी बायोरिएक्टर करीब दो मंजिल ऊंचे हैं, जो हर माह 1 करोड़ से ज्यादा खुराकों का निर्माण कर सकते हैं. यह संस्था चेचक और टीबी जैसे मर्ज के खिलाफ 100 से ज्यादा देशों में दुनिया के 65 फीसद बच्चों को टीके लगाने में मदद करती है.

कोविड के खिलाफ टीकाकरण न केवल गंभीर बीमारी की संभावना को बड़ी हद तक कम करने बल्कि इसके संक्रमण की तेजी से फैलती श्रृंखला तोड़ने के लिए बेहद अहम है. एसआइआइ ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शुरू से ही अग्रणी भूमिका निभाई. 16 जनवरी और 5 अगस्त के बीच इसने देश कोविशील्ड की 44.40 खुराकें वितरित दी हैं. एसआइआइ हर महीने 11 करोड़ टीके बना रहा है और उत्पादन को 12 करोड़ प्रति माह से ज्यादा बढ़ाने की योजना बना रहा है. साल के अंत तक 1.3 अरब टीकों के सरकार के लक्ष्य पूरा करने के लिए यह अगस्त और दिसंबर 2021 के बीच भारत को टीके की 50 करोड़ खुराक देगा.

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं समेत इंडस्ट्री ने मिलकर टीकाकरण को तेज रफ्तार देने के लिए सीआइआइ के साथ भागीदारी कायम की है. व्यापक रूप से लोगों का टीकाकरण पक्का करने के लिए अभियान का लक्ष्य भारत के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के समुदायों तक पहुंचना है. सीआइआइ के साथ भागीदारी कमियों को पूरा करने और कोविड टीकों को बराबर बंटवारा पक्का करने का अच्छा तरीका है. एसआइआइ ने जनवरी और फरवरी के बीच दूसरे देशों को भी 6 करोड़ टीके निर्यात किए. यह

टीके का हरावल दस्ता

कोविड वैक्सीन के विकास और उत्पादन में असाधारण योगदान

विजेता: भारत बायोटेक, हैदराबाद

जीत की वजह: कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 70 करोड़ खुराकों तक बढ़ाई; 2021 के अंत तक साल में एक अरब खुराक के उत्पादन का लक्ष्य

अमरनाथ के. मेनन

कोवैक्सीन भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड (बीबीआइएल) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के मातहत कार्यरत राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे के बीच सार्वजनिक-निजी भागीदारी की कामयाब कहानी साबित हुई है. यह कोविड-19 के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है. बीबीआइएल इन दिनों सेंट लुइस स्थित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर कोविड की एक नई एडीनोवायरस वेक्टर्ड, नाक से दी जाने वाली वैक्सीन 'बीबीवी154' पर भी काम कर रहा है.

बीबीआइएल की स्थापना डॉ. कृष्णा एम. इल्ला और उनकी पत्नी सुचित्रा इल्ला ने 1996 में की थी. वे नवोन्मेषी टीकों और जैवचिकित्साओं के सृजन के लिए अमेरिका में अपना सफल करियर छोड़कर लौटे थे.

हैदराबाद में जीवन विज्ञान का सबसे बड़ा क्लटस्टर जीनोम वैली स्थापित करने के पीछे डॉ. कृष्णा इल्ला ही उत्प्रेरक रहे हैं.

बीस करोड़ डॉलर (1,480 करोड़ रुपए) से ज्यादा के निवेश से स्थापित बीबीआइएल ने बीते ढाई दशकों में नवाचार का प्रभावशाली

व्यापक असर एसआइआइ में वैक्सीन का उत्पादन (ऊपर) और कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला (दाएं)

उसने कोवैक्स सुविधा के माध्यम से किया, जो वैक्सीन गठबंधन गावी और डब्ल्यूएचओ की अगुआई में विश्वव्यापी पहल है और जिसका उद्देश्य देशों के टीकों का समतामूलक बंटवारा करना है. एसआइआइ ने कोविड के खिलाफ दूसरे टीके बनाने के लिए भी भागीदारी की है. जून 2021 में इसने पुणे के संयंत्र में अमेरिकी फर्म नोवोवैक्स की ओर से विकसित वैक्सीन कोवोवैक्स का उत्पादन शुरू किया. कोवोवैक्स ने तीसरे चरण के परीक्षण जून मध्य में 90 फीसद प्रभाव क्षमता के साथ पूरे किए. एसआइआइ ने इन दिनों विकसित की जा रही एक और कोविड-19 वैक्सीन के लिए ऑस्ट्रेलिया की बायोटेक कंपनी थेमिस बायोसाइंसेज के साथ भी हाथ मिलाया है. ■

देश का गौरव भारत बायोटेक लैब में डॉ. कृष्णा इल्ला

ट्रैक रिकॉर्ड कायम किया है, जिसके पास डब्ल्यूएचओ की प्री-क्वालिफिकेशन के अलावा 145 से ज्यादा ग्लोबल पेटेंट, 16 से ज्यादा टीकों का व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो, चार जैवचिकित्साएं और 123 से ज्यादा देशों में पंजीकरण हैं.

कंपनी ने इंफ्लुएंजा एच1एन1, रोटावायरस, जापानी एनसेफ्लाइटिस, रैबीज, चिकुनगुनिया, जीका और टायफाइड के लिए दुनिया का पहला टिटैनस-टॉक्साइड संयुक्त टीका विकसित किया है. इसने दुनिया भर में टीकों की छह अरब से ज्यादा खुराकें भेजी हैं. ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन से रैबीज वैक्सीन संयंत्र, चिरोन बेहरिंग का अधिग्रहण करके बीबीआइएल 2019 में दुनिया की सबसे बड़ी रेबीज टीका निर्माता कंपनी बन गई. बीबीआइल के चेयरमैन और एमडी डॉ. कृष्णा इल्ला कहते हैं, ''कोवैक्सीन के विकास की यात्रा को ही देखें तो हमारा उद्देश्य भारतीय विज्ञान (की क्षमताओं) और सुरक्षित, विश्वस्तरीय तथा सस्ती वैक्सीन के जरिये महामारी से निपटने का ज्ञान सिद्ध करके दिखाना था.'' ■

और अंत में

गुमनाम हीरो के लिए विशेष अवार्ड

विजेता: गुरुप्रसाद मोहपात्रा, दिल्ली

जीत की वजह: महामारी की दूसरी लहर के शिखर दिनों में चिकित्सा ऑक्सीजन के उत्पादन और अस्पतालों को उसकी आपूर्ति में आ रही समस्याएं दूर करने में कर्तव्य के प्रति अपने समर्पण के लिए

अनिलेश एस. महाजन

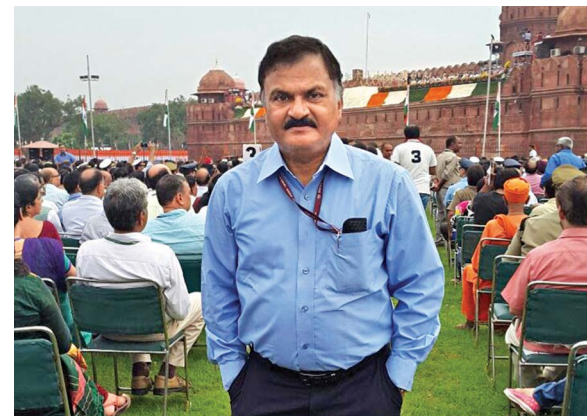

मुस्तैद डीपीआइआइटी सचिव गुरुप्रसाद मोहपात्रा

दूसरी लहर जब पूरे जोर थी, देश भर के अस्पताल ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति से जूझ रहे थे और मरीज एक-एक सांस के लिए तड़प रहे थे. अगर ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने और उसे चिकित्सा सुविधा केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था आसान बनाने में भारत ने कोई कामयाबी हासिल की, तो उसका बहुत सारा श्रेय एक शख्स को जाता है और वे हैं—दिवंगत गुरुप्रसाद मोहपात्रा, जो उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) को सचिव थे. वे अस्पतालों को ऑक्सीजन की सहज आपूर्ति के लिए बनी अधिकारप्राप्त समिति के अध्यक्ष भी थे.

अपने जीवन के आखिरी दौर में मोहपात्रा कोविड से संक्रमित हो गए. अपने आखिरी महीनों में तेज बुखार से ग्रस्त होने के बावजूद वे सातों दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध रहे, वर्चुअल बैठकों में हिस्सा लेते रहे और ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था की गड़बड़ियां दूर करने में जुटे रहे. 19 अप्रैल को उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और दो महीनों बाद वे कोविड-10 से पैदा परेशानियों के आगे जिंदगी हार गए. वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आने और अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने सरकारी कर्तव्य पूरे करते रहे. कर्तव्य के प्रति उनका यह समर्पण ही था जिसकी बदौलत अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था में उत्पन्न गड़बड़ियों को यथासंभव जल्द से जल्द दुरुस्त किया जा सका. ■

इंडिया टुडे RPG खुशी की खोज

जैविक कृषि में जो ढूंढते हैं *आनंद*

खुशी की सौगात: *किसानों को जैविक कृषि अपनाने के लिए तैयार करना और उनकी आय बढ़ाने में मददगार बनना*

अनिलेश एस. महाजन

उमेंद्र दत्त, 58

खेती विरासत मिशन

जैतू, जिला फरीदकोट, पंजाब

सुबह जल्दी उठना, डायरी से नंबर निकालकर पांच नए लोगों को फोन करके जैविक और प्राकृतिक खेती पर चर्चा करना, 58 वर्षीय उमेंद्र दत्त की पिछले 25 वर्षों से यही दिनचर्या है. कृषि पर चर्चा के लिए वे किसानों ही नहीं, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों, नागरिक समाज समूहों, यहां तक कि राजनेताओं को भी फोन करते हैं. उनका जोर खेती के ऐसे तरीकों को बढ़ावा देने पर है जिसमें रासायनिक अपशिष्ट बिल्कुल न हो.

पंजाब के फरीदकोट जिले के एक शांत छोटे-से शहर जैतू में रहने वाले दत्त ने अपना पूरा जीवन सभी प्रकार के किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत भूमिधारकों, भूमिहीन मजदूरों और यहां तक कि घरेलू बागबानी करने वालों को खेती की इस पद्धति से परिचित कराने के लिए समर्पित कर दिया है. उनका प्रयास इसलिए भी खास हो जाता है, क्योंकि पंजाब में बाजार में आने वाली 85 प्रतिशत फसलों की खरीद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) और भारतीय कपास निगम (सीसीआइ) जैसी केंद्रीय एजेंसियां कर लेती हैं, इसलिए वहां उपज बढ़ाने के लिए कीटनाशकों और उर्वरकों का भारी मात्रा में उपयोग होता है. इससे न केवल मिट्टी और भूजल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को भी बड़ा नुक्सान हो रहा है.

दत्त ने 20,000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया है जो अब लगभग 15,000 एकड़ में जैविक फसलें उगाते हैं. अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए दत्त कहते हैं कि पंजाब में लाखों किसान राज्य की कुल 42 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हैं और उसे देखते हुए जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या भले ही छोटी हो सकती है ''लेकिन परिवर्तन तो बड़ा है.''

दत्त 1996 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक पत्रिका के संपादक हुआ करते थे. उसी दौरान उन्होंने कृषि पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौतों के प्रभाव पर शोध करना शुरू किया. इसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया. यह वह समय था जब अधिकांश कृषि विशेषज्ञ दिल से सिफारिश कर रहे थे कि पंजाब के किसानों को पैदावार बढ़ाने को उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए. वे बताते हैं, ''मैंने नौकरी छोड़ दी और जैविक कृषि को ज्यादा गहराई से सीखने-समझने का फैसला किया. गृहनगर लौटा और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का फैसला किया.'' वे कहते हैं, उस समय कृषि विशेषज्ञ तब उन्हें 'पागल आदमी कहते थे लेकिन आज मैं एक

खुशी का मंत्र

''हम इनसान प्रकृति का एक हिस्सा हैं, इसलिए प्रकृति के खिलाफ हिंसा भगवान के खिलाफ हिंसा है. प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है. और बदले में प्रकृति हमें हमेशा तृप्ति, आनंद और आध्यात्मिक जुड़ाव की भावना से भर देती है''

खुशहाली के बीज
उमेंद्र दत्त जैविक कृषि अपनाने वाले किसानों के बीच

प्रगतिशील किसान माना जाता हूं' 2005 में, दत्त ने जागरूकता पैदा करने और यह दिखाने के लिए कि कैसे जैविक खेती सफल और धरती के लिए अच्छी हो सकती है, खेती विरासत मंच (केवीएम) नामक एक गैर सरकारी संगठन शुरू किया.

दत्त महीने में 15-18 गांवों में वर्कशॉप करते हैं. वे बताते हैं, ''मैंने जल्दी ही महसूस किया कि छोटे किसान पारंपरिक खेती से आसानी से बाहर आ सकते हैं. मैंने उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया.'' सबसे ज्यादा उत्साह महिला किसानों ने दिखाया. वे कहते हैं, ''पुरुष का सारा गुणा-भाग पैदावार के इर्दगिर्द होता है, जबकि महिला किसानों के लिए सुख ज्यादा अहम है. भले वे भूमिहीन मजदूर हों पर इसकी अहमियत समझती हैं.''

दत्त बरनाला, मुक्तसर और फरीदकोट जिलों के 60 गांवों में भूमिहीन किसानों के बीच जैविक किचन गार्डन की अवधारणा को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि वे अपना पेट भर सकें और जो अधिशेष हो उसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा सकें. पर यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहा है जिन्होंने इसे चुना है. बरनाला के भोटना गांव की भूमिहीन किसान जगमीत कौर कहती हैं, ''शुद्ध सब्जियों से हमें न केवल बेहतर कीमत मिलती है, बल्कि हमें ऐसे पक्के ग्राहक भी मिल जाते हैं जो अपने भोजन में कीटनाशक और खतरनाक रसायन नहीं चाहते.'' उनके पति निर्मल, जो खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं, अब अपनी उपज बाजारों में बेचते हैं. पंजाब के बड़े धार्मिक डेरे और सामाजिक ट्रस्ट भी अब जैविक खेती को अपना रहे हैं और दत्त उनके पसंदीदा व्यक्ति हैं.

दत्त कहते हैं कि पंजाब में जैविक खेती को बढ़ावा देना मुश्किल तो है लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसे यहां किया न जा सके. उनका कहना है कि बहुत से किसान उनकी चर्चाओं और कार्यशालाओं में शामिल होते हैं, लेकिन चंद लोग ही नए तरीकों को अपनाते हैं. दत्त कहते हैं, ''वे एक बाजार और विपणन तंत्र की तलाश कर रहे हैं. एक एनजीओ के रूप में हम 22 अलग-अलग शहरों में साप्ताहिक किसान हाटों का आयोजन करते हैं. हमने कुछ दुकानदारों को विशेष स्टोर स्थापित करने के लिए भी प्रशिक्षित किया है जहां केवल जैविक किसानों की उपज बेची जाती है.'' ऐसे पंद्रह स्टोर अभी खुले हैं. ■

मुझे खुशी *कैसे मिलती है*

सोनाली कुलकर्णी
अभिनेत्री

''छोटी-छोटी चीजों से मुझे बड़ी खुशी मिलती है. मसलन, सुबह की पहली चाय, मेरी फ्लाइट समय से उड़ना. मेरी बेटी जब चिट्ठी लिखती या चित्र बनाती है या जब मैं पति के लिए खाना बनाती हूं, तो मुझे खुशी होती है. मैं पानी या बिजली बचाती हूं तो मुझे खुशी होती है. मेरा को-ऐक्टर अच्छा शॉट दे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे हर दिन से बड़ी उम्मीदें नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम एक सही और पारदर्शी संवाद चैनल रखते हैं क्योंकि परेशानियां अक्सर छोटी गलतफहमियों से ही शुरू होती हैं.''

खुश होने के नुस्खे

डॉ. विनोद कुमार (मनोरोग चिकित्सक), प्रमुख, एमपावर-द सेंटर, बेंगलूरू

''खुशी एक अतींद्रिय अवधारणा है. अनादि काल से सुख को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता रहा है. लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति काव्यात्मक, दार्शनिक, समाजशास्त्रीय या अपने परिप्रेक्ष्य में मनोवैज्ञानिक है या नहीं. मोटे तौर पर खुशी का वर्गीकरण आनंद-उन्मुख या उद्देश्य-उन्मुख के रूप में किया जा सकता है. सकारात्मक मनोविज्ञान आंदोलन लगातार यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि लोग कैसे खुश होते हैं—या कोई विश्वास, व्यक्तित्व लक्षण या कोई अन्य तरीका है जो लोगों को अधिक सकारात्मक अनुभव प्रदान कर सकता है. हाल के कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि दैनिक जीवन की साधारण और छोटी-छोटी चीजों जैसे तारीफ या अप्रत्याशित उपहार मिल जाने से लोगों को बहुत खुशी मिलती है. अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि अधिक विकल्प अधिक अप्रिय अनुभवों की ओर ले जाते हैं. ये निष्कर्ष कितने ही भरोसेमंद लगते हों, सकारात्मक मनोविज्ञान तो अभी भी अपनी शैशव अवस्था में है.''

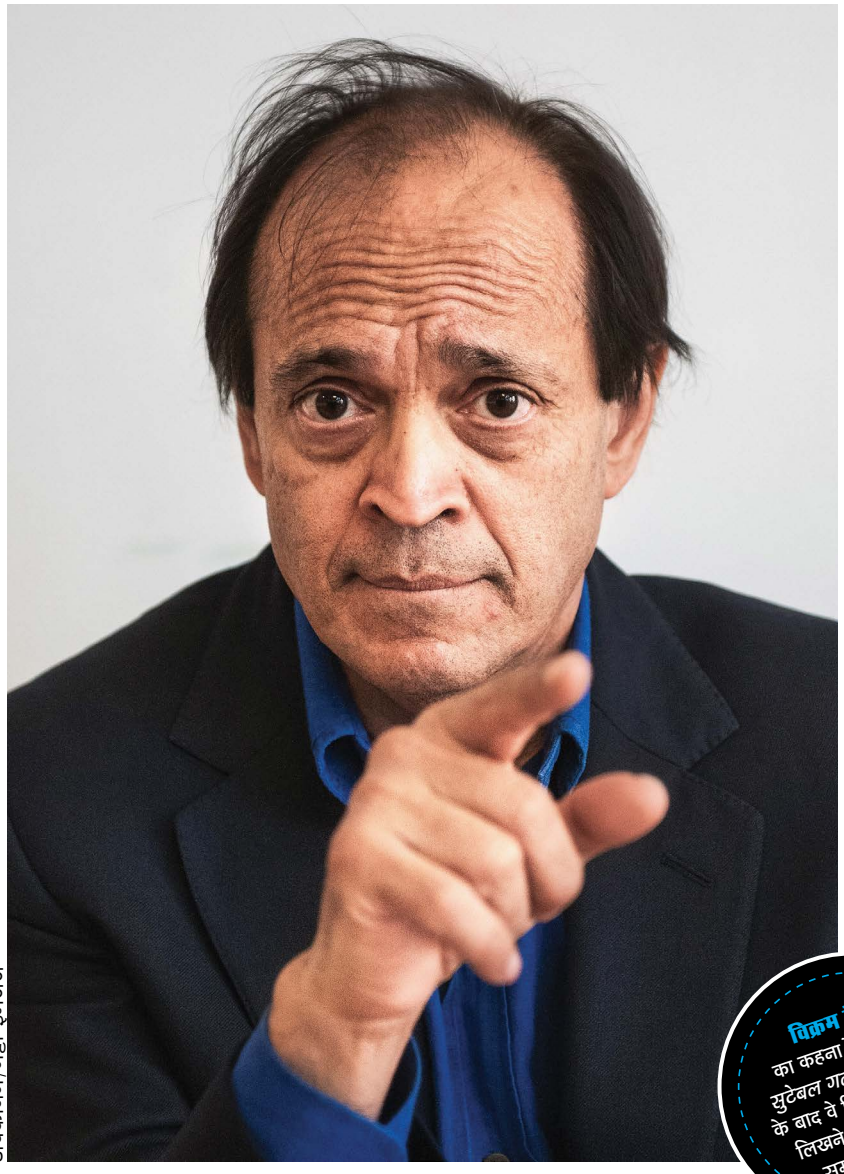

अवेकनिंग/गेट्टी इमेजेज

विक्रम सेठ का कहना है कि *अ सुटेबल गर्ल* पूरा करने के बाद वे सिर्फ कविताएं लिखने में ही अपना समय लगाएंगे

किताबें

छंदों में बुना जीवन

अ सुटेबल बॉय पर बीबीसी की ओर से तैयार सीरीज के चर्चाओं में रहने के बाद अब एक नए संग्रह की वजह से मशहूर लेखक **विक्रम सेठ** कवि के रूप में अपनी उपलब्धियों को लेकर खबरों में हैं. स्पीकिंग टाइगर से सात खंडों में छपे इस संग्रह में सेठ की विलक्षण प्रतिभा के व्यापक आयाम दिखते हैं. *इंडिया टुडे* से उनकी एक दुर्लभ बातचीत:

● पुश्किन के उपन्यास *यूजीन अनेगिन* का चार्ल्स जॉन्स्टन का अनुवाद हाथ लगने का किस्सा अक्सर आपके लेखकीय जीवन को दिशा देने वाला पल बताया जाता है. ऐसे और भी निर्णायक मोड़ रहे हैं?

ऐसे तो कई मौके आए. यहां एक का जिक्र करूंगा. यूनिवर्सिटी में दूसरे साल, जब मुझे फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ने थे, मैं ओरिएंटल इंस्टीट्यूट चला गया, यह सोचकर कि मैं नजरें बचाकर चुपचाप जापानी कक्षा में बैठ जाऊंगा. मैं बिल्डिंग की गलत मंजिल पर जा पहुंचा और चीनी भाषा की क्लास में घुस गया. हफ्ते-दो हफ्ते बाद मुझे घुसपैठिया कहकर निकाल दिया गया. पर इससे मुझे भाषा की समझ मिली. करीब इसी वक्त इत्तेफाकन एक दोस्त ने मुझे 8वीं सदी के चीनी कवि वांग वेइ की कविताओं के पेंगुइन क्लासिक्स अनुवाद पढ़ने को दिए. उन्होंने प्रकृति, दोस्ती और एकांत के बारे में जिस तरह लिखा, वैसा मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था. इन कविताओं ने मुझे गहरे तक झकझोर दिया और तभी मैंने उन्हें मूल रूप में पढ़ने के लिए पर्याप्त क्लासिकल चीनी सीखना तय किया. कई साल बाद, थ्येनआनमेन नरसंहार के अगले साल, अकाल और गृह युद्ध के उस मुश्किल वक्त के बारे में सोचते हुए जिससे वांग वेइ गुजरे थे, मैंने अपने लिए उनकी कविताओं का अनुवाद किया.

● आपने एकपदीय शब्दों में लिखी कविताओं के जो प्रयोग किए, वे चीनी कविता के आपके अनुवाद से प्रेरित हैं?

हां. अलग-अलग 'संकेताक्षरों' में एकपदीय क्लासिकल चीनी कविता लिखी गई है जो कानों को खास तरह की अनुभूति देती है. इसमें शब्द-ध्वनियों का प्रयोग है, जिनका अनुवाद नहीं हो सकता. छंदबद्धता भी है, जिनका अनुवाद संभव है. *सून* या *वॉक* या फिर *शेयर्ड ग्राउंड* जैसी मेरी ही कुछ कविताएं और *ऐन इक्वल म्युजिक* के कुछ गद्यांश भी पूरी तरह एकपद में रचे-बसे लगते हैं. पता नहीं क्यों. शायद सरलता की खातिर.

● *अ सुटेबल बॉय* की शायरी से परे आप अपने कानों पर हिंदी/हिंदुस्तानी के प्रभाव के बारे में बता सकते हैं?

कहानी में या चरित्रों के मन में जो चल रहा है, उसके मुताबिक *ए सुटेबल बॉय* में बहुत सारी हिंदी/ हिंदुस्तानी/उर्दू कविता है: नर्सरी राइम से लेकर लोकगीतों, पॉलिटिकल जिंगल, गजल, नज्म, मरसिया, गीता, शास्त्रीय संगीत की बंदिशों, गांधीजी की आश्रम रचनावली के भजनों और उस दौर के फिल्मी गीतों तक: भारत में पले-पढ़े होने के नाते आप इन सबसे

घिरे होते हैं! बेशक इसने मुझ पर गहरा असर डाला. बल्कि 'असर डाला' सही शब्द नहीं है—इसने मुझे गढ़ा और मुझे पता तक नहीं चला कि मुझे गढ़ा जा रहा था. शायद इसीलिए मैं इसके असर का वैसा विश्लेषण नहीं कर सकता, जैसी कोशिश मैंने चीनी कविता के साथ की.

हालांकि इसने साफ तौर पर मुझे प्रेरित किया. मसलन, कुछ साल पहले मैंने हनुमान चालीसा का उसके दोहों-चौपाइयों का उसी लय-ताल में अंग्रेजी में अनुवाद किया. मैंने बस एक बार 2014 में पटना लिटरेरी फेस्टिवल में इसका सस्वर पाठ किया जहां मैंने बारी-बारी से तुलसीदास की मूल रचना और अपना अनुवाद पढ़ा. पता नहीं मैं इसे कब छपवाऊंगा. छपवाऊंगा भी या नहीं. शायद मुझे करना चाहिए—आखिर मैंने खुद भी अनुवादों से लाभ लिया है. मुझे जैसा काम पसंद है, अगर यह उसकी फीकी अनुकृति भी है, तब भी यह उस पाठक को कुछ तो दे ही सकती है जिसकी मूल भाषा तक कोई गति नहीं.

कुछ तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं कविता से प्यार करता हूं. कुछ इसलिए कि मैं अपने चरित्र भास्कर और ब्रह्मपुर की स्थानीय रामलीला में वानर सेना में उसके बचपन के किरदार के बारे में सोच रहा था. कुछ इसलिए भी कि जो हिंदू प्रतीक, ग्रंथ, रीति-रिवाज और मान्यताएं मेरे जीवन का हिस्सा रहीं, उन्हें अब उन लोग हड़पे ले रहे हैं, जो इनका इस्तेमाल दूसरे भारतीयों को नीचा दिखाने या कुचलने के लिए करना चाहते हैं—देशभक्ति से इसका कोई वास्ता नहीं, यह अ-भारतीय, यहां तक कि अ-हिंदू है.

● *थ्री चाइनीज पोएट्स* की बात करें, तो राज्यसत्ता के साथ इनमें से हरेक के रिश्ते को आप आठवीं सदी के चीन के संदर्भ में उनकी पहचान का अभिन्न हिस्सा बताते हैं. 21वीं सदी के भारत में इस रिश्ते की व्याख्या किस तरह से करेंगे आप?

मनुष्य और नागरिक होने के नाते कवियों के लिए यह लाजिमी है कि उनके विचार उनकी कृतियों में झलकें. यह बात उन पर उपन्यासकारों से अधिक लागू होती है क्योंकि कवियों का झुकाव चरित्रों की नहीं बल्कि अपनी मनोदशा दिखाने की तरफ होता है. मगर कवि और राज्यसत्ता के रिश्ते के बारे में मैं सामान्यीकरण करना नहीं चाहूंगा. मैं नहीं समझता कि कवि दूसरे किसी भी व्यक्ति से ज्यादा 'दुनिया के मान्यताविहीन विधि निर्माता' हैं. राज्यसत्ता की उपलब्धियों और विनाशकारी कृत्यों के बारे में कब और कैसे बोलना है, बोलना भी है या नहीं, कई बातों पर निर्भर करता है.

आपने चूंकि जिक्र छेड़ा है तो अगर इन तीनों चीनी कवियों को देखें जिनका मैंने अनुवाद किया, हरेक ने इस मामले में अलहदा रास्ता अपनाया. वांग वेइ अंतर्मुखी और शांत थे और युवा उम्र में ही इंपीरियल सर्विस और दरबार से रिटायर हुए थे—हालांकि उनके भाई बाद में प्रधानमंत्री बने. ठाठदार ली बइ ने राज्यसत्ता की या अपने चारों तरफ घट रही दुनिया की कारगुजारियों की मुश्किल से ही परवाह की, जब तक कि ढेर सारी मदिरा और स्याही और पानी—अच्छा हो कि उसमें नशे में धुत्त पूर्णिमा का चांद भी हो—उन्हें मिलता रहे. डु फु को राज्यसत्ता की सेवा के बारे में गहरी परवाह थी और उन्होंने कई बार इंपीरियल सिविल सेवा की परीक्षा पास करने की नाकाम कोशिश की. उनकी बहुत सारी कविता उस कशमकश में फंसी है, जो आजीवन साम्राज्य के प्रति उनकी निष्ठा और हिंसा, सेना में जबरन भर्ती, परिवारों के बिछोह और अकाल की उस आफत में अपने चारों तरफ लोगों की भीषण तकलीफ के बीच उनके मन में चल रही थी.

● आपकी बहुत सारी कविता प्राकृतिक इमेजरी से निकली है. दिल्ली सरीखे शहर में रहकर (उस किस्म के मंडराते जलवायु विनाश के तले जिसकी तरफ आपने अपनी कृतियों में इशारा किया है) इस स्रोत को आप बार-बार कैसे भरते हैं?

जहां तक संभव हो, मैं बगीचों में खूब टहलता हूं. यह मुझे फिर से भर देता है. या फिर यमुना किनारे हमारे स्थानीय पक्षी अभयारण्य में. 'अभयारण्य'—इस शब्द में ही निहित है कि हम इनसानों ने हर चीज को (खुद को भी) खतरे में डाल दिया है.

सबसे ज्यादा मुझे पेड़ों से प्यार है, जो अपनी हरियाली में इतने उदार हैं. और पक्षियों, डायनोसोर के वंशजों से.

● *फ्रॉम हैवन लेक* के बाद आपने कोई और यात्रावृत्तांत लिखने पर विचार किया?

हां, पर मैं लिखूंगा नहीं. इतना कम वक्त बचा है और बचा हुआ वक्त (*अ सुटेबल गर्ल* खत्म करने के बाद) मैं कविता को देना चाहूंगा.

● आपने अप्रत्याशित कामों, मसलन मूर्ति बनाने, में भटक जाने की बात कही है. आपने पिछली बार किसी नई और मनमोहक चीज में खुद को कब मसरूफ पाया?

मूर्तिकला ही मानिए—मिट्टी पर आप ऊपर से लगा-लगाकर जोड़ते हैं; पत्थर और लकड़ी को तराशते-काटते हैं और प्लास्टर के साथ दोनों ही कर सकते हैं. फिर कांच या कांसे या जस्ते के साथ सांचे के जरिए भी मूर्तिकला है.

यह चिंतन-मनन और मर्मस्पर्शी सृजन का अंतहीन संसार है. ऐसा संसार जहां पेंटिंग के रंगों और दो आयामों के विपरीत, हम एक रंगारंग विरलता, मगर तीन आयामों के इलाके में होते हैं (इसमें चारों तरफ घूमने या इसे नीचे या ऊपर से देखने की भी गर्भित क्षमता के साथ). बीते कुछ सालों में इतना गहरा बदलाव मेरे भावबोध में नहीं आया. मगर मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे आखिरी एक या दो दशक में कुछ हो.

● *द गोल्डन गेट* में 'मेरे यौवन का सूरजमुखी कुम्हला रहा है' से लेकर *समर रेक्वियम* में तिल-तिल क्षरण देखते हुए भी निर्लिप्त और उदासीन रहने के बार-बार लौटते विचार तक क्या आपको लगता है कि नश्वरता पर मनन के लिए कविता अनूठे ढंग से उपयुक्त है?

मेरे विचारों में नश्वरता हमेशा थोड़ी-बहुत रही है. आखिर कोख में आने के क्षण से ही हम तेजी से मौत की तरफ बढ़ रहे हैं.

हां. मैंने नश्वरता के बारे में अपने विचार आम तौर पर कविता के माध्यम से व्यक्त किए हैं, हालांकि *अ सुटेबल बॉय* में मिसेज महेश कपूर की मौत शायद दूसरी विधा का उदाहरण हो सकती थी.

पिछले महीने 97 की उम्र में मेरे पिता का देहांत हुआ. हालांकि उनकी मृत्यु घर पर, संपूर्ण जीवन जीकर हुई. मेरी बहन आराधना और मैं भी उनके साथ थे, पर इसने मेरे भीतर अजीब-सा खालीपन छोड़ दिया. उनके साथ एक ड्रिंक और गपशप के लिए जाने की बात हर शाम मेरे ख्यालों में लौट आती है. लेकिन अब बातचीत (सपनों के अलावा) एकतरफा हो गई है.

अब जब मुझे एहसास होता है कि मेरी अपनी जिंदगी का करीब पांचवां हिस्सा (अगर मैं खुशकिस्मत हुआ) ही बचा है, यह देखना दिलचस्प होगा कि मैं मौत के बारे में कम सोचता हूं या ज्यादा.

जो भी हो, मैं उम्मीद करता हूं कि अपने सहस्त्र-चंद्र-दर्शन—अपने हजारवें पूनम के चांद को देखने—के लिए यहां होऊंगा. यह 2033 में हनुमान जयंती, गुड फ्राइडे को पड़ेगा और यह—संयोग से—मेरे बौद्ध बंधु शांतम का जन्म दिन है.

—सोनल शाह

फुरसत

सवाल + जवाब

दिखता है बस दरवाजा

प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कहीं न जा पाने की बेचैनी, उत्तर प्रदेश में गुरुकुल खोलने की इच्छा और उम्र के सवालों पर

●क्या अब जब कोरोना संकट कम होता दिख रहा है, संगीत समारोहों की आपकी व्यस्तता फिर शुरू हो सकी है?

जब कोई गिर पड़ता है तो उठने में समय लगता है और फिर उठने के बाद लड़खड़ाता है चलने में. संगीत समारोह अभी धीरे-धीरे शुरू हो रहे हैं. उम्मीद है जल्दी ही पहले की तरह होने लगेंगे.

●कोरोना के एकांत के समय को आप किस प्रकार व्यतीत करते थे?

पिछले साल मार्च महीने से, जब से कोरोना संकट शुरू हुआ है, मैं मुंबई से बाहर ही नहीं निकला हूं. बस बाहर जो दरवाजा है, वही दिखाई देता है कि कब मैं इससे निकल पाऊंगा. यहां मेरा वृंदावन गुरुकुल है, परिवार की तरह सभी शिष्य-शिष्याएं रहते हैं. मैंने अपना पूरा समय यहीं बिताया. सभी साथ में थे तो उस दौरान भी गाना-बजाना सब चलता रहा. लेकिन मेरा जो दूसरा गुरुकुल भुवनेश्वर में है, उसे मैंने इस दौरान बहुत याद किया. वहां नहीं जा सका. नवंबर में वहां जाने की योजना बनाई है.

●गुरुकुल की बात चली है तो याद आता है कि कभी आपने कहा था, उत्तर प्रदेश में गुरुकुल बनाने की आपकी इच्छा है. प्रयागराज में आपका जन्म हुआ और इस प्रदेश से आपका गहरा लगाव भी है

जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे आश्वासन दिया था. अभी भी सरकार अगर मुझे गुरुकुल बनाकर दे तो मैं वहां आकर सिखा सकता हूं. जब मुझे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया तब भी मैं जाया करता ही था.

●अब क्या करना बाकी रह गया है?

कुछ भी नहीं, सब कर लिया है. भारतीय संगीत का प्रचार-प्रसार देश-विदेश में कर लिया. सभी जगह कार्यक्रम किए. अब तो जिस तरह का संकट पूरी दुनिया में आया, उसमें खुद को बचा लेना ही बहुत है.

–आलोक पराड़कर

अखिल नारायण शर्मा